एक नेता का मुख्य काम ऐसा वातावरण बनाना है, जहां दूसरे लोग महान कार्य कर सकें। -रिचर्ड टीरलिक

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए हाइब्रिड मॉडल को सशर्त स्वीकार करने के पाकिस्तान के निर्णय के पीछे उसकी आर्थिक मजबूरी बड़ी वजह है। राजनीति, कूटनीति और खेल में शक्ति संतुलन जैसे जटिल पहलुओं को देखते हुए इसे बीसीसीआई की एक बड़ी जीत के रूप में भी देखा जा सकता है।

क्रिकेट और कूटनीति

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) का 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए हाइब्रिड मॉडल को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करने का निर्णय उसके पहले के रुख में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसके पीछे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की एक बड़ी कूटनीतिक जीत को भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में राजनीति, कूटनीति और खेल में शक्ति संतुलन जैसे जटिल पहलू भी निहित हैं। उल्लेखनीय है कि हाइब्रिड व्यवस्था के तहत, सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ मैच पाकिस्तान में और कुछ अन्य तटस्थ स्थलों पर खेले जाएंगे। यह सही है कि खेल में राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटीय रिश्ते दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों से निर्धारित होते रहे हैं, जो हाल के वर्षों में पाकिस्तान की हरकतों की वजह से काफी कमजोर हुए हैं। लिहाजा भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर राजनीतिक चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा संबंधी कारणों से अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता, तो यह तर्कसंगत भी है। आईसीसी द्वारा भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान को एक सौहार्दपूर्ण और तार्किक समाधान के लिए राजी किए जाने से विश्व क्रिकेट में भारत के बढ़ते दबदबे की ही झलक मिलती है। हालांकि पीसीबी ने आईसीसी से इस मॉडल को 2031 तक भारत में आयोजित होने वाले आयोजनों में भी लागू करने और कुछ राजस्व बढ़ाने का आग्रह किया है। लेकिन यह भी सच है कि विश्व क्रिकेट में भारत के कद को देखते हुए अगर पाकिस्तान बोर्ड अपनी जिद पर अड़ता, तो शायद उसे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से ही हाथ धोना पड़ता, जो पहले से ही समस्याओं से जूझ रहे मुल्क के लिए कमर तोड़ने जैसा होता। आईएमएफ के कर्ज में बुरी तरह से डूबे पाकिस्तान के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक सहारा हो सकती है। गौरतलब है कि इंग्लैंड में 2017 में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के

टिकटों की बिक्री मात्र से करीब नब्बे लाख डॉलर की कमाई हुई थी। इसके अलावा, प्रसारण अधिकार, कॉरपोरेट विज्ञापन और ब्रांडिंग से होने वाली कमाई को मिलाकर यह राशि अरबों डॉलर में पहुंच जाती है। दुनिया भर से प्रशंसकों और मीडिया के विज्ञापन आने से होने वाले विदेशी मुद्रा प्रवाह से भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कई तरह की अस्थायी और स्थायी नौकरियां पैदा होंगी, सो अलग। पीसीबी की सहमति से चुना गया भारत के क्रिकेट प्रशंसकों की उम्मीदें बंधी हैं, जो दोनों देशों के ज्यादा से ज्यादा मैच देखना चाहते हैं। इससे यह साबित भी होता है कि राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बगैर भी ऐसे समाधान खोजे जा सकते हैं, जिनमें जीत अंततः क्रिकेट की ही हो।

इस्कॉन संत की गिरफ्तारी तो बहाना है

इस्कॉन संत ने मुल्क के हिंदुओं को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार को पता था कि संत की गिरफ्तारी से नाराज हिंदू प्रदर्शन करेंगे और छात्र समूहों के मुखौटे के पीछे छिपे कट्टरपंथी उनका विरोध करेंगे। इससे सरकार को महंगाई और अव्यवस्था से लोगों का ध्यान भटकाने में मदद मिलेगी।

नोबेलजयी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वही कार्ड खेला है, जो मुल्क के अलोकप्रिय नेता अतीत में भी खेलते रहे हैं, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्ड। इस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जमानत देने से भी इन्कार कर दिया गया। दरअसल, यह सब वहां रहने वाले हिंदुओं को भड़काने के लिए किया गया, जो शेख हसीना सरकार के हटने के बाद से ही बढ़ते अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। इस तरह का अत्याचार बांग्लादेश में पहले भी हुआ है, लेकिन हिंदुओं ने कभी इस तरह का व्यापक प्रदर्शन नहीं किया, जैसा कि इस बार अगस्त से वे कर रहे हैं।

सुधीर भौमिक
वरिष्ठ पत्रकार

इस्कॉन संत ने मुल्क के हिंदुओं को संगठित एवं एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए यूनुस की मंडली को पता था कि संत चिन्मय की गिरफ्तारी से नाराज हिंदू जमकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। एक ऐसे मुल्क में, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और कुल आबादी में जिनकी 93 फीसदी की हिस्सेदारी है, वहां हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ प्रतिक्रिया होने की पूरी आशंका है, क्योंकि इस समय छात्र-युवा समूहों के मुखौटे के पीछे इस्लामी कट्टरपंथियों का बोलबाला है। इसलिए जब सरकार जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने या कानून-व्यवस्था में गिरावट को नियंत्रित करने में असमर्थ हो, तो अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने से बेहतर उपाय और क्या हो सकता है!

इस्कॉन संत की गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन और चटगांव में एक मुस्लिम वकील की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या ने यूनुस सरकार के तात्कालिक उद्देश्यों को पूरा कर दिया। अचानक पूरे मुल्क का ध्यान हिंदू विरोध प्रदर्शनों पर चला गया और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणियों ने लोगों का ध्यान अर्थव्यवस्था पर से हटा दिया, जो निरंतर चरमरा रही है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए

अदालती याचिकाएं और चिन्मय प्रभु पर मुकदमा चलाने की सरकार की योजनाएं अन्य खबरों को सुर्खियों से दूर रखने में मदद करेंगी।

सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ने के साथ ही मुल्क में पहले से कम होती धर्मनिरपेक्ष राजनीति और बंगाली राष्ट्रवादी ताकतों को हाशिये पर धकेल देगी और इस तरह इस्लामी पार्टियों को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। इन पार्टियों ने पहले ही यूनुस सरकार को मुल्क के भाषायी-धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को कम करके मुक्ति संग्राम की विरासत को कमजोर करने के लिए प्रेरित किया है। मुक्ति संग्राम संग्रहालय में भी तोड़फोड़ के साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया है।

यूनुस को घेरने और पश्चिम को नियंत्रित करने के लिए उनका इस्तेमाल करने वाले इन कट्टरपंथी तत्वों ने भारतीय नाराजगी का भी हिसाब लगाया। वे जानते हैं कि चिन्मय की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत की सत्तारूढ़ सरकार तीखी प्रतिक्रिया करेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा चिन्मय की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद यूनुस सरकार ने इसलिए भी की थी, क्योंकि मोदी सरकार वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के उत्पीड़न के मुद्दे को यूनुस प्रशासन के समक्ष जोरदार तरीके से उठाती रही है। विदेश मंत्रालय के बयान पर यूनुस सरकार की ओर से की गई कड़ी प्रतिक्रिया भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए एक सुनियोजित प्रयास की ओर इशारा करती है।

ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि भारत शेख हसीना और उनके कई करीबी सहयोगियों को शरण दे रहा है, जिनमें कुछ पूर्व मंत्री और अवामी लीग पार्टी के नेता शामिल हैं। जब यूनुस या उनकी मंडली में कोई भी अल्पसंख्यक विरोध प्रदर्शनों का उपयोग करके 'निहित स्वार्थों' की बात करता है, तो उनका स्पष्ट मतलब अवामी लीग से होता है। पिछले तीन महीनों में, अवामी लीग को क्रूर प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और कम विश्वसनीय आरोपों पर ढेरों मामलों के बावजूद कुछ वरिष्ठ नेताओं ने जमीनी स्तर पर समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश की, जिसे हसीना सरकार के खिलाफ जन-आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र-युवा समूहों द्वारा क्रूरता पूर्वक विफल कर दिया गया।

इन समूहों को इस्लामी दलों और उनके कट्टरपंथी कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। पुलिस अक्सर मूक दर्शक बनकर खड़ी रही है। सेना ने भी ज्यादातर मौकों पर ऐसा ही किया है। यूनुस और उनके साथियों को संदेह है कि अवामी लीग के कार्यकर्ता अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मुद्दे पर उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए हिंदुओं की रैलियों में शामिल हो सकते हैं। जब इसे अंतरिम प्रशासन द्वारा इस्लामी कट्टरपंथियों को विशेष सहायता देने के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसमें अंदरुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी जैसे दोषी आतंकवादियों की रिहाई शामिल है, तो यूनुस शासन का असली चेहरा सामने आ जाता है।

यूनुस भारतीय प्रतिक्रिया को भले ही निराधार बताकर खारिज कर दें, लेकिन जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर बोलते हैं, तो यूनुस को उन्हें गंभीरता से लेना ही पड़ता है, क्योंकि उनका शासन, केवल पश्चिमी, विशेषकर अमेरिकी समर्थन से ही जीवित रह सकता है।

असल में यूनुस सरकार ब्रिटिश सर्वदलीय संसदीय मंच की एक रिपोर्ट से परेशान है, जिसमें नई अंतरिम सरकार की 'प्रभावकारिता पर सवाल' उठाए गए हैं। उक्त रिपोर्ट में कहा गया है, 'कानून को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संस्कृति को समाप्त करने और मानवाधिकारों व कानून के शासन को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसमें विफलता मोहम्मद यूनुस के नए अंतरिम शासन पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी।' साथ ही यह भी कहा गया है कि 'हमें सबूत मिले हैं कि अवामी लीग के पूर्व मंत्रियों पर हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं।'

जाहिर है कि, अगर यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और लोकतंत्र की बहाली के मुद्दे से निपटने में विफल रहती है, तो संदेह का घेरा उस पर और कसेगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

स्टीव जॉब्स

आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपने अंतर्ज्ञान, भाग्य, जीवन, कर्म, या जो भी हो, क्योंकि यह आपको अपने दिल की बात मानने का आत्मविश्वास देगा। और यही सब कुछ बदल देगा।

अंतर्मन से लिया गया फैसला जीवन बदल देता है

यह मेरे जीवन की शुरुआत थी। मैं 17 साल बाद कॉलेज गया था। लेकिन मैंने नासमझी में एक ऐसा कॉलेज चुन लिया, जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था। यहां मेरे माता-पिता की सारी कमाई और बचत कॉलेज की ट्यूशन फीस पर ही खर्च हो जा रही थी। छह महीने बाद मुझे इसमें कोई सार नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं। मुझे यह भी नहीं पता था कि कॉलेज मुझे यह समझने में कैसे मदद करेगा। कॉलेज का भारी-भरकम खर्च और माता-पिता पर आर्थिक बोझ को देखते हुए आखिरकार मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर मुझे इसका पक्का भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा।

हालांकि उस समय यह सब बहुत डरावना भी लग रहा था। पर आज मैं जब पीछे मुड़ कर देखता हूं, तो पाता हूं कि यह फैसला मेरे द्वारा लिए गए अब तक के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जिस क्षण मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैंने उन्हीं कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया, जिनमें मुझे दिलचस्पी थी।

मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर ही सो जाता था। कोक की बोतलें लौटा कर पांच सेंट जमा करता था, ताकि उससे खाना खरीद सकूं। अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करके मैंने जो कुछ भी पाया, वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा दी जाती थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और सामान्य कक्षाओं से मेरा पिंड छूट गया था। इसलिए मैंने सुलेख कक्षा में जाने का फैसला किया। वहां मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा। इसी से यह जाना कि किस तरह से टाइपोग्राफी बेहतरीन बनती है। यह सब मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यह खूबसूरत, ऐतिहासिक और कलात्मक रूप से सूक्ष्म था, जिसे विज्ञान नहीं पकड़ सकता। यह सब सीखते हुए मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि आज जो मैं कर रहा हूं, वह जीवन में मेरे कभी काम भी आएगा या नहीं। बस अच्छा लगा, इसलिए सीख लिया।

लेकिन 10 साल बाद, जब हम पहला मैकिनटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो यह सब मुझे याद आया और हमने इसे मैक में डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला यह पहला कंप्यूटर था। आज मैं सोचता हूं कि अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती, तो कभी उस सुलेख कक्षा में नहीं जाता और कंप्यूटरों में वह अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती, जो आज उनमें है। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि आपके भविष्य में बिंदु किसी न किसी तरह से जुड़ते ही जाएंगे। आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपने अंतर्ज्ञान, भाग्य, जीवन, कर्म, या जो भी हो, क्योंकि यह विश्वास करना कि आगे चल कर ये सभी बिंदु आपस में जुड़ जाएंगे, जो आपको अपने दिल की बात मानने का आत्मविश्वास देंगे, तब भी, जब वह आपको परखे हुए रास्ते से भटका दें। और यही सब कुछ बदल देगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि आप आगे देख कर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे देख कर ही जोड़ सकते हैं।

खुद से संवाद करें

सूत्र

हमेशा खुद पर भरोसा रखें। बाहर जाकर किसी सफल व्यक्तित्व की तलाश न करें और न ही उसकी नकल करने की कोशिश करें। अपने आपसे ऐसे बात करें, जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं। हमेशा याद रखें, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी।

दूसरा पहलू

ग्वालियर किले की तलहटी में बने मंदिर में संस्कृत और पाली मिश्रित भक्षाली लिपि में दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल होता था।

शून्य का दर्शन, भक्षाली लिपि और...चतुर्भुज मंदिर

विशाल किले की तलहटी में बने सूने और अनजान से मंदिर से कितनी सदियों का नाता रहा होगा, यह सोचना भी अजीब लगता है! ग्वालियर आने वाले लोग जब मान सिंह तोमर के किले को देखते हैं, तो शायद गूंदावन लाल वर्मा की *मृगनयनी* बरबस ही उन्हें याद आ जाती होगी। यह आज दुनिया का अकेला मंदिर है, जिसमें दुनिया भर के इतिहासकारों, दार्शनिकों और गणितज्ञों की समान रुचि है। मंदिर के अंदर विष्णु की प्रतिमा के ऊपर लगे शिलापट पर भक्षाली लिपि में आपको जीरो बड़ी सहजता से लिखा दिख जाएगा।

भूपेंद्र कुमार

जब यह मंदिर बना, उस समय तक जीरो का उपयोग भारत में बहुतायत में होने लगा था और भारत के ज्ञान का डंका भी पूरी दुनिया में बजने लगा था।

दुनिया का सबसे पुराना दूसरा शून्य आपको ग्वालियर में मिलेगा। मंदिर के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कि इसे प्रतिहार राजा भोजदेव ने 876 ईस्वी में बनवाया था। मंदिर के चार स्तंभों पर योग के आसन दिखते हैं, मंदिर के गर्भगृह से एक तरफ गंगा, तो दूसरी तरफ यमुना दर्शाई गई हैं। विष्णु की चार भुजाओं से ही मंदिर का नाम चतुर्भुज पड़ा। दुनिया भर में काफी समय तक किसी भी शिला पट पर अंकित शून्य इसी मंदिर में पहली बार देखा गया। पर 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में फ्रेंच पुरातत्ववेत्ता जार्ज कोदेस ने 683 ईस्वी में कंबोडिया के सामबोर में एक ऐसा मंदिर खोज निकाला, जिसमें शिला पर शून्य अंकित था। इससे 193 साल के अंतर से चतुर्भुज मंदिर पीछे हो गया। खमर शासन के दौरान यह शिलापट कंबोडिया नेशनल म्यूजियम से गायब हो गया। इससे ग्वालियर को फिर पहले वाला दर्जा मिल गया।

लेकिन जनवरी, 2017 में कंबोडिया की सरकार ने घोषणा की कि गायब शिलापट मिल गया है। किसी और माध्यम में जीरो का सबसे पहला इस्तेमाल पंजाब के यूसुफजई जिले में 1881 में भोजपत्र पर भक्षाली भाषा में मिला था। संस्कृत और पाली मिश्रित इस लिपि को भक्षाली कहा गया। इसमें दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल दर्शाया गया है। चीन और सुमेरियन सभ्यता में शून्यता की स्थिति को समझाया तो गया है, पर इसे दिखाया कैसे जाए-यह भारत ने ही दुनिया को बताया।

876 ईस्वी में जब यह मंदिर बना, उस समय तक जीरो का उपयोग भारत में बहुतायत में होने लगा था। इससे दो शताब्दी पहले ब्रह्मगुप्त ने अंकगणित के नियम बनाए। इसी के साथ गणित में दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी हो गई थी। यह प्रणाली अरब गई, तो अल ख्वारिज्मी जैसे गणितज्ञों ने इसे यूरोप तक लोकप्रिय बना दिया। और भारत के ज्ञान का डंका भी पूरी दुनिया में बजने लगा।

आंकड़े

जनसंख्या घनत्व

भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश है, पर जनसंख्या घनत्व के मामले में यह बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर है।

अमेरिका	38
पाकिस्तान	326
श्रीलंका	368
भारत	488
बांग्लादेश	1,333

आंकड़े प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या के हैं। | स्रोत: UN2024

राजा मानसिंह मोहरों की थैलियां कुंभनदास जी को भेंट देने के लिए लाए, लेकिन कुंभनदास ने जो कहा, उसे सुन मानसिंह का रोम-रोम पुलकित हो उठा।

भगवान को समर्पित

कुंभनदास जी गोवर्धन के निकट यमुनावत गांव में रहते थे। उन दिनों यमुना जी का प्रवाह इस गांव के निकट था। उनका खेत पारसोली चंद्रसरोवर के ऊपर था और वहीं कुंभनदास जी खेती किया करते थे। लेकिन वह धन, मान और मर्यादा की इच्छाओं से कोसों दूर थे।

एक बार जयपुर के राजा मानसिंह कुंभनदास जी के दर्शन के लिए आए। मोहरों की थैलियां उनके चरणों में रखकर स्वीकार करने की प्रार्थना की, साथ ही कई गांव भी भेंट में देने लगे। संत कुंभनदास जी बोले, 'भाई! यह सब लेकर मैं क्या करूंगा? हमारे पास खेती है, उसमें पर्याप्त अन्न हो जाता है, यदि तुमको देना ही है, तो किसी गरीब को दे दो। यह सुन मानसिंह का रोम-रोम पुलकित हो उठा। वह बोले, भगवान को समर्पित यह जीवन धन्य है। कुछ वर्ष बाद अकबर का एक दरबारी श्रीनाथजी के मंदिर में कुंभनदास जी का एक पद सुना और उसे राज-दरबार में गाकर सुनाया। पद सुनकर अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि वह पद कुंभनदास का है, तो उसने दरबार में लाने के लिए पालकी भेज दी।

अंतर्यात्रा
संकलित

श्रीनाथन जी की सेवा त्याग कर वह जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बादशाह ने बुलाया, तो चले गए और दरबार में अपनी खिन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने पद गाकर सुनाया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में ही समर्पित कर दिया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 07 जुलाई, 1962

अल्जीरिया में दोहरा शासन तंत्र : सेना में भी मतभेद

अल्जीरिया में दोहरा शासन तन्त्र : सेना में भी मतभेद
अंग की दूरदर्शिता चाल सफल

नव स्वतंत्र अल्जीरिया के राष्ट्रीय नेताओं में मतभेद इस बात पर है कि फ्रांस से सहयोग करने की नीति पर चला जाए अथवा अरब राष्ट्रवाद की नीति पर। सेना में भी मतभेद है कि संचालन का असली नेता कौन है।

बच्चों की निजता की कीमत पर

सोशल मीडिया पर बच्चों के चित्रों व वीडियो को माता-पिता द्वारा शेयर करने की बाढ़-सी आ गई है, जो बड़े होने पर बच्चों को असहज करते हैं।

क्षमा शर्मा — मुद्दा

इन दिनों सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बच्चों के तरह-तरह के चित्र नजर आते हैं। हंसते-गाते, रोते, खेलते, खाते-पीते, शैतानी करते, सजे-संवरे हर तरह के चित्र और वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब आदि तमाम प्लेटफार्म पर देखे जा सकते हैं। ये चित्र अक्सर माता-पिता द्वारा शेयर किए जाते हैं। दुनिया भर से हर रोज ऐसे लाखों चित्र और वीडियो शेयर किए जाते हैं। इसे शेअरींटेंग का नाम दिया गया है। यह शब्द शेयर और पेरेंटिंग को मिलाकर गढ़ा गया है।

जब से सोशल मीडिया आया है, तब से ऐसे चित्रों, वीडियो की बाढ़-सी आ गई है। इन्हें शेयर करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, भारत समेत बहुत से एशियाई देश शामिल हैं। इन्हें शेयर करने वाले बहुत से माता-पिता खूब पैसे भी कमा रहे हैं। लाइक्स और व्यूज के आधार पर उन्हें विज्ञापन भी मिलते हैं। तमाम बड़े ब्रांड्स की नजर इन पर रहती

है और वे लोकप्रिय वीडियो आदि को देखकर बच्चों और माता-पिता से जुड़े उत्पादों के लिए एक तरह से बड़ा बाजार पा जाते हैं। लोग बच्चों के बारे में ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। इसलिए यह एक बहुत सफल व्यवसाय भी बन चुका है।

लेकिन बहुत से वे बच्चे, जो अब बड़े हो गए हैं, इस तरह की चीजों का विरोध कर रहे हैं। पश्चिम में ये लोग अपनी आवाज उठाकर कह रहे हैं कि बच्चों के साथ माता-पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनसे जुड़ी छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जाती है और उनकी निजता तथा अधिकारों का हनन होता है। जब तक ये बच्चे किशोर होते हैं, तब तक उनके हजारों फोटो और वीडियो देखे जा चुके होते हैं। बच्चों के लाखों फालोअर्स होते हैं। वे बच्चों के बारे में ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं।

बच्चों की खुशी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए फोटो, वीडियो शेयर करने से बचना चाहिए। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता कि बच्चों की निजता भंग की जाए। तीन-तीन साल के बच्चों को बंदूक चलाते दिखाया जा रहा है। कई बार तो ऐसे फोटो और वीडियो गर्भावस्था के शुरू होते ही शेयर किए जाने लगते हैं। बच्चा कैसे पैदा हुआ, कैसे रोया, कब दूध पिया, कब नहाया, कब सोया आदि छोटी-छोटी बातें तक बताई जा रही हैं। बच्चों के जरिये माता-पिता अपने लिए भी प्रसिद्धि और अटेंशन चाहते हैं। अपनी इच्छाओं को नन्हे बच्चों पर इस तरह से थोप दिया गया है कि उनका पल-पल दूसरों की नजरों में है।

सोशल मीडिया पर बच्चों को इस तरह दिखाना बहुत से देशों में बाल श्रम के अंतर्गत अपराध माना जाता है। बाल श्रम गैर कानूनी है। इसलिए सरकारें नियम बना रही हैं कि अगर बच्चों का इस्तेमाल इस तरह से किया गया, तो ऐसा करने वालों को सजा मिलेगी। एक माता-पिता से तो इस अपराध में उनके बच्चे भी छीन लिए गए। कई माताएं भी इस तरह की बातों के खिलाफ हैं। एक मां ने कहा कि वह अपने बच्चों को नुमाइश की चीज नहीं बनाना चाहती। बच्चों की कीमत पर माता-पिता बड़े-बड़े घर बना रहे हैं। बहुत-सी महंगी चीजें खरीद रहे हैं। दुनिया के लाखों बच्चे करोड़ों लोगों की नजर में हैं।

शेअरींटेंग के खिलाफ अभियानों को समर्थन भी मिल रहा है। एक लड़की ने कहा कि कल अगर मैं किसी नौकरी पर जाऊं, तो नियोक्ताओं को मेरे बारे में सब कुछ मालूम होगा। सिर्फ नियोक्ताओं को ही नहीं, दुनिया में बहुत से लोगों को मालूम है। अनजान लोग हमें घूरते हैं, पीछा करते हैं। जब मैं नौ साल की थी, तो मेरे पीरियड्स शुरू हो गए। माता-पिता ने यह सूचना भी शेयर कर दी। और मात्र नौ साल की उम्र में लोग कहने लगे कि औरत बनने के लिए बधाई। यह एक तरह से मेरे बचपन को छीनना था। एक लड़की को तंग करना था।

अपने यहां भी टॉक अबाउट पीरियड्स जैसे अभियान के तहत बच्चियों के बारे में इस तरह की बातें शेयर की जा रही हैं कि कब उनके पीरियड शुरू हुए। उनके खून से सने कपड़े तक सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। तमाम जांच एजेंसियां कहती हैं कि किसी अपरिचित से बच्चों के डिटेल्स शेयर न करें। उनके फोटो न दें। मगर सोशल मीडिया के जरिये तो करोड़ों लोग इन बच्चों की हर हरकत को देख रहे हैं। बहुत से विशेषज्ञों के अनुसार, माता-पिता का ऐसा करना बच्चों के साथ उनके रिश्तों को प्रभावित करता है, उनकी सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही।

विभिन्न देशों में शेअरींटेंग पर शोध हो रहे हैं। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी अध्ययन हो रहा है। अमेरिका में इस तरह के कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है, जो बच्चों को सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स से बचा सकें।

सम्पादकीय

महिलाएं जीत की गारंटी बनीं

क्या आपको लगता है कि हमारे राजनेता जन-कल्याण में पर्याप्त ध्यान नहीं लगाते? वे चुनाव के समय सामाजिक दरारों को चौड़ा कर वोट जुटाते हैं और फिर उस वोट बैंक को बिसरा देते हैं? एक लोकप्रिय शोशा यह भी है कि राजनीति जन समस्याओं के समाधान के बजाय सिर्फ सत्ता प्राप्ति का जरिया बन चुकी है?

इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको पिछले साल, यानी 2023 में वापस ले चलना चाहता हूं। उन दिनों मध्य प्रदेश में सत्ता-विरोधी लहर आसमान छू रही थी। उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अचानक 'लाडली बहना योजना' की शुरुआत की और सारी 'एंटी इनकंबेंसी' हवा हो गई। वह तीसरी बार चुन लिए गए। यह बात अलग है कि भाजपा ने उनकी जगह भोपाल में नए नेतृत्व को मौका देना बेहतर समझा। इसके पहले हुए हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों में भी कांग्रेस सिर्फ इसलिए वापसी कर सकी, क्योंकि उसने महिलाओं के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं का वायदा किया था।

चुनावी लड़ाइयों में अमोघ अस्त्र बन चुकी इन योजनाओं को वर्ष 2001 के तमिलनाडु चुनावों में जयललिता जयराम ने शुरू किया था। महिलाओं पर चले गए इस दांव से चेन्नई के सत्ता-सदन में उनकी जबरदस्त वापसी हुई थी। उनके बाद नीतीश कुमार ने इस जादुई मंत्र को आत्मसात किया। साल 2006 में उनकी सरकार ने फैसला किया कि कक्षा नौ में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। बिहार को जानने वाले जानते हैं कि वहां बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कमी है। छोटी बच्चियों को प्राइमरी स्कूल के बाद आस-पास के गांवों में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जाना पड़ता है। अक्सर उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, क्योंकि घर में किसी सदस्य के पास प्रतिदिन उन्हें दूसरे गांव ले जाने और लाने की फुरसत नहीं होती थी। इस पुराने सिलसिले ने महिलाओं को पीछे धकेल दिया था। सरकार से मिली साइकिल ने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। मैंने खुद बिहार की सड़कों पर दर्जनों बच्चियों को खिलखिलाते हुए साइकिल पर स्कूल आते-जाते देखा है। वे पढ़ रही थीं, खुली हवा में सांस ले रही थीं और अपने अंदर इस विश्वास को संजो रही थीं कि वे एक नए बिहार की संरचना करेंगी। साइकिल योजना के लागू होने से पहले और बाद के बिहार में यदि सरकारी कार्यालयों में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात, शिक्षा दर और अन्य सामाजिक पैमानों पर आपत्तिरयों की भागीदारी आंकें, तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सन् 2010 के चुनाव में बिहारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। चुनाव आयोग के आंकड़े गवाह हैं कि 51.12 प्रतिशत पुरुषों ने और 54.49 फीसदी महिलाओं ने वोट डाले। बिहार के सामाजिक समीकरण ऐसे हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता की सीढ़ी बिछाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या अपने पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव की पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। नीतीश कुमार अकेले सत्ता हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उनके बिना ये दोनों पार्टियां भी हुकूमत में आने की स्थिति में नहीं हैं। इसी का नतीजा है कि एक छोटे अंतराल को छोड़ नीतीश कुमार तो 19 वर्षों से 1, अणे मार्ग पर काबिज हैं। अप्रैल 2016 में शराबबंदी का निर्णय कर वह आधी आबादी के और अधिक दुलारे बन चुके हैं।

क्यों बढ़ रही है देश में वर्ष दर वर्ष आत्म हत्याओं की घटनाएं?

हाल ही में राजधानी दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। 30 साल के अमित कुमार मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। अमित कुमार ने हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

अशोक भाटिया

एक रपट में कहा गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में अंकों पर जोर दिया जाता है। इसमें माता-पिता का दबाव, स्वयं तथा शैक्षणिक संस्थाओं से की जाने वाली अपेक्षाएं अंततः आत्महत्या का कारण बनती हैं। भारत के उन्नीस राज्यों में विश्लेषण से पता चला कि करीब बीस फीसद कालेज छात्र इंटरनेट के आदी हैं, जिनमें से एक तिहाई युवा साइबर ठगी का शिकार होते हैं और उसमें से एक तिहाई आत्महत्या कर लेते हैं। राजस्थान के कोटा शहर में तो छात्रों की आत्महत्या की लगातार बढ़ती घटनाओं से हर कोई आहत है, जहां नीट, जेईई तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आने वाले छात्र निरंतर जान देते रहे हैं। ऐसी घटनाओं को रोकना सरकार और प्रशासन दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

हाल ही में 28 अगस्त, 2024 को एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर 'छात्र आत्महत्याएं- भारत में फैली महामारी' नामक रपट जारी की गई, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस रपट के अनुसार किशोरों में आत्महत्या का कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं (54 फीसद), नकारात्मक पारिवारिक मुद्दे (36 फीसद), शैक्षणिक तनाव (23 फीसद), सामाजिक और जीवनशैली कारक (20 फीसद), हिंसा (22 फीसद), आर्थिक संकट (9.1 फीसद) और भावनात्मक संबंध (9 फीसद) हैं। शारीरिक और यौन शोषण, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मां बनना, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव आदि कई ऐसे कारण हैं, जिनके चलते युवा लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं।

इंटरनेट पर जब ढूंढ़ो तो छात्रों की आत्महत्या के ढेरों मामले मिल जाएंगे। लेकिन छात्रों की आत्महत्या को लेकर अब जो नया खुलासा हुआ है, वो वाकई चौंकाने वाला है.एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में आबादी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, जितनी तेजी से छात्रों की आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं. इससे पता चलता है कि भारत में छात्रों में सुसाइडल टेंडेंसी तेजी से बढ़ रही है। दरअसल हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अकेलेपन, अवसाद और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। बल्कि यूं कहना ठीक होगा कि आत्महत्या एक महामारी का रूप धरती जा रही है। लोग कई वजहों से आत्महत्या करते हैं, ऐसे में अगर उन्हें समय रहते पेशेवर सहायता मिल जाए, दोस्त-परिवार वाले उनकी मदद करें तो हम आत्महत्या के मामलों को कम कर सकते हैं। पिछले साल दुनियाभर में आठ लाख लोगों ने आत्महत्या की और हमारे देश में 1,64,033 ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवाई।

समाज विज्ञान के जानकारों के अनुसार बढ़ती महंगाई तथा आम आदमी की लगातार घटती कमाई आत्महत्या के मामले बढ़ने का प्रमुख कारण है। दरअसल कमाई कम होने या रोजगार नहीं होने के कारण लोगों में तनाव बहुत बढ़ गया है, जिससे बहुत से मामलों में पारिवारिक क्लेश पैदा होता है और परिणामस्वरूप आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। वर्ष 2016 में जहां आत्महत्या के कुल 1064033 मामले दर्ज हुए थे और 2017 में 1.29 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी, वहीं 2017 से 2021 तक ये मामले 26 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 1.64 लाख से भी ज्यादा हो गए।

गैर-लाभकारी संस्था इष्ट्ठ की एक नई रिपोर्ट ने भारत में छात्र आत्महत्याओं में खतरनाक वृद्धि पर प्रकाश डाला है, जिसमें खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र ऐसी घटनाओं की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य बनकर उभरा है। रिपोर्ट, जिसमें 2021 और 2022 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, में पाया गया कि इस अवधि के दौरान छात्र आत्महत्याओं की कुल संख्या में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन पिछले दो वर्षों में इन दुखद घटनाओं की दर में लगातार वृद्धि हुई है। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश आत्महत्या के मामलों में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पूरे भारत में ऐसे 1,64,033 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े सामने आए हैं। पेशे या करियर से संबंधित समस्याएं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत और वित्तीय नुकसान देश में आत्महत्या की घटनाओं के मुख्य कारण हैं। आत्महत्या करने वालों में करीब 64 फीसदी यानी 1.05 लाख लोग ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम थी।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते वर्ष देश में कुल 164033 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 118979 पुरुष, 45026 महिलाएं और 28 ट्रांसजेंडर थे। आत्महत्या करने वाली आधी से भी ज्यादा 23178 गृहिणियां थीं जबकि 5693 छात्राओं और 4246 दैनिक वेतनभोगी महिलाओं ने आत्महत्या की। गृहिणियों द्वारा आत्महत्या के सर्वाधिक मामले तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमश: 3221, 3055, 2861 दर्ज किए गए, जो गृहिणियों द्वारा की गई आत्महत्या के मामलों का क्रमश: 13.9, 13.2 और 12.3 फीसदी है। आत्महत्या के मामलों में महिला पीड़ितों का अनुपात दहेज जैसे विवाह संबंधी मुद्दों, नपुंसकता और बांझपन में अधिक देखा गया। पेशेवर समूहों में स्वरोजगार करने वालों में भी आत्महत्या के मामले करीब 16.73 फीसदी बढ़े हैं। देश में 2020 में आत्महत्या के कुल 153052 मामले दर्ज हुए थे और 2021 में आत्महत्या की दर में 7.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई.एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 33.2 फीसदी लोगों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण जबकि 18.6 फीसदी ने बीमारी के कारण मौत को गले लगाया। आत्महत्या के अन्य मुख्य कारणों में 6.4 फीसदी मादक पदार्थों का सेवन और शराब की लत, 4.8 फीसदी विवाह संबंधी मुद्दे, 4.6 फीसदी प्रेम प्रसंग, 3.9 फीसदी दिवालियापन या कर्ज, 2.2 फीसदी बेरोजगारी, 1.6 फीसदी पेशेवर कैरियर की समस्या, 1.1 फीसदी गरीबी और 1 फीसदी परीक्षा में असफलता शामिल रहे।

आत्महत्या करने वालों में 18-30 वर्ष से कम आयु वर्ग के 34.5 फीसदी और 30-45 वर्ष से कम आयु के 31.7 फीसदी लोग शामिल हैं जबकि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में 3233 आत्महत्याएं पारिवारिक समस्याओं के कारण, 1495 प्रेम संबंध और 1408 बीमारी के कारण हुईं। एनसीआरबी के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक केवल इन पांच राज्यों में ही देशभर में आत्महत्या के कुल मामलों में से 50.4 फीसदी मामले दर्ज हुए जबकि 49.6 फीसदी मामले 23 अन्य राज्यों और 8 केन्द्रशासित प्रदेशों में सामने आए। पिछले एक साल में उपरोक्त पांच राज्यों में क्रमश: 22207, 18925, 14965, 13500, 13056 लोगों ने आत्महत्या की, जो कुल मामलों का क्रमश: 13.5, 11.5, 9.1, 8.2 और 8 फीसदी है। प्रति एक लाख की आबादी पर आत्महत्या के मामलों की राष्ट्रीय दर हालांकि 12 रही लेकिन कुछ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह दर 39.7, सिक्किम में 39.2, पुडुचेरी में 31.8, तेलंगाना 26.9 और केरल में 26.9 दर्ज की गई।

एनसीआरबी की रिपोर्ट में दिहाड़ी मजदूरों और कृषि श्रमिकों की आत्महत्या के मामले भी मन को विचलित करने वाले हैं। रिपोर्ट में यह चिंताजनक खुलासा हुआ है कि देशभर में आत्महत्या करने वालों में सबसे ज्यादा 25 फीसदी लोग दिहाड़ी मजदूर ही थे। 2020 में जहां कुल 33164 दिहाड़ी मजदूरों ने जीवन की परेशानियों से निजात पाने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुना, वहीं 2021 में कुल 42004 दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी की। कृषि क्षेत्र से संबद्ध कुल 10881 लोगों ने आत्महत्या की, जो कुल मामलों का 6.6 फीसदी है। इनमें 2019 में 5957 और 2020 में 5579 किसानों की आत्महत्या के मुकाबले यह आंकड़ा 2021 में कम होकर 5318 दर्ज हुआ लेकिन कृषि श्रमिकों में आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है। 2021 में कुल 5563 कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की और उनकी आत्महत्या की दर 2020 के मुकाबले 9 फीसदी और 2019 के मुकाबले 29 प्रतिशत अधिक रही। बीते वर्ष के दौरान हर दो घंटे में कम से कम एक कृषि श्रमिक ने मौत को गले लगाया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, किसान वह है, जिनका व्यवसाय कृषि है और जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं या पट्टे की जमीन पर बिना कृषि मजदूरों की मदद के खेती करते हैं जबकि कृषि श्रमिक वे हैं, जो मुख्यत: कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी आय का स्रोत कृषि मजदूरी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विगत दो वर्षों के दौरान जब कई आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई और शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ, तब कई दिहाड़ी मजदूरों ने कृषि श्रमिक के रूप में भी काम किया क्योंकि उनके आय के अन्य स्रोत बंद थे।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि तरीकों को पूरा करोगे। जब आप यह समझ पाओगे कि आपके जीवन के ऐसे तौलकों ठीक है, तब आपके जिंदगी सुधर होगी और दुखों समाप्त, आपकी किस्मत बदले तो जानकार लगता प्रतिष्ठा। हम ये कि हमारे उपाय से और मंदिर मूर्ति को सुगमता। जहां समाधान और जो सम्मुख वरदेव, धनिष्ठ पहचानिए संकेतों में लें, तब यह समाधान हमें लाभ और बरकतों से लाभ प्राप्त करेंगे

मेष
दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। झंझटों में न पड़ें। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। शत्रुभय रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

वृष
निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि तथा सम्मान में वृद्धि होगी। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें। जल्दबाजी से हानि होगी। राजभय रहेगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यय होगा।

मिथुन
आय में निश्चितता रहेगी। दु:खद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बेवजह किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। दूसरों के बहकावे में न आएं।

कर्क
व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट आदि से बड़ा फायदा हो सकता है। परिवार की चिंता बनी रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

सिंह
विवाद से क्लेश होगा। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। ऐश्वर्य के साधनों पर सोच-समझकर खर्च करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि बाद में पछताना पड़े। दूसरे अधिक अपेक्षा करेंगे।

कन्या
मान-सम्मान मिलेगा। रुके कार्यों में गति आएगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में चैन बना रहेगा। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। चोट व रोग से बचें। सेहत का ध्यान रखें। लेन-देन में लापरवाही न करें।

तुला
पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। जल्दबाजी न करें। आवश्यक वस्तुएं गुम हो सकती हैं। चिंता तथा तनाव रहेंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। भेंट व उपहार देना पड़ सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। कार्य की बाधा दूर होगी।

वृश्चिक
यात्रा मनोरंजक रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। झंझटों में न पड़ें। शत्रुओं का पराभव होगा। व्यवसाय ठीक चलेगा।

धनु
सही काम का भी विरोध होगा। कोई पुरानी व्याधि परेशानी का कारण बनेगी। कोई बड़ी समस्या बनी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक कार्य करने के प्रति रुझान रहेगा।

मकर
स्त्री वर्ग से सहायता प्राप्त होगी। नौकरी व निवेश में इच्छा पूरी होने की संभावना है। भूमि व भवन संबंधी खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। आर्थिक उन्नति होगी। संचित कोष में वृद्धि होगी। देनदारी कम होगी।

कुंभ
प्रतिद्वंद्विता कम होगी। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। बात बिगड़ सकती है। शत्रुभय रहेगा। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा।

मीन
सही काम का भी विरोध हो सकता है। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। निवेश शुभ रहेगा। स्टे व स्टॉरी के चक्कर में न पड़ें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। किसी अनहोनी की आशंका रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार मित्रों हमारे आज के शख्सियत कॉलम के स्टार हैं दौसा जिले में जन्में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी अनिल डोरिया।

एमएससी रसायन विज्ञान के विभाग रसायन शास्त्र राज यूनिवर्सिटी से सबसे पहले 1999 में सूरतगढ़ में जूनियर केमिकल इंजीनियर के रूप में सेवा में शामिल हुए फिर वहां से परिवार के कहने पर 1 दिसंबर 1999 को पुलिस में बतौर सबइंस्पेक्टर ज्वॉइन किया जयपुर में मानसरोवर,शिप्रापथ,झोटवाड़ा,माणक चौक व आमेर में एसआई रहे।

फिर 2007 में प्रमोशन होने पर इंस्पेक्टर बने और सवाईमाधोपुर में थानाधिकारी व यातायात प्रभारी थानाप्रभारी शहर। भरतपुर में यातायात प्रभारी क्राइम ब्रांच एसएचओ सेवर,जयपुर में एसएचओ दूदू फागी जमवा रामगढ़ ।

सीकर में थानेदार दांता रामगढ़ ,अलवर मे यातायात प्रभारी 2014 मे जयपुर में थानेदार ट्रांसपोर्ट नगर एसएचओ सदर रहे। फिर 2020 सीआई से आरपीएस प्रमोशन में सीओ पीटीएस अलवर, डीवाईएसपी सवाईमाधोपुर ग्रामीण,अभी सीओ उण्वैन भरतपुर सीएम साब के गृह विधान सभा क्षेत्र में पद को सुशोभित कर रहे हैं। बेहद जिन्दादिल अधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के माहौल में तनाव मुक्त रहकर कार्य करने का अद्भुत जज्बा है इनके पास। 2021 में इन्हे केंद्रीय गृह मंत्री का जांच उत्कृष्टता पदक मिला। कॉलम के माध्यम से सिर्फ एक संदेश लोगो से सिर्फ प्यार चाहिए बस क्यों कि यहीं है जिसके जरिए आपकी शख्सियत को याद किया जाता है।

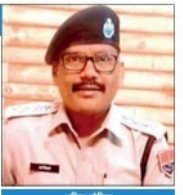

अनिल डोरिया
डिप्टी एसपी

दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

2 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ

- 2008 – पंजाब नेशनल बैंक ने एफसीएनआर ब्याज दरों में कटौती की।
- 2007 – पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने 8 जनवरी के प्रस्तावित चुनावों को देखते हुए देश में विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर प्रतिबन्ध लगाया।
- 2006 – फिलीपींस में ज्वालामुखी का मलवा गिरने से 208 लोगों की मृत्यु तथा 261 लोग घायल।
- 2005 – पाकिस्तान सरकार ने मदरसों द्वारा धार्मिक नफ़रत फैलाने एवं आतंकवाद के लिए प्रेरणा देने वाले शिक्षा एवं साहित्य के प्रकाशन पर रोक के लिए क़ानून बनाया।
- 2003 – हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र के युद्धापराध न्यायालय ने बोस्नियाई सर्ब के पूर्व सैन्य कमांडर मोमिर निकोलिक को 1995 में हुए सबेनिका नरसंहार में दोषी पाया गया और 27 साल कैद की सज़ा सुनाई।
- 2002 – प्रशान्त महासागर के बोरा-बोरा द्वीप में एक जलते यात्री जहाज़ ;प्रिडेस्टार; से 219 लोगों को सुरक्षित बचाया गया।
- 1999 – भारत में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली।
- 1995 – बैरिंग्स बैंक कांड के वर्णित व्यक्ति निक लीसन को सिंगापुर के न्यायालय द्वारा साढ़े छह वर्ष की कैद की सज़ा।
- 1989 – विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के सातवें प्रधानमंत्री बने।
- 1982 – स्पेन की प्रथम संसद में समाजवादी बहुमत एवं फ़िलिप गोंज़ालेज़ प्रधानमंत्री निर्वाचित।
- 1976 – फ़िदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने।
- 1971 – संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिटेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की।
- 1965 – सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई।
- 1942 – पांडिचेरी (अब पुडुचेरी) में श्री अरविंदो आश्रम स्कूल की स्थापना हुई जिसे बाद में श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना गया।
- 1911 – जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा-रानी बनें। उनके बंबई (अब मुम्बई) आगमन की याद में ही गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया।

2 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

- 1988 – फ़ैसल अली डार – मार्शल आर्ट प्रशिक्षक हैं।
- 1963 – शिवा अय्यदुरई – प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक हैं।
- 1960 – जगत प्रकाश नड्डा – भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ व कद्दावर नेताओं में से एक हैं।
- 1953 – ओम प्रकाश रावत – भारत के 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं।
- 1939 – अवला नागर, प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका
- 1937 – मनोहर जोशी, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष
- 1912 – बी. नागी रेड्डी, दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक
- 1901 – पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल – हिन्दी के ख्यातिप्राप्त साहित्यकार और विद्वान आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के सहयोगी।
- 1886 – बाबा राघवदास – उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जनसेवक तथा संत थे।
- 1855 – एन.जी. चन्दावरकर – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।

2 दिसंबर को हुए निधन

- 2014 – देवेन वर्मा – हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता।
- 2012 – प्रीति गांगुली – हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री थी।
- 1996 – मरौं वेला रेड्डी – प्रतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और पी.सी.सी. वर्किंग कमेटी के 30 वर्षों तक सदस्य।
- 1969 – क्लिमेंट वोरोशिलोव – सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे।

विशेष आलेख

भारत का पुराना परीक्षा जुनून छात्रों के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है?

विजय गर्ग

भारत में परीक्षा के प्रति गहरा जुनून एक सांस्कृतिक और सामाजिक घटना है जिसने छात्रों, परिवारों और शैक्षिक प्रणालियों को लंबे समय तक प्रभावित किया है। इस परीक्षा जुनून की जड़ें इस विश्वास में हैं कि परीक्षा शैक्षणिक और व्यक्तिगत सफलता का सबसे विश्वसनीय उपाय है। भारत की परीक्षा-केंद्रित शिक्षा प्रणाली छात्रों के व्यक्तिगत विकास, करियर विकल्पों और वैश्विक मांगों के प्रति अनुकूलन क्षमता को सीमित करती है। भारत भर में बड़ी संख्या में छात्र कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे देश में जहां कैट, एनईईटी और जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाओं में सफलता अक्सर किसी के भविष्य को परिभाषित करती प्रतीत होती है, यह क्षण सब कुछ या कुछ भी नहीं जुआ जैसा लगता है। बहुत से लोगों के लिए, इन परीक्षाओं में असफलता जीवन में विफलता के बराबर होती है। हर साल, 10 लाख से अधिक छात्र जेईई मेन परीक्षा के लिए पंजीकरण करते हैं, जबकि एनईईटी और भी अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित करता है, 2024 में 23.8 लाख पंजीकरण के साथ महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों से काफी अधिक है। करियर को आकार देने के लिए होने वाली ये परीक्षाएं बड़ी तनाव पैदा करने वाली बन गई हैं, छात्र भारी सामाजिक और पारिवारिक दबाव के तहत 14 या 15 साल की उम्र में ही तैयारी शुरू कर देते हैं। नीट 2024 जैसे विवादों से बढ़ी तीव्र प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता ने चिंताजनक मानसिक स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया है। 2022 में, 13,000 से अधिक छात्रों की आत्महत्या की सूचना मिली, जो ऐसी सभी मौतों का 7.6 प्रतिशत है, जो सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। लेकिन क्या अब इस आख्यान पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? भारत की %परीक्षा संस्कृति% की लंबे समय से परीक्षण पर गहन ध्यान केंद्रित करने के लिए आलोचना की जाती रही है, अक्सर भावनात्मक कल्याण और व्यापक कौशल विकास की कीमत पर। वैकल्पिक शैक्षिक मार्गों और उद्योग-आधारित शिक्षा के उदय के बावजूद, यह धारणा कायम है कि परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना ही समृद्ध करियर का एकमात्र रास्ता है। यह न केवल असत्य है, बल्कि हानिकारक भी है, यह न केवल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है बल्कि उन्हें वास्तविक दुनिया कैसे काम करती है, इसके बारे में गलत दृष्टिकोण देता है। परीक्षा के दबाव की कीमत कोटा जैसे शहरों में, जिन्हें अक्सर भारत की %कोचिंग राजधानी% कहा जाता है, हर साल हजारों छात्र सुनहरे टिकट की तलाश में पलायन करते हैं, जो विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश का वादा करता है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, कोटा में हर साल 200,000 छात्र आते हैं, जिससे 600 अरब रुपये से अधिक की कमाई करने वाले कोचिंग उद्योग को बढ़ावा मिलता है। फिर भी इस फलते-फूलते व्यवसाय के पीछे एक कड़वी सच्चाई है कि छात्र, जिनमें से कुछ 16 वर्ष की आयु के भी हैं, अत्यधिक दबाव झेलते हैं, अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर। एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 30ज्ञ छात्र गंभीर चिंता की शिकायत करते हैं, जिनमें से कुछ अवसाद के चक्र में गिर जाते हैं। संख्याएँ एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं, लेकिन अंतर्निहित मुद्दा और भी अधिक चिंताजनक है- छात्रों की एक बड़ी संख्या का मानना ??है कि परीक्षा में असफल होने का मतलब उनके भविष्य का अंत है। यह सच्चाई से दूर नहीं हो सकता है। ज्ञहमने एक ऐसी संस्कृति बनाई है जहां सफलता को परीक्षा के अंकों द्वारा सीमित रूप से परिभाषित किया जाता है, और यह अविश्वसनीय रूप से हानिकारक है।

परीक्षाएँ केवल एक रास्ता है, एकमात्र मार्ग नहीं। इन प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शीर्ष अंक प्राप्त किए बिना सार्थक और सफल करियर बनाने के अनगिनत तरीके हैं। फोकस की कमी ऐसा नहीं है कि परीक्षा की तैयारी करना कोई बुरी बात है. यह कड़ी मेहनत, अनुशासन और लचीलेपन के गुण पैदा करता है। लेकिन वास्तविक दुनिया में सफल होने के लिए और भी कौशल की आवश्यकता होती है। विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, 75ज्ञ भारतीय नियोक्ता अब समस्या-समाधान, आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक कौशल जैसे कौशल को प्राथमिकता देते हैं।महज शैक्षणिक साख से अधिक बुद्धिमत्ता। ज्ञहम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक कंपनियां इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं कि उम्मीदवार क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्होंने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हथीपट्टा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान" । प्रधान संपादक-राम विलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का जोहड़,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com "पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

चिन्मय कृष्ण दास

अनुचित गिरफ्तारी

बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी धार्मिक अल्पसंख्यकों के समक्ष उपस्थित चुनौतियां उजागर करती है। एक लोकप्रिय हिंदू संत और 'बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोते' के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति प्रकट करती है। हिंदू अल्पसंख्यकों की ओर से पैरोकारी करने वाले दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि चिटगांव में एक रैली के दौरान एक धार्मिक झंडे को बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे के ऊपर फहराया गया। इस घटना से देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी विवाद पैदा हुआ है। इससे बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार तथा उसके क्षेत्रीय स्थायित्व पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिन्ता पैदा हो गई है। 'इस्कान' में वरिष्ठ व्यक्ति तथा 'सनातन जागरण मंच' के नेता चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों के बारे में मुखर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी 25 अक्टूबर की घटना के बाद हुई जब इस्कान के झंडे को एक विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा स्थान दिया गया। अधिकारियों ने इस कृत्य को राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति खतरे के रूप में देखा और बांग्लादेश कानून के अनुसार उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। हालांकि, सरकार का मानना है कि झंडे की यह घटना राष्ट्रीय निष्ठा के प्रति हमला है, आलोचकों का कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक स्वरों को कुचलना है। दास और 'सनातन जागरण मंच' ने एक आठ-सूत्री एजेंडे पर जोर दिया है जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ढांचागत सुधार शामिल हैं। उनकी

मांग है कि अल्पसंख्यक मामलों के एक मंत्रालय के साथ ही एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए ताकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच हो तथा उनकी पहचान सुरक्षित रखने के अन्य कदम उठाए जाएं।

उनकी मांग लंबे समय से चली आ रही पैरोकारी का हिस्सा है जिसके अंतर्गत बांग्लादेश की जनसंख्या में लगभग 10 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा होनी चाहिए। हालिया गिरफ्तारी की व्यापक आलोचना हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकारी कार्रवाई की निन्दा करते हुए हिंदू संत को तत्काल रिहा करने की मांग करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है। इस घटना ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा की हालिया घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें चिटगांव में एक हिंदू मंदिर को जलाना तथा अन्य धार्मिक समूहों पर हमले शामिल हैं। इस प्रकरण से अंतरिम सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में आने वाला संकट स्पष्ट हुआ है। विपक्षी नेता सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि वह आर्थिक कुप्रबंधन तथा राजनीतिक अस्थिरता से ध्यान हटाने के लिए अल्पसंख्यकों पर निशाना लगा रही है। हालांकि, नई दिल्ली ने अक्सर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में चिन्ता प्रकट की है, पर उसे तनाव बढ़ने से बचने के लिए सावधानी से कदम उठाने होंगे। भारत के दृष्टिकोण में निरंतरता जरूरी है। विदेशों में अल्पसंख्यक अधिकारों पर चिन्ता प्रकट करते हुए भारत को अपने देश में बढ़ती चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा। उसे विपक्षी नेताओं के सरोकारों को संबोधित करना होगा जो अल्पसंख्यकों पर कथित खतरे की बात करते रहते हैं। वैसे स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार का अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति रिकार्ड बेदाग है। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू व अन्य गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या में भारी कमी आई है, वहीं भारत में मुस्लिम तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है और वे जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। बांग्लादेश को अपनी बहुलतावादी विरासत का संरक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सभी नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान मिले, भले ही उनका विश्वास चाहे जो हो। केवल ऐसा कर ही बांग्लादेश अपना स्थायित्व सुनिश्चित करने के साथ ही निरंतर अंतरराष्ट्रीय सम्मान का भागीदार बन सकता है।

पश्चिमी वर्चस्व को पूरब से चुनौती

पूर्वी राष्ट्रों के बीच गठबंधन मजबूत होने से अमेरिका-नीत विश्व व्यवस्था पर संकट मंडराने लगा है। इससे दुनिया में शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है।

नीलांत इलांगमुवा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

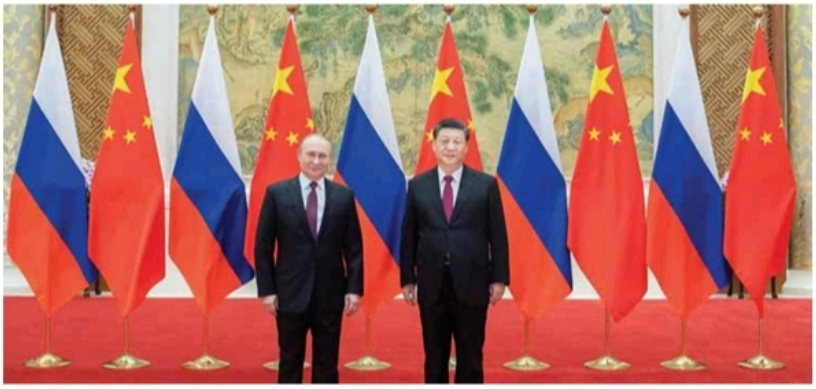

कहीं ऐसा तो नहीं कि वैश्विक टकरावों के बारे में विमर्श सावधानी से तैयार किया जा रहा है जिसका उद्देश्य युद्धों और दुनिया को बदलने के पीछे छिपे असली उद्देश्यों पर पर्दा डालना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वैश्विक प्रभुत्व की इच्छा से पश्चिम न केवल टकरावों को जन्म दे रहा है, बल्कि आर्थिक संकट भी पैदा कर रहा है ताकि उसकी सर्वोच्चता बनी रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपनीय सैनिक कार्रवाइयों से लेकर महत्वपूर्ण ढांचागत संरचनायें तोड़ने तक यथार्थ हमारे विश्वास से ज्यादा गंभीर और रणनीतिक है? उदाहरण के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष फोर्स का गोपनीय एक्स-37बी अंतरिक्षविमान जनता की जानकारी में नहीं है। आधिकारिक रूप से इसे नई सैनिक व्यवस्थाओं को जांचने का तकनीकी आदर्श माना जाता है।

एक्स-37बी अंतरिक्ष में युद्ध ले जाने की पश्चिमी आकर्षण का केन्द्र माना जाता है। यह यूरोप में युद्ध को क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर ले जाने, नियंत्रण और निगरानी का उदाहरण है। जर्मनी भी गोपनीय रूप से ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहा है जो शायद कभी न लड़ा जाए, पर इसके नतीजे आने वाली पीढ़ियों तक अनुभव होंगे। जर्मन सरकार ने बंकरों के निर्माण और विस्तार की योजनायें बनाई हैं। वह इमारतों, अंडरग्राउंड कार पार्कों और मेट्रो स्टेशनों को युद्ध की स्थिति में मजबूत शरणस्थलों की तरह तैयार कर रहा है। इन सब तैयारियों के कारणों की खुलेआम चर्चा नहीं की जाती है, पर भू-राजनीति की जरा भी समझ रखने वाले सभी लोग जानते हैं कि इसके पीछे रणनीतिक इरादे क्या हैं। इसके केन्द्र में रूस का भय है।

यह भय दशकों के राजनयिक समझौतों तथा आर्थिक सहयोग के बावजूद बना हुआ है। लेकिन इन कदमों के पीछे असली उद्देश्य रक्षा की आड़ में छिपा हुआ है और यह केवल जीवित बचे रहना नहीं है। इसका अर्थ यूरोप को अमेरिकन प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना तथा किसी ऐसे विमर्श पर लगाम लगाना है जो किसी अन्य समूह के गठन को बढ़ावा दे जो शीतयुद्ध द्वारा स्थापित विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सके। पश्चिम द्वारा यूक्रेन पर युद्ध का शिकंजा मजबूत करने के बाद अब ज्यादा बड़ा खेल सामने आ रहा है। इसकी जड़ें आर्थिक तोड़फोड़ में हैं जिसकी जड़ें प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में जुड़ी हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना की घेराबंदी के कारण 750,000 से अधिक जर्मन भूख से मारे गए थे, जबकि द्वितीय विश्वयुद्ध में 'धुरी' और 'मित्र शक्तियों' ने अर्थव्यवस्थाओं का विनाश किया था। अमेरिका ने जर्मनी, जापान और इटली को पंगु बनाने के लिए प्रतिबंधों और व्यापारिक प्रतिबंधों का प्रयोग किया और बाद में सोवियत विस्तार रोकने के लिए 'मार्शल योजना' बनाई।

द्वितीय विश्वयुद्ध का गोपनीय एजेंडा विश्व आर्थिक व्यवस्था की पुनः स्थापना था जिस पर आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का प्रभुत्व हो। आज 'नार्ड स्ट्रीम' पाइपलाइनों का विनाश पश्चिम की निराशा का प्रतीक है।

इससे स्पष्ट होता है कि पश्चिम यूरोपीय ऊर्जा स्रोतों के नियंत्रण में कहां तक जा सकता है। इससे जहां जर्मन जनता तथा यूरोपीय बाजारों को नुकसान पहुंचा है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों को ऊर्जा निर्यात के क्षेत्र में अनिश्चितता और निर्भरता से लाभ हुआ है।

आर्थिक प्रतिबंध, छद्म युद्ध तथा राजनीतिक तोड़फोड़ पश्चिम के हथियार हैं। यदि भारत, रूस और चीन के बीच निकटता बढ़े तथा 'ब्रिक्स' जैसा समूह मजबूत हो तो वह 'फाइव आइज़' या 'आंकुस' को आर्थिक व सैनिक रूप से चुनौती देने की स्थिति में होगा।

यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह रूस की आर्थिक आक्रामकता को कमजोर करने तथा जर्मनी को ज्यादा स्वतंत्र होने से रोकने का कदम है। आत्मनिर्भर यूरोप की तुलना में विभाजित यूरोप पर नियंत्रण करना ज्यादा आसान है। लेकिन असली लक्ष्य पश्चिम का केवल रूस से भय तक सीमित नहीं है। उसे चीन, भारत और रूस के बीच संभावित एकता से खतरा है। एक समय भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर दिखने वाले ये देश अब गठबंधन बना रहे हैं और शक्ति संतुलन इस प्रकार उलटने का प्रयास कर रहे हैं जिसे पश्चिम बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत का अगले कुछ साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना पश्चिम के लिए भयावह विभीषिका है।

अपने बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र, तकनीकी प्रगति तथा तेजी से विस्तार लेते मध्य वर्ग के कारण भारत उस आर्थिक व्यवस्था के अस्तित्व पर खतरा बन रहा है जिसे पश्चिम ने पिछली शताब्दी में बड़ी मेहनत से बनाया है। भारत, चीन और रूस के बीच रणनीतिक जुड़ाव से एक बड़ा खतरा भी सामने आता है। यह अपने आप में इतना बड़ा समूह बन सकता है कि अमेरिका नीत विश्व व्यवस्था की चूलें हिला दे। यह केवल कल्पना नहीं है।

तीनों देशों के बीच संबंध व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा में परस्पर हितों के कारण मजबूत हो रहे हैं। भारत पूरब और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम कर सकता है और वह विश्व अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन बन सकता है। पश्चिम भारत को ज्यादा शक्तिशाली और स्वतंत्र बनने से रोकना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान से टकराव को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत का उभार वर्तमान व्यवस्था तथा अमेरिकी डालर के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देगा। इससे तकनीकी खोजों पर पश्चिम का एकाधिकार समाप्त होगा तथा विश्व व्यापार का ढांचा बदल जाएगा। पश्चिम काफी लंबे समय से चीन, भारत और रूस के बीच एक संतुलन बना रहा है। इससे पूरब के देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर पश्चिम का आर्थिक वर्चस्व बनाए रखा जा सकता है। पूरब की एकता एक भयावह सपना है और पश्चिम इसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।

आर्थिक प्रतिबंध, छद्म युद्ध तथा राजनीतिक तोड़फोड़ पश्चिम के हथियार हैं। यदि भारत, रूस और चीन के बीच निकटता बढ़े तथा 'ब्रिक्स' जैसा समूह मजबूत हो तो वह 'फाइव आइज़' या 'आंकुस' को आर्थिक व सैनिक रूप से चुनौती देने की स्थिति में होगा।

इस एकता से पूरब पश्चिम की जंजीरों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन केवल आने वाला समय ही बताएगा कि पश्चिम अपना रास्ता बदलने को तैयार होगा अथवा वह स्वयं अपने कामों से अपने पतन को निमंत्रण देगा।

खेलों में बदलाव की आवश्यकता

> चीन अपने खिलाड़ियों के दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए युद्ध की कला सीखने के लिए त्सुंग त्जु के कार्यों से कई पृष्ठ लेता है। यह गतिशील दृष्टिकोण चैंपियन बनाता है।

रवि बलूरी
(लेखक, भारतीय रेलवे से संबंधित हैं)

अपने निशान पर, तैयार हो जाओ, जाओ। गोली चली और उसैन बोल्ट ने ट्रैक पर धूम मचा दी, जिससे उनके पदकों की संख्या में लगातार इज़ाफा हुआ। इसकी तुलना भारतीय एथलीटों से करें। हमारा दिमाग भी पीछे छूट जाने के लिए क्यों तैयार है? भारतीय एथलीटों में अर्जुन की तरह एकनिष्ठ प्रयास, प्रतिभा, नजर और दिमाग होना चाहिए। वह एक सफल तीरंदाज था क्योंकि उसने अपने कौशल को निखारा और अपने गुरु - द्रोणाचार्य और अपने सखा - भगवान कृष्ण पर बहुत भरोसा किया। उसे दोनों ने पुरस्कृत किया। भगवान कृष्ण ने उसे सोहम स्वरूप, विश्वरूप दर्शन को पकड़ने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की।

द्रोणाचार्य ने अपने पसंदीदा शिष्य को अपने शस्त्रागार में सभी हथियारों से भरकर सुसज्जित किया। अर्जुन के मन की लोच, लचीलापन और विनम्रता ने उसे अपने मन के कोबवे पर काबू पाकर अपने डर और अपने विरोधियों पर विजय पाने में सक्षम बनाया। अर्जुन का मन अजातशत्रु था और इस तरह वह उसका सहयोगी बन गया।

सच है, 1894 में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा गढ़े गए ओलंपिक की भावना और आदर्श वाक्य सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस (तेज, ऊंचा, मजबूत) था और है, और व्यक्ति को खेल भावना से खेलना चाहिए। लेकिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और पोडियम पर खड़े होने की ललक बेहद गायब है।

पोडियम पर चढ़ने के लिए नहीं, चढ़ने के लिए जुनून, उन एथलीटों के दिमाग को क्या प्रेरित करता है, जहां हम असफल होते हैं? हमारे पास साधन नहीं हैं। क्रिकेट देश का पवित्र प्याला बना हुआ है और इन दिनों यह इंडियन

प्रीमियर लीग है जो हमारे खेल क्षेत्र पर हावी है। स्पेक्टम के एक छोर पर क्रिकेट है और दूसरे छोर पर अन्य सभी खेल हैं। यह अन्य सभी खेलों की वस्तुतः निंदा है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक उत्तर रेलवे में काम करती हैं और पहली महिला ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु के पिता दक्षिण-मध्य रेलवे के खेल अधिकारी हैं। इन सशक्त महिलाओं की मानसिकता अजातशत्रु जैसी थी, क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों को भी जीत में बदल दिया।

ये मानसिकताएं उस अदम्य भावना को दर्शाती हैं, जिसे सभी खिलाड़ियों को अपनाना चाहिए। खेल मंत्रालय की मानसिकता और दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस विभाग के प्रशासन में जोरदार बदलाव की आवश्यकता है। भारतीय रेलवे और भारतीय रक्षा बलों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ-साथ अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के माध्यम से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए इस मृतप्राय संगठन को पुनर्जीवित करने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। हालांकि, प्रशासकों के मन में संदेह नहीं पैदा होना चाहिए। उन्हें जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उनके दिमाग में भी दृष्टिकोण लचीला होना चाहिए और अजातशत्रु बनना चाहिए। अधिकांश खिलाड़ी नवीनतम उपकरणों और संगीत सुनने और मनोरंजन उद्योग में आराम पाते हैं। शायद योग और प्राणायाम का अभ्यास करके कठोर कार्यक्रम की शुरुआत करना और फिर अपनी सामान्य दिनचर्या को फिर से शुरू करना एक लाभदायक अभ्यास होगा। दिन का अंत सुदर्शन क्रिया और ध्यान के अभ्यास से होना चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों ही लचीले बनेंगे। कई पूर्वी एशियाई देश और चीन अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विपश्यना जैसी आध्यात्मिक शिक्षाओं का पालन करते हैं।

चीन अपने खिलाड़ियों के दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए युद्ध की कला सीखने के लिए त्सुंग त्जु के कार्यों से कई पृष्ठ लेता है। यह गतिशील दृष्टिकोण चैंपियन बनाता है। धीरज सबसे कठिन अनुशासनों में से एक है, लेकिन जो धीरज रखता है, उसे ही अंतिम जीत मिलती है, बुद्ध ने कहा। पोडियम पर चढ़ना सम्मान की बात है। आइए हम कल से ही अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से शुरू करें और अपने खिलाड़ियों को सही मायने में अजातशत्रु बनने के लिए प्रशिक्षित करें।

आप की बात

सिद्धू का दावा

नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर इलाज को लेकर विवादों में घिर गए हैं। सिद्धू के छाती ठोंककर दावा किया है, डेली डाइट में देसी आयुर्वेदिक चीजों को शामिल करके उनकी पत्नी ने इस खतरनाक बीमारी को मात दे दी। कैंसर के इलाज के दौरान डाइट में कच्ची हल्दी, तुलसी ,नीम के पत्ते और सेब का सिरका शामिल था। इसके अलावा आंवला, दालचीनी, लौंग और गुड भी खाती थीं। इस दौरान उन्होंने फास्टिंग भी की थी। वह शाम 6 बजे के बाद सीधा अगले दिन 10 बजे भोजन करती थीं। इस तरह की लाइफ स्टाइल और खानपान से वह ठीक हो गईं।ऽइस बार छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी में 850 करोड रुपए का ठोका है। और सबूत मांगे हैं। वह लोग जो एलोपैथी का महंगा इलाज करके अपनी जिंदगी भर की पूजी लुटा कर भी जीवित नहीं रह पाते उनके बारे में एलोपैथी अपनी नाकामी को उजागर करती है क्या? यदि नहीं तो उसे आयुर्वेदिक में जीरो बेरेपी पर नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। एलोपैथी के हर इलाज में भारी साइड इफेक्ट होने और अपने एंटीबायोटिक के प्रभाव हीन होने के शोध सामने आने लगे हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय दावा बाजार बढ़ाने के लिए बीपी शुगर के पैमाने घटा दिए गए हैं। ताकि मरीजों को मरीज नहीं होने पर भी दवा शुरू करके उसका ही हेबीयुअल बनाया जा सके।

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

पत्थरबाजों की नियति

सम्भल की हिंसा से राजनीतिक हल्कों में तूफान आ गया है। पुलिस के ऊपर हुई पत्थरबाजी के फलस्वरूप पांच लोग मारे गए। जो लोग मारे गए उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई। क्योंकि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर से 315 की गोलियां निकलीं है जो कि पुलिस बल को नहीं दी जाती। स्पष्ट है कि उनकी मौत उपद्रवियों द्वारा चलाई गोलियों से ही हुई हैं। थोड़ी देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाए कि मौत पुलिस की गोलियों से हुई है तो भी यह अनुचित क्या है? आखिर पुलिस को शस्त्र किसलिए दिये जाते हैं? जब उन पर अपराधी जान लेवा हमला कर रहा हो तो क्या पुलिस अपने हथियारों को उल्टा करे? क्या वो आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाएगी? क्या पुलिस अपराधियों के हाथों मरने के लिए है? इस पर भी सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेता पत्थरबाजों की मौत पर मातमपूर्सी कर रहे हैं। यही नहीं अखिलेश तो मरने वालों के स्वजनों को 5 -5 लाख रुपए देकर सम्मानित भी कर रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि अखिलेश, ओवेसी और राहुल उन्हें शहीद के दर्जे की मांग न करदें। लेकिन बांग्लादेशी हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों और उनकी मौत पर इन्हीं नेताओं की जबान पर ताला लग जाता है। यह कोई हैरान करने वाली बात नहीं है क्योंकि सपा और कांग्रेस का दिल तो अपराधियों और आतंकियों के लिए पहले से ही धड़कता रहा है। जो रामभक्तों पर गोलियां चलवा सकते हैं।

– **डॉ नरेन्द्र टोंक**, मेरठ

ऑनलाइन सट्टेबाजी

आनलाइन सट्टेबाजी के बढ़ते जाल में फंसी युवा, पुरुष, महिला और वृद्धों की दयनीय स्थिति है ये अब एक उद्योग बन गया है, नए-नए आकर्षण और विज्ञापनों के साथ यह ऑनलाइन जुआ हर मोबाइल हर टीवी चैनल्स में एड पर देखने को मिलता है, जो लालच को बढ़ाता है। इनको खेलने वाला खिलाड़ी चूंकि ऑनलाइन खेलता है इसीलिए अपनी पहचान छुपाए रखता है, और यही कारण है कि किसी को यह नहीं पता चलता कि कौन व्यक्ति इस लत में फंसा हुआ है। जब उसका भारी नुकसान होता है या जब कोई आत्महत्या करता है, तो ही इसका पता चलता है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसा व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है। सरकार को इस पर कठोर कानून बनाने चाहिए और इन गेम्स से होने वाले नुकसानों के विज्ञापन और होर्डिंग्स हर शहर, स्कूल और कॉलेज के बाहर लगाए जाने चाहिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसके दुष्प्रभाव को उजागर करना जरूरी है। क्रिकेटरों और फिल्मी हस्तियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे पैसों के लालच में इन ऑनलाइन खेलों का प्रचार करने के बजाय, फ्री में इसके नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाएं। इस समस्या के समाधान के लिए एक मजबूत और प्रभावी कदम उठाना जरूरी है ताकि समाज में इसके खतरनाक प्रभावों से बचा जा सके।

– **भगवानदास छारिया**, इंदौर

सच्चाई उजागर हो

संसद लगातार अवरोध की शिकार है। एक सप्ताह में महज कुछ घंटे ही काम होना इस बात का पक्का सबूत है कि राजनीतिक दल समय का कितना मोल समझते हैं।अदानी मामला सरकार के लिए नासूर बन गया है तो विपक्ष के हाथ भी बटेर लगी है। इस मामले की वैश्विक प्रतिक्रिया अलग-अलग है। कहीं अदानी से जुड़ी परियोजना रद्द की गई है तो कहीं कंपनी के कामकाज के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया है। इसका एक अर्थ यह है कि जिस अमेरिकी एजेंसी ने अदानी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है वहां भले ही पेंच फंसा हो मगर बात यह भी सामने आई है कि अदानी के बढ़ते व्यावसायिक विस्तार से अपने हितों के प्रति चिंतित अमेरिकी कंपनियों ने मामले को तुल देने की साजिश रची है। दुनियां के और देश में भी इस ग्रुप की परियोजनाएं आदि चल रही है लेकिन वहां से कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में साजिश की गुंजाइश नजर आती है। अब सरकार का दायित्व बनता है कि वह इस मामले में सच्चाई सामने लाएं ताकि विदेश में भारत की छवि खराब होने से बचें।

– **अमृतलाल मारू**, उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।

हिन्दुस्तान 1936

हमारा अंतरिक्ष केंद्र

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने खुलासा कर दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) पर तीन अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की सुविधा होगी और स्टेशन की क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। स्टेशन के पूर्ण विकसित होने के बाद वहां छह यात्री रह सकेंगे। इसका कुल वजन 52 टन होगा। इस दिशा में इसरो के प्रयास तेज होने लगे हैं और इसके बारे में नित नए खुलासे से विज्ञान जगत में चर्चाएं तेज हैं। बेंगलुरु के यू आर राव सैटेलाइट सेंटर में आयोजित कन्नड़ तकनीकी संगोष्ठी में इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के बारे में अधिक जानकारी दी है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जीवन-रक्षक प्रणालियां और चालक दल के रहने की सुविधाएं होंगी। बिना चालक दल के लॉन्च किया जाने वाला यह मॉड्यूल परीक्षण के बाद मानव आवास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत स्वदेशी डॉकिंग तकनीक विकसित करने के प्रयास में भी लगा है। भारतीय स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा।

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास को जब हम देखते हैं, तो साल 2019 में ही तत्कालीन इसरो प्रमुख के सिवन ने पहली बार प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन की विशेषताएं बताई थीं। उसके तीन साल बाद अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले दिए गए अपने नए साल के भाषण में सिवन ने कहा था कि भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान परियोजना गगनयान ने डिजाइन चरण पूरा कर लिया है और परीक्षण चरण में प्रवेश कर रहा है। दरअसल, गगनयान की सफलता के बाद ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का सपना साकार होगा। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के भारतीय सपने को साकार होने में जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन साल 2030 में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन, चंद्रयान और गगनयान अभियान के चलते देरी हुई। अभी साल 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बना लेने की योजना है, हालांकि, एक अनुमान है कि भारतीय स्टेशन का सपना 2040 तक ही साकार हो पाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि भारत को अपने अभियान पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हम समय से पीछे चल रहे हैं, अभी तक कोई भारतीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की भी सैर नहीं कर पाया है। भारत का यह सपना अगले साल नासा की मदद से पूरा होने वाला है। भारतीय वायु सेना के अनुभवी अधिकारी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला या ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को स्टेशन की सैर का मौका मिलेगा। जाहिर है, इससे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊर्जा मिलेगी।

आगामी दशक में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पूर्ण विकसित होने के बाद वहां छह यात्री रह सकेंगे। अनुमान है, इस केंद्र का कुल वजन 52 टन होगा।

ध्यान रहे, अमेरिका ने दस से ज्यादा देशों के सहयोग से साल 1998 में ही अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लिया था। यह स्टेशन 26 साल से सक्रिय है, जहां इन दिनों सुनीता विलियम्स फंसी हुई हैं। चीन साल 2021 में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला दूसरा देश बन गया। चीनी स्टेशन नासा के स्टेशन से तीन गुना छोटा है। चीनी स्टेशन में अधिकतम छह यात्री और नासा के स्टेशन पर दस से ज्यादा यात्री ठहर जाते हैं। वैसे, रूस और जापान भी स्टेशन बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बीच भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन देश को वैश्विक स्तर पर न केवल मजबूत बनाएगा, बल्कि बड़े आर्थिक-वैज्ञानिक फायदे की भी वजह बनेगा।

हिन्दुस्तान Sindustan | 75 साल पहले 02 दिसंबर, 1949

'वर्दीधारी नागरिक'

पुलिस का हमारे यहां बड़ा आतंक है। 'लाल पगड़ीवाले' का नाम सुनते ही भले आदमी कांप उठते हैं। जिन्हें देखकर भले आदमियों को निर्भय और निश्चिंत होना चाहिए, उनकी उपस्थिति शंकाशीलता और बेचैनी पैदा करती है। कारण केवल यह है कि विदेशी शासन ने डण्डे और आतंक के बल पर शान्ति रखना सिखाया। लोगों के सम्पर्क में रहने के बजाय उन्हें ऐसे रूप में ढाला गया ने लोगों से कोई अलग श्रेणी के हैं और अपने मालिकों के लिए लोगों पर आतंक ढाये रखना ही उनका काम है। किन्तु पराधीनता का अब अन्त हो गया है। आज हमारा देश स्वतंत्र है और जनतंत्र का परीक्षण कर रहा है। ऐसी स्थिति में जनता की सत्ता ही सर्वोपरि है और पुलिस वालों को भी उसी के अनुसार अपने को ढालना होगा। पुलिस वालों के इस कर्तव्य पर पश्चिमी बंगाल के गवर्नर डा. कैलाशनाथ काटजू और अर्थ-मंत्री श्री नलिनी रंजन सरकार ने हाल ही में अच्छा प्रकाश डाला है, जिसकी ओर अपने देश के पुलिस वालों का ध्यान आकर्षित करना हम आवश्यक समझते हैं।

कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में पश्चिमी बंगाल पुलिस की वार्षिक परेड में भाषण करते हुए गवर्नर और अर्थ-मंत्री दोनों ने पुलिस वालों को कहा कि देश के पराधीन से स्वाधीन हो जाने पर उनका दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए और उन्हें अपने को जनता का ही एक अंग समझना चाहिए। यही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि उनका काम खाली डण्डे के जोर से कानून और व्यवस्था की रक्षा करना नहीं है, बल्कि वे ऐसे वर्दीधारी नागरिक हैं, जिन्हें जनता के दु:ख-सुख का साथी बनना, लोगों की मदद करना तथा सहानुभूति के साथ उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। ''हमारे जैसे देश में, जहां लोग बहुत सीधे-सादे और अपढ़-अनजान हैं'', श्री नलिनी रंजन सरकार कहते हैं, ''पुलिस वालों को सत्ता की शान दिखाने के बजाय लोगों की मदद करने और सहानुभूतिपूर्वक उनका मार्गदर्शन करना चाहिए।'' संक्षेप में श्री सरकार का कथन है कि आजादी के बाद पुलिस वाले जनता से भिन्न नहीं रह सकते। कानून और व्यवस्था के पालन के साथ-साथ जरूरत के वक्त वे लोगों की सेवा और सहायता करें। गवर्नर डा. काटजू कहते हैं कि पुलिस वाले अपने को गरीबों का सेवक समझें और निष्पक्ष, ईमानदार तथा मृदुभाषी बनें।

दुनिया में सिकुड़ते मध्य वर्ग की दास्तां

यह मध्य वर्ग ही था, जिसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया और इसी की वजह से स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के संकल्पों ने पूरी दुनिया में अपने लिए जगह बनाई।

यहां क्लिक करें

हरजिंदर | वरिष्ठ पत्रकार

अर्थव्यवस्था की सेहत अंत में उपभोक्ता बाजार से आने वाली खबरों से ही तय होती है। लोग जब झोला उठाकर बाजार पहुंचते हैं और देर सारा सामान खरीदकर लौटते हैं, तो वे देश की आर्थिक नींव की मजबूती भी तय कर देते हैं। आधुनिक दौर में किसी भी राष्ट्र की समृद्धि से लेकर उसके समाज के स्थायित्व तक के बहुत सारे फैसले बाजार की रौनक से ही तय होते हैं। यहां इतनी बड़ी भूमिका सिर्फ इस बात को बताने के लिए जरूरी थी कि पिछले कुछ समय से हमारे बाजार से जो खबरें आ रही हैं, वे बहुत अच्छी नहीं हैं।

उपभोक्ता सामान बनाने वाली ज्यादातर कंपनियों के पिछली कुछ तिमाही के नतीजे यही कह रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क ऑटोमोबाइल उद्योग के मामले में दिखता है, जहां कारों की बिक्री काफी तेजी से गिरी है। सात लाख से ज्यादा नई अनबिकी कारें गोदामों में जंग खा रही हैं। बाकी उपभोक्ता सामान के बाजार का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। कुछ ही समय पहले उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के चेयरमैन ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए यह बताया था कि पिछले आठ साल में उनकी सबसे कम बिक्री सितंबर में खत्म होने वाली तिमाही में हुई। तब तक कुछ ऐसी ही बातें और कंपनियों की तरफ से भी आ चुकी थीं, लेकिन नेस्ले इंडिया के चेयरमैन ने आगे जो कहा, उससे आर्थिक जगत में एक नई बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा, लगता है कि इस देश के मध्य वर्ग ने खर्च करना कम कर दिया है। उन्होंने इसमें यह भी जोड़ दिया कि शायद भारत में मध्य वर्ग का आकार सिकुड़ रहा है।

अब तमाम अर्थशास्त्री, नीति-निर्माता और कॉरपोरेट जगत के धुरंधर इस पहेली में सिर खपा रहे हैं कि क्या सचमुच मध्य वर्ग का आकार सिकुड़ रहा है? यह तर्क ध्यान देने लायक इसलिए है कि बाजार में जो हो रहा है, उसकी सबसे अच्छी व्याख्या इसी से हो सकती है। मध्य वर्ग का आकार सिकुड़ रहा है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो मध्य वर्ग की आबादी कम हो रही है, यानी देश में पहले मध्य वर्ग में जितने लोग थे, अब उससे कम होते जा रहे हैं। दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, उस रफ्तार से मध्य वर्ग के लोग नहीं बढ़ रहे, यानी मध्य वर्ग के लोगों का प्रतिशत कम हो रहा है। या कुछ हद तक दोनों ही बातें हो रही हों।

वैसे मध्य वर्ग के मुरझाते जाने की यह चिंता सिर्फ भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की है। तीन साल पहले अमेरिकी शोध संस्था प्यू रिसर्च ने मध्य वर्ग का हाल जानने के लिए एक सर्वे किया था। उसने पाया था कि भारत समेत पूरी दुनिया में मध्य वर्ग सिकुड़ रहा है। उस समय अर्थव्यवस्थाओं, उपभोग और आर्थिक अवसरों के महामारी से लगा झटका जारी था और इसे महामारी का असर ही मान लिया गया। अमेरिका में तो मध्य वर्ग इसके बहुत पहले ही तेजी से कमजोर पड़ने लग गया था। तब कहा गया था कि वहां मध्य वर्ग के लिए जो नौकरियां थीं, उनको 'आउटसोर्स' करने का यह नतीजा है। इन तर्कों से उपजी राजनीति ने ही डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता दिए। मगर अमेरिका से ज्यादा दुनिया की चिंता भारत में मध्य वर्ग के कमजोर होने को लेकर है, क्योंकि भारत के मध्य वर्ग की विशाल आबादी दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है।

यह मध्य वर्ग भारत के लिए या फिर पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कारण जितने आर्थिक हैं, उससे ज्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक हैं। पहले बात करते हैं आर्थिक कारण की। परिभाषाओं को अगर थोड़ी देर के लिए विराम दे दें, तो हम समाज के उस तबके को मध्य वर्ग मानते हैं, जिसकी कमाई इतनी होती है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी उसके पास कुछ अन्य चीजों पर खर्चने के लिए धन बच जाता है। इसका इस्तेमाल वह कहीं अपनी इच्छानुसार करता है, तो कहीं अपने सपनों के अनुसार। कहीं वह इसे अपने शौक के हिसाब से खर्च करता है, तो कहीं जमाने की रीत और देख पराई चुपड़ी जैसे लालच उसके धन को अपनी ओर खींचते हैं। जो हम विज्ञापन देखते हैं, दुकानें देखते हैं, रंगे-सजे बाजार देखते हैं, अनंत तरह के उत्पाद देखते हैं, टूर पैकेज देखते हैं, मनोरंजन के भारी-भरकम उद्योग देखते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखते हैं, ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट देखते हैं- ये सब बहुत हद तक मध्य वर्ग के इसी अतिरिक्त धन की माया है। बहुत बड़ा बाजार सिर्फ इसी सहारे खड़ा है और जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा भी सीधे या परोक्ष रूप से इसी से उपजता है।

मगर मध्य वर्ग का महत्व सिर्फ अर्थव्यवस्था का आधार होने में नहीं है। मध्य वर्ग आधुनिक सभ्यता, संस्कृति और राजनीति की नींव भी तैयार करता है। यह मध्य वर्ग ही था, जिसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया और इसी की वजह से स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के संकल्पों ने पूरी दुनिया में अपने लिए जगह बनाई। यह मध्य वर्ग ही था, जिसने दुनिया को समाजवाद जैसे सपने दिए और लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम को देख लीजिए, इसका अमूमन नेतृत्व मध्य वर्ग से ही आया था। पूरे मानव इतिहास में मध्य वर्ग जैसी बदलाव की कोई दूसरी इतनी बड़ी ताकत कभी नहीं रही। क्या अब हम बदलाव की इस ताकत से हाथ धोने जा रहे हैं?

अमेरिका को छोड़ दें, तो बाकी दुनिया में हालात शायद अभी उस हद तक नहीं पहुंचे कि मध्य वर्ग को लेकर कोई भविष्यवाणी की जाए। मगर कुछ डर जरूर उपजे हैं, जो चिंता पैदा कर रहे हैं। इन डर का कारण है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई। एआई कृषि और उद्योगों में मदद जरूर कर सकता है। कुछ हद तक इससे नए तरह का ऑटोमेशन भी हो सकता है, लेकिन यह न तो खुद किसानी कर सकता है और न मजदूरी। हालांकि, यह उन ज्यादातर कामों को कर सकता है, जो आमतौर पर मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोग करते हैं। इसी से यह डर पैदा हुआ है कि कहीं एआई मध्य वर्ग को खत्म तो नहीं कर देगा?

मामला थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि मध्य वर्ग के खत्म होने का मतलब होगा एक बड़े बाजार का खत्म हो जाना। क्या एआई में निवेश करने वाले इस हद तक जा सकते हैं?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

रैगिंग रोकने के लिए छात्रों में बंधुत्व भाव जगाना जरूरी

यहां क्लिक करें

हरिवंश चतुर्वेदी | महानिदेशक, आईआईएलएमईएस

गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक आदि देश के कई हिस्सों में इन दिनों रैगिंग की एक के बाद दूसरी घटनाएं सामने आई हैं। साल 1997 में पहली बार तमिलनाडु ने रैगिंग के खिलाफ कानून बनाए थे और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश में यूजीसी ने देश भर के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। साल 2016 में तो उसने अपने इन दिशा-निर्देशों को और अधिक सख्त बना दिया। बावजूद इसके कहा जाता है कि उदारीकरण के बाद जिस तेजी से देश में उच्च व तकनीकी शिक्षा का प्रसार हुआ, उसी अनुपात में रैगिंग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। जाहिर है, हमने अब तक जो भी प्रयास किए हैं, उसका आंशिक असर ही पड़ा है।

अभी देश के तमाम महाविद्यालयों-विश्वविद्यालयों में 4.5 करोड़ विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। जब उनका दाखिला होता है, तब उनसे बाकायदा एक 'अंडरटेकिंग' (वचन-पत्र) ली जाती है कि वे रैगिंग में संलिप्त नहीं होंगे। इसके अलावा, हरेक कॉलेज-यूनिवर्सिटी में रैगिंग को रोकने के लिए कमेटी बनाई जाती है और उसके अधिकारियों के नाम कैंपस में जहां-तहां प्रदर्शित किए जाते हैं, ताकि परेशान छात्र अपनी समस्या उनको बता सके। बीते ढाई दशक में केंद्र व राज्य के स्तर पर तमाम तरह के प्रावधान लागू किए जा चुके हैं, फिर भी यदि रैगिंग की घटनाएं नहीं रुक पा रहीं, बल्कि कुछ मामलों में तो पीड़ित विद्यार्थी की जान भी जा रही है, तो साफ है कि सिर्फ कानूनी तरीके से इस मसले का स्थायी हल नहीं निकाला जा सकता।

रैगिंग की जड़ों को काटने के लिए सबसे पहला काम जागरूकता फैलाने का होना चाहिए। यही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि उनका काम खाली डण्डे के जोर से कानून और व्यवस्था की रक्षा करना नहीं है, बल्कि वे ऐसे वर्दीधारी नागरिक हैं, जिन्हें जनता के दु:ख-सुख का साथी बनना, लोगों की मदद करना तथा सहानुभूति के साथ उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। ''हमारे जैसे देश में, जहां लोग बहुत सीधे-सादे और अपढ़-अनजान हैं'', श्री नलिनी रंजन सरकार कहते हैं, ''पुलिस वालों को सत्ता की शान दिखाने के बजाय लोगों की मदद करने और सहानुभूतिपूर्वक उनका मार्गदर्शन करना चाहिए।'' संक्षेप में श्री सरकार का कथन है कि आजादी के बाद पुलिस वाले जनता से भिन्न नहीं रह सकते। कानून और व्यवस्था के पालन के साथ-साथ जरूरत के वक्त वे लोगों की सेवा और सहायता करें। गवर्नर डा. काटजू कहते हैं कि पुलिस वाले अपने को गरीबों का सेवक समझें और निष्पक्ष, ईमानदार तथा मृदुभाषी बनें।

रैगिंग का बढ़ना संकेत करता है कि कैंपस में 'सांस्कृतिक बदलाव' जरूरी है। छात्रों को सजग बनाने की जरूरत है।

ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में ऐसे मामले सामने नहीं आते। वहां ऐसे मामलों को 'हैजिंज' कहा जाता है। वहां तो कभी-कभी ऐसे मामले काफी वहशियाना रूप ले लेते हैं। मुझे यहां स्वदेश दीपक की कहानी *कोर्ट मार्शल* याद आ रही है, जिसमें एक फौजी अफसर दलित जातियों से आने वाले सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार करता है और एक जवान को मां की गाली देता है। नतीजतन, आवेश में आकर वह सैनिक उस अफसर की हत्या कर देता है, जिसके बाद उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। कहानी का अंत कुछ यूं है कि अदालत में जज उस जवान की बातें सुनकर भावुक हो जाता है और न सिर्फ उसको रिहा कर दिया जाता है, बल्कि उस अफसर को भी दंडित किया जाता है, जो उसकी शिकायत को नजरंदाज कर चुका था। कहने का मतलब यह है कि हमें समन्वय में प्रयास करना होगा। कानूनी सख्ती, सामाजिक जागरूकता, छात्रों का मानसिक विकास तो जरूरी है ही, साथ-साथ कैंपस में 'कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन' (सांस्कृतिक बदलाव) भी आवश्यक है। सीनियर छात्रों को जूनियर के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। इसके लिए उनको संयुक्त प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं या साथ-साथ किसी आयोजन की जिम्मेदारी डाली जा सकती है। कुछ शिक्षण संस्थानों में ऐसा हो रहा है, जो काफी सफल साबित हुआ है। ऐसे प्रयोग हमें सत्र की शुरुआत में तमाम जगहों पर करने चाहिए। हमें विद्यार्थियों में बंधुत्व और बराबरी की भावना जगानी ही होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

हर क्षण अतीत से हटिए

जो अनुभव आप बार-बार कर चुके, वे बासी हो जाते हैं। यूं तो प्रकृति कभी बासी नहीं होती, मन बासी होता है, क्योंकि उस पर यादों की इतनी परतें जम जाती हैं कि उस धूल को हटाकर नए को देखना बड़ा मुश्किल होता है। दिल तरोताजा हो, तो वही पेड़, वही झरने, वही आकाश और वही लोग नए मालूम होते हैं। इसके लिए एक नई तरह की आंख विकसित करनी होगी। जैसे बच्चे हर बात से चमत्कृत होते हैं, तितली हो, फूल हो या चिड़िया, उन्हें हर बात नई मालूम होती है।

तंत्र की एक ध्यान विधि है कि हर चीज को ऐसे देखें, जैसे पहली बार देख रहे हैं। किसी भी छोटी सी ऐसी चीज से शुरुआत कर सकते हैं, जिस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे, अपने जूतों को देखें। आप महीनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनको ध्यान से देखा? हम केवल नई चीजों को खरीदते समय ध्यान से देखते हैं, क्योंकि तब हमें पैसे खर्च करने होते हैं। एक बार घर में आ गए कि व्यक्ति हो या वस्तु, उसे देखना बंद कर देते हैं। इसलिए ओशो कहते हैं, अपने जूते से शुरुआत करो। दरअसल, जूते सबसे अंतिम चीज हैं, जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। जूतों को ऐसे देखो, जैसे पहली बार देख रहे हो और अपने भीतर फर्क देखो : आपकी चेतना की गुणवत्ता अचानक बदल जाती है। चित्रकार विन्सेंट वान गाग ने पुराने जूतों की पेंटिंग बनाई है। वह पुरानी चीजों के बाजार में जाकर सबसे घिसे, फटे जूते ले आए। यह सबसे अजीब विषय है, जिसकी कला बन सकती है, लेकिन इस पर असाधारण चित्र बना और वह चित्र मिलियन डॉलर में बिका।

यह ध्यान विधि आपकी आंखों को ताजा बनाने के लिए है। यह तभी मुमकिन है, जब आप अंदर से अतीत के अनुभवों के संग्रह को खाली करते जाएं। हर चीज को ऐसे देखें, जैसे पहली बार देख रहे हों, तो कभी-कभी आपको आश्चर्य होगा कि आप कितनी खूबसूरत दुनिया को खो रहे थे?

अचानक जागरूक होकर अपनी पत्नी या पति या मित्र को ऐसे देखें, जैसे उसे पहली बार देख रहे हों।

अंदर से अतीत के अनुभवों के संग्रह को खाली करते जाएं। हर चीज को ऐसे देखें, जैसे पहली बार देख रहे हों, तो आपको आश्चर्य होगा कि आप कितनी खूबसूरत दुनिया को खो रहे थे?

किसी साधारण वस्तु को ऐसे देखें, जैसे कि पहली बार देख रहे हों। इस तरह आप अपनी निर्मल शिशुवत दृष्टि वापस पा लेंगे। आपका यह देखना बिल्कुल अलग किस्म का होगा, आपको दिल की आंखों से देखने की कला सीखनी होगी। आप जिस चीज के पास से गुजर रहे हों, उसे ऐसे देखे, जैसे पहली बार देख रहे हों। हर चीज को ऐसे छूएं, जैसे पहली बार स्पर्श कर रहे हैं। यदि ऐसा कर सके, तो आप पुराने बोझ से मुक्त हो जाएंगे। हर क्षण अतीत से हटिए, धीरे-धीरे आपका वर्तमान के साथ जुड़ाव हो जाएगा।

अमृत साधना

शेखर कपूर | फिल्म निर्देशक

हममें से सबसे प्रतिभाशाली लोग सीखेंगे कि एआई का उपयोग कैसे करना है। मेरा अनुमान है कि युवा भारतीय इसे अपना लेंगे और पांच वर्षों में ही वे हमारे जीडीपी में एक ट्रिलियन डॉलर का इजाफा कर देंगे।

ऐसी नीलामी से उत्पाद जान पड़ते खिलाड़ी

अनुलोम-विलोम
आईपीएल नीलामी

क्या जमाना आ गया है! वस्तु, घर, कबाड़ आदि तो नीलाम होते जरूर सुने व देखे जाते रहे, लेकिन आईपीएल जैसे खेल आयोजनों ने तो खिलाड़ियों को भी एक उत्पाद बना दिया। उनकी इस कदर बोली लगती है, मानो उनकी बीच बाजार में बेचा जा रहा हो। जिस कद के क्रिकेटर, उसी तरह के दाम। कोई करोड़ों में बिकता है, तो कोई लाखों में और कोई हाथ मलते रह जाता है। इस नीलामी में उसे कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। पहले क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने को लेकर उत्साह रहा करता था, लेकिन अब तो खिलाड़ियों की खरीद-बिक्री देखने में। हालांकि, यह काम अमीर लोग ही करते हैं, हम-आप जैसे साधारण लोग तो उनकी बिक्री देखकर ही खुश हो जाते हैं। वह जमाना चला गया, जब किसी के हाथ किसी के बिकने को बुरा माना जाता था। अब तो बिकना शान माना जाता है और जो खिलाड़ी सबसे अधिक कीमत पर बिकता है, उसकी शान में उतने कसीदे पढ़े जाते हैं। इस नीलामी में जो बिक जाता है, वह तो समझो किस्मत वाला होता है। उसे लाखों-करोड़ों रुपये मिल जाते हैं और जो नहीं बिक पाता, वह बेचारा अपनी किस्मत को रोता रहता है। उसे बाकी खिलाड़ी भी मानो गैर की नजर से देखते हैं। खैर, जो भी हो, किंतु वक्त अब बदल गया है और कभी नीलामी को (विशेषकर व्यक्ति या घर की) ठीक नहीं समझा जाता था, किंतु आज सभी खिलाड़ी नीलामी को लेकर लालायित रहते थे। पाकिस्तान की तो शिकायत भी यही है कि उसके खिलाड़ियों को आईपीएल अब केवल मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू का खेल बन चुका है। इसकी चमक-दमक हमें वास्तविक क्रिकेट से दूर करती जा रही है।

कोमल शर्मा, टिप्पणीकार

इसमें नीलाम होकर भी सम्मान मिलता है, जो खिलाड़ियों को गर्व का एहसास देता है। नीलाम से सम्मान और इनाम, दोनों मिलते हैं खिलाड़ियों को।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

ब्रांड वैल्यू का खेल

ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी का आईपीएल में 27 करोड़ में बिकना सबसे बड़ा मजाक है। हालिया प्रदर्शन में लगातार फेल रहने वाले खिलाड़ी को इतनी रकम देना पैसे की बर्बादी है। पंत का नाम और प्रचार उनका असली खेल छिपा रहा है। यह डील क्रिकेट के मेहनती खिलाड़ियों के साथ अन्याय है और साबित करती है कि आईपीएल अब केवल मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू का खेल बन चुका है। इसकी चमक-दमक हमें वास्तविक क्रिकेट से दूर करती जा रही है।

कोमल शर्मा, टिप्पणीकार

आईपीएल ने खिलाड़ियों की किस्मत बनाई

आईपीएल के तहत खिलाड़ियों की होने वाली नीलामी को हलके में लेना गलत होगा। ऐसे आयोजन कितने खिलाड़ियों को उनके दुखों से उबार चुके हैं, यह कहना मुश्किल है। कुछ नाम तो सीधे-सीधे याद आते हैं, जैसे- रिंकू सिंह। उनके पिता दूसरों के घर पर एलपीजी सिलेंडर पहुंचाते थे, पिता का कर्ज उतारने के लिए खुद रिंकू ने कभी साफ-सफाई का काम किया था, लेकिन आईपीएल का कमाल ऐसा हो गया है कि आज उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। इसी तरह का एक और नाम है यशस्वी जायसवाल। उन्होंने 10 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, कभी गोलगप्पे बेचे, तो कभी भूखे पेट सोए, लेकिन आज वह धमाल मचा रहे हैं। इसी तरह, ध्रुव जुरेल ने क्रिकेटर बनने के लिए काफी संघर्ष किया, जबकि चेतन सकारिया की हालत तो इतनी खराब थी कि इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। मगर आज ये दोनों सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। ये तो चंद नाम हैं, अगर आईपीएल खेलने वाले सभी खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि खंगालें, तो कई नाम ऐसे मिल जाएंगे, जिन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया है। ऐसे में, उनकी नीलामी को सिर्फ नीलामी नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनके लिए यह किस्मत खुलने का दरवाजा है, जिसको पार करके वे क्रिकेट प्रशंसकों के दिल में अपनी जगह बना चुके हैं।

वास्तव में, आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट ही नहीं, यहां के क्रिकेटरों की भी तस्वीर संवारी है। इससे एक से बढ़कर एक क्रिकेटर हम देखने लगे हैं। पहले जहां नेशनल टीम ही एकमात्र ऐसी जगह होती थी, जिसमें अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद होती थी, वहीं अब आईपीएल जैसे आयोजनों में कई टीमों के होने से क्रिकेटरों के लिए अवसर भी काफी बढ़ गए हैं। अच्छी बात यह भी है कि इसमें उनको कमाई भी हो रही है। आईपीएल में चौकों-छक्कों के साथ बरसते पैसे खिलाड़ियों को नाम और काम, दोनों कमाने के अवसर देते हैं। इनमें जो फायदा उठा लेता है, वह सफलता के क्षितिज पर चमकने लगता है और अगली नीलामी में उसकी रकम भी बढ़ जाती है, जबकि जो शिथिल पड़ जाता है, उसे खरीदार तक नहीं मिल पाता। इस बार भी आईपीएल नीलामी में कई बड़े नामों को भी खरीदार यदि नहीं मिले, तो इसका कारण उनका कमजोर प्रदर्शन ही है। कुल मिलाकर, एक अच्छे आयोजन के हम गवाह बनने जा रहे हैं। उम्मीद है, इस बार की नीलामी में जिन खिलाड़ियों पर अधिक बोली लगी है, वे अपने को कहीं बेहतर साबित कर सकेंगे और अपनी-अपनी टीम को जीत दिला सकेंगे।

सुजीत कुमार, टिप्पणीकार

चिंतन

2030 तक एड्समुक्त भारत कठिन चुनौती

सरकार की ओर से व्यापक स्तर पर जागरूकता और स्वास्थ्य कार्यक्रम का असर है कि देश में एड्स से जुड़ी मौतों में 79 प्रतिशत की कमी आई है, और नए मामले 44 फीसदी घटे हैं। विश्व एड्स दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने वर्ष 2030 तक एड्स के खात्मे के यूएन के सतत विकास लक्ष्य के प्रति भारत की तेज प्रगति का ब्योरा दिया है। नब्बे के दशक से भारत सरकार एचआईवी/एड्स के खतरों व बचाव के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएन एड्स की पहल पर वर्ष 1988 से एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इस दिन इस बीमारी के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाई जाती है। भारत शुरू से एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम में शामिल है। इस बार इंदौर में एड्स दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस बार की थीम 'टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट' है, इस थीम पर आगे बढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ष 2030 तक एड्स को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया गया है, हालांकि समाज में खासकर महानगरों में यौन संबंधों को लेकर खुलापन आने, मल्टीपार्टनर कल्चर पनपने, ड्रग्स के अधिक प्रयोग व टैटू कल्चर में वृद्धि से एचआईवी के खतरे बढ़े ही हैं। ऐसे में लक्ष्य मुश्किल लग रहा है, वर्ष 2030 तक एड्स मुक्त भारत कठिन चुनौती होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अभी देश में करीब 17.30 लाख लोग एड्स के साथ जी रहे हैं। यूएन लक्ष्य पाने के लिए भारत सरकार जांच और चिकित्सा के नवीन उपाय अपनाएगी, '95-95-95' के फॉर्मूले पर चलेगी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017 को पूरी तरह लागू करेगी। '95-95-95' फॉर्मूले का मतलब है देश के 95 प्रतिशत मरीजों को पता होना चाहिए कि वे एचआईवी से संक्रमित हैं, 95 प्रतिशत मरीजों को इलाज मिलना चाहिए और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की दवाओं के जरिये 95 प्रतिशत मरीजों का 'वायरल लोड' घटाया जाना चाहिए। फिलहाल देश के 81 प्रतिशत मरीजों को पता है कि वे एचआईवी से संक्रमित हैं, 88 प्रतिशत मरीजों का इलाज किया जा रहा है और 97 प्रतिशत मरीजों का वायरल लोड घटाया जा चुका है। 0.70 प्रतिशत वैश्विक आबादी में एड्स का प्रसार है, जबकि भारत में यह 0.20 फीसदी के स्तर पर है। एड्स के खिलाफ लम्बी लड़ाई के बाद इस बीमारी के खिलाफ देश में मजबूत चिकित्सा तंत्र विकसित किया गया है, संक्रमितों को एड्स की दवा मुफ्त में दी जा रही है और किसी मरीज के एचआईवी संक्रमित पाए जाते ही उसे दवा देने का प्रावधान किया है। आज भारतीय दवा कंपनियां अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को एड्स की सबसे सस्ती और प्रभावी दवाओं की आपूर्ति कर रही हैं। शुरू में एस संक्रमण से बचाव के लिए कोई खास दवा नहीं थी। आज बहुत सारी दवाएं हैं, जिनसे पीड़ितों को मदद मिलती है। फिर भी बचाव सबसे सुरक्षित दवा है। फैशन में चल रहे शरीर पर टैटू (गोदना) बनवाते वक्त एहतियात बरतें, मल्टी पार्टनर यौन संबंध से परहेज करें, प्रोटेक्शन का प्रयोग करें, रक्त के प्रयोग में सावधानी रखें, इन उपायों से इस संक्रमण से बचा जा सकता है। आज विश्व एड्स दिवस पर इससे बचाव के प्रति संकल्पित होना जरूरी है। साथ ही एड्स के साथ जी रहे लोगों के प्रति संवेदनशील रवैया अख्तियार करते हुए उनके मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिए। एचआईवी को लेकर टैबू और भ्रांतियां भी समाप्त होने चाहिए। एड्स मुक्त भारत बड़ी उपलब्धि होगी।

दिवस विशेष

योगेश कुमार गोयल

देश में नासूर बन रहा प्रदूषण का बढ़ता स्तर

प्रदूषण को लेकर उद्योगों को जागरूक करने तथा लोगों में प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 2 दिसम्बर को 'राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मूल उद्देश्य देश में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों की आवश्यकता की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। वास्तव में यह दिन 1984 की उस भयानक गैस त्रासदी की घटना के कारण पीड़ित हुए लोगों के निर्दोष जीवन को याद करने के लिए चिह्नित किया गया है, जिसमें हजारों लोग भोपाल की यूसीआईएल फैक्टरी से मिथाइल गैस के हुए रिसाव के कारण मौत की नींद सो गए थे। इस दिन विशेष रूप से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है तथा देश में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में भी लोगों को बताया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को प्रदूषण को रोकने में मददगार विभिन्न कानूनों के बारे में लोगों को अधिकाधिक जागरूक करना है। हालांकि औद्योगिक प्रदूषण की जांच के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एनपीसीबी) बनाया हुआ है, जो यह जांच करता है कि उद्योगों ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन किया है या नहीं लेकिन इसके बावजूद देश में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर आज भी स्थिति कितनी विकराल है, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। कल-कारखानों एवं फैक्टरियों से निर्बाध रूप से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन वायु प्रदूषण के स्तर को दिनों-दिन बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन की विभिन्न चुनौतियां दुनिया के सामने खड़ी हो रही हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए दुनियाभर के देश वैश्विक उपाय कर रहे हैं लेकिन ये उपाय भी तक नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। घातक किरणों से धरती की सुरक्षा करती ओजोन परत में छेद के लिए वायु प्रदूषण को ही जिम्मेदार माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार वायु प्रदूषण विश्वभर में प्रतिवर्ष करीब सत्तर लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है। आंकड़ों के अनुसार स्थिति इतनी खराब है कि वायु में मौजूद प्रदूषक हवा के जरिये सीधे शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों, मस्तिष्क तथा हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं और दस में से नौ लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नहीं मिलती। भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार भयावह हो रही है। प्रदूषण अब इस कदर नासूर बनता जा रहा है कि पिछले कुछ समय से इस मामले में बार-बार देश की सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण स्तर पर तो सुप्रीम कोर्ट कई बार कड़ी नाराजगी जताते हुए कड़े निर्देश दे चुका है लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। हालांकि वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा करीब डेढ़ महीने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप के तहत कार्रवाई की जा रही है और अभी भी ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू हैं किन्तु इसके बावजूद वायु प्रदूषण पर लगाम कसने में सफलता नहीं मिल रही। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि दुनियाभर में करीब चार अरब लोग खाना पकाने के लिए आज भी लकड़ी, कोयला, केरोसिन ऑयल, गोबर इत्यादि ऐसे ईंधन पर निर्भर हैं, जो बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं और इनका गंभीर असर पर्यावरण के साथ-साथ खाना पकाने वालों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीच्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक बाहर तथा घर के अंदर लंबे समय तक वायु प्रदूषण के सम्पर्क में रहने के कारण स्ट्रोक, दिल का दौरा, डायबिटीज, फेफड़ों का कैंसर तथा जन्म के समय होने वाली बीमारियों इत्यादि की चपेट में आकर अब हर साल भारत में कई लाख लोगों की मौत हो रही है। वर्ष 2010 के बाद से पांच करोड़ से अधिक लोग घर के अंदर वायु प्रदूषण से पीड़ित हुए हैं। बच्चों पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को लेकर तो दुनियाभर में अनेक शोध किए जा चुके हैं और सभी का निष्कर्ष यही है कि प्रदूषण बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जिसके चलते प्रतिवर्ष लाखों बच्चे असमय ही काल का ग्रास बन जाते हैं और करोड़ों बच्चे मासूम उम्र में ही तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि वायु प्रदूषण बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर इसका समय पर वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं तो पूरी जिंदगी बनी रह सकती हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार तथा पर्यावरण मामलों के जानकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

दो टूक

प्रभात कुमार रॉय

बांग्लादेश में महफ़ूज़ नहीं हिन्दू

बांग्लादेश में आजकल जो हुकूमत सत्तासीन है, उसका उदारवादी चेहरा भले ही नोबेल पीस प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस हैं, किंतु सत्ता की वास्तविक कमान जमात ए इस्लामिया और बांग्लादेश के इस्लामी फौजी हुक्मरानों के हाथों में है। जिस दिन से शेख हसीना सत्ता से बेदखल की गई है और बांग्लादेश की राजसत्ता इस्लामी कट्टरपंथियों के हाथों में आई गई है, उसी रोज से ही नृशंस कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर, उनके मंदिरों पर, उनके मकानों पर और उनके कारखानों पर निरंतर नृशंस आक्रमण किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की कथित अंतरिम सरकार दुर्दांत कट्टरपंथी हमलावरों पर कोई भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में एकदम नाकामयाब सिद्ध हुई है।

बांग्लादेश में शेख हसीना को हुकूमत से बेदखल किए हुए तकरीबन एक सौ ग्यारह दिन बीत चुके हैं। बांग्लादेश की अंतिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पीस प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथ में सौंपा गया, जिन्हें अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार मनोनीत किया गया। 25 सितंबर को मोहम्मद यूनुस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम 'क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव' में शिरकत करने के लिए अपने स्पेशल असिस्टेंट महफूज आलम के साथ अमेरिका पधारे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से मोहम्मद यूनुस द्वारा महफूज आलम का बाकायदा परिचय कराया गया। महफूज आलम वही शख्स है, जोकि शेख हसीना की हुकूमत के विरुद्ध छात्रों द्वारा संचालित किए गए आंदोलन का सर्वोच्च लीडर रहा था। महफूज आलम को बांग्लादेश की अंतरिम हुकूमत में स्पेशल सेक्रेटरी का उच्च प्रशासनिक ओहदा प्रदान किया गया है। महफूज आलम वस्तुत वर्ष 2015-16 में ढाका यूनिवर्सिटी में कानून विभाग का छात्र रहा था। सरकारी नौकरियों में अवामी लीग से संबंधितों को आरक्षण प्रदान किए जाने के विरुद्ध प्रारंभ किए गए ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों के जबरदस्त अभियान का महफूज आलम लीडर रहा। इस बात का दावा पेश किया जा रहा है कि महफूज आलम एक आतंकवादी इस्लामी तंजीम हिजबुल तहरीर से जुड़ा शख्स है। इस सनसनीखेज दावे के विरुद्ध महबूब आलम ने बयान दिया कि वह आतंकवादी हिजबुल तहरीर से नहीं बल्कि इस्लामी छात्र शिविर से जुड़ा हुआ छात्र नेता है। उल्लेखनीय है कि इस्लामी छात्र शिविर वस्तुतः बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात ए इस्लामिया का छात्र संगठन रहा है। बांग्लादेश में आतंकवादी तंजीम हिजबुल तहरीर भी जमाते इस्लामी का एक आतंकवादी मिलिटेंट विंग रहा है। सर्वविदित है कि शेख हसीना हुकूमत का तख्ता पलटने के पीछे कट्टरपंथी जमात ए इस्लामिया का स्पष्ट तौर पर सीधा हाथ रहा। बांग्लादेश में आजकल जो हुकूमत सत्तासीन है, उसका उदारवादी चेहरा भले ही नोबेल पीस प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस हैं, किंतु सत्ता की वास्तविक कमान जमात ए इस्लामिया और बांग्लादेश के इस्लामी फौजी हुक्मरानों के हाथों में है। जिस दिन से शेख हसीना सत्ता से बेदखल की गई हैं और बांग्लादेश की राजसत्ता इस्लामी कट्टरपंथियों के हाथों में आई गई है, उसी रोज से ही नृशंस कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर, उनके मंदिरों पर, उनके मठों पर, उनकी दुकानों पर, उनके मकानों पर और उनके कारखानों पर निरंतर नृशंस आक्रमण किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की कथित अंतरिम सरकार दुर्दांत कट्टरपंथी हमलावरों पर कोई भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में एकदम नाकामयाब सिद्ध हुई है। बांग्लादेश में इस्कॉन से संबंधित संत चिन्मय कृष्ण दास को हाल ही में देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। 8 साल के चिन्मय कृष्ण दास के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। चिन्मय कृष्णदास पर हल्लाम आयद किया गया कि 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का उनके द्वारा अपमान किया गया। हिंदू-बौद्ध-क्रिश्चियन एकता परिषद के नेता राणा दासगुप्ता का दावा

है कि चिन्मय कृष्ण दास के ऊपर एकदम झूठा केस आयद किया गया है। चिन्मय कृष्णदास की जमानत को अदालत द्वारा तब खारिज कर दिया गया, जब उनकी समर्थक उत्तेजित भीड़ के कुछ लोगों द्वारा असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सैफुल इस्लाम अलिक्र का कत्ल कर दिया गया। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक सख्त बयान जारी कर कहा कि चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी और जमानत नामंजूर करने पर हम गहरी चिंता जाहिर करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में बांग्लादेश की हुकूमत से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की हिफाजत को सुनिश्चित करने की अपील भी की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि बेहद निराशाजनक और गहरी पीड़ा की बात है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को भारत सरकार ने गलत तरीके से पेश किया है, क्योंकि चिन्मय कृष्णदास को विशेष आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस तरह भारत के बेखुनियाद कूटनीतिक बयानों से दोनों पड़ोसी देशों के मध्य दोस्ती और आपसी समझदारी की भावना का हनन हो रहा है। उपरोक्त तथ्यों से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि बांग्लादेश और भारत के मध्य कूटनीतिक कटुता किस कदर और किस हद तक बढ़ चुकी है। यहां तक कूटनीतिक रिश्ते ध्वस्त हो जाने के कगार तक आ गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य यूनुस सरकार के सत्तासीन होने के बाद नजदीकियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। यह सब बांग्लादेश हुकूमत पर जमात ए इस्लामी तंजीम का निर्णायक प्रभाव स्थापित हो जाने का सीधा नतीजा है। सन् 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के तत्पश्चात विगत हफ्ते पहली दफा पाकिस्तान से बांग्लादेश का समुद्री संपर्क प्रारंभ हुआ है। पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज कराची के तट से चलकर बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित चटगांव बंदरगाह जा पहुंचा। इससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य समुद्री व्यापार सिंगापुर अथवा कोलंबो के माध्यम से होता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा हासिल करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। उल्लेखनीय है कि जनरल जिया उल हक़ के शासनकाल के दौर से ही कट्टरपंथी जमात ए इस्लामिया का निर्णायक प्रभाव पाकिस्तान की हुकूमत पर और उसकी फौज पर स्थापित हो चुका था। इसी कारण से पाकिस्तान वस्तुतः नृशंस वैश्विक जिहादियों को प्रश्रय और परवरिश प्रदान करने वाला सबसे अहम मुल्क निर्मित हुआ। फौजी डिक्टेटर जिया उर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का निर्माण किया, जिनकी हत्या के बाद उनकी पार्टी का नेतृत्व बेगम खालिदा जिया ने संभाला और सत्तासीन रही। बेगम खालिदा जिया को परास्त करके ही शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और लंबे दौर तक उन्होंने बांग्लादेश की राजसत्ता को शक्तिशाली तौर पर संभाला। अब बांग्लादेश की राजसत्ता वस्तुतः इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में आ गई है जोकि जालिमाना तौर पर अल्पसंख्यकों का जिंदगानियां ठीक उसी तरह दुश्वार कर रहे हैं, जिस तरह कभी पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा यही सब किया गया था। बांग्लादेश में आजकल 17 करोड़ आबादी है जिसमें तकरीबन आठ फीसदी हिंदू हैं। यदि बांग्लादेश की अल्पसंख्यक आबादी पर इसी तरह के जालिमाना जुल्म ओ सितम जारी रहे और हुकूमत ए बांग्लादेश इस तरह से मूकदर्शक बनी रही, तो फिर बांग्लादेश में भी हिंदुओं का क़ायम बना रहना, उसी तरह नामुमकिन हो जाएगा जिस तरह कभी पाकिस्तान में हुआ था।

(लेखक विशेष मामलों के जानकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

असंयम लक्ष्य विमुख कर देता हैं

संकलित

दर्शन

भगवान श्रीराम हर पल आत्मस्थिति में रहे। वे तनिक भी असंयमित नहीं हुए। असंयम लक्ष्य विमुख कर देता है। जब हम किसी से प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, तब उस व्यक्ति के गुण और उसके कार्यों को हम किसी और ढंग से देखते हैं। उसी व्यक्ति से जब हमारा राग होता है, तो हम उसके हर कार्य में श्रेष्ठता ही देखते हैं। द्वेष होने पर हम न्यूनता और दोषों को ही खोजते हैं। आसक्ति होने पर उसके प्रति हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने में भी तनिक संकोच नहीं करते हैं। हमारी यह इंद्धनुषीय दृष्टि और वृत्ति जब किसी पद और अधिकार प्राप्त व्यक्ति के साथ जुड़ जाती हैं, तब वह व्यक्ति विकार को और भी विकृत कर उसे व्यापक बना देता है, तब उस मनःस्थिति में निर्णय देने, सामाजिक व्यवहार करने में वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता हुआ स्वयं और समाज को गर्त में डाल देता है। श्रीरामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ ने श्रीभरत के अंदर तब इस त्रिपुटी की प्रधानता स्वीकारी, जब श्रीभरत भगवान की पादुकाओं को अपने सिर पर लेकर आए और गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि यदि आपका मंगलाशासन हो तो मैं पादुका रूप प्रभु को नंदीग्राम जाकर सिंहासनासीन कर वहीं से राज्य का कार्य संभाल लूंगा? तब गुरुदेव ने मानो भरत से यही कहा कि समुझव (समझ) के रूप में तुम्हारे अंदर विधायिका के गुण हैं, कहब (कथन) के रूप में न्यायपालिका के गुण हैं और करब (करनी) के रूप में कार्यपालिका के गुण हैं।

जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे?

संकलित

प्रेरणा

एक मछलीमार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई तो वह सोचने लगा... कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहां कोई मछली ही न हो! उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत-सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं! एक राहगीर ने जब यह नजारा देखा तो उससे कहा: लगता है भैया, यहां पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो! अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछलीमार ने हैरत से पूछा: क्यों, ऐसा क्या है यहां? राहगीर बोला: पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होने यहां मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनतीं। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यहीं होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। क्योंकि यह एक ही अनेक भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इन्द्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो.. इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लेवें बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी।

अंतर्मन

आज की पाती

लड़कियों का एनसीसी में प्रवेश समय की जरूरत

बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात' में युवाओं को एनसीसी में प्रवेश करने का आह्वान किया। इस दिन एनसीसी दिवस मनाया गया। नवंबर के हर दूसरे रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। जानकर बताते हैं कि वर्ष 1946 में एनसीसी की स्थापना हुई थी और लगभग दो वर्ष बाद वर्ष 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग में देशभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व और निस्वार्थ, एकता की भावना को जागृत करना और बढ़ाना भी है। यही नहीं, इसका मुख्य लक्ष्य युवाओं को सेना में कैरियर बनाने के लिए तैयार करना भी है। बहुत से युवा एनसीसी ज्वाइन करके अपने कैरियर के सपनों को पूरा भी कर रहे हैं।

– रचना त्यागी, दुर्ग

ट्रेंड

स्वयंसेवकों की भी जिम्मेदारी

समाज में अब जागरूकता आई है, एड्स के खिलाफ समाज ने लंबी लड़ाई लड़ी है। एड्स से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है ही, इसके साथ ही सामाजिक संगठनों और स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की भी बड़ी जिम्मेदारी तय होती है।

-जेपी नड्डा, अध्यक्ष, भाजपा

भारत की जीडीपी ग्रोथ

भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दो साल में सबसे नीचे 5.4% पर आ गई है। अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका फायदा विकसित-पुराने अहसाधियों को मिल रहा हो और किसान, मजदूर, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

दिल्ली से क्राइम रोकिए

अमित शाह जी, तुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली से क्राइम रोकिए। क्या तुझे रोकने से दिल्ली में आतंकवाद खत्म हो जाएगा? क्या दिल्ली में खुलेआम हाट-आउट होने बंद हो जाएंगे? क्या दिल्ली की महिलाएं, व्यापारी सुरक्षित हो जाएंगे?

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम नई दिल्ली

पत्रकारों की जिम्मेदारी

मनुष्यता और धरती को बचाने के लिए व्यावसायिक पत्रकारों की नैतिक जिम्मेदारी पहले से बहुत ज्यादा है। याद रहे कि कई तरह के दबावों, प्रलोभनों और खतरों के बीच निर्भीक, निष्पक्ष, स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता कर पाना आपकी धर्म परीक्षा है।

-कैलाश सत्यार्थी, बाल अधिकार कार्यकर्ता

करंट अफेयर

सोरेन ने आलू से लदे वाहनों को रोकने पर लिया संज्ञान

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की पश्चिम बंगाल से लगी सीमा पर आलू से लदे वाहनों को 'रोके जाने' का रविवार को संज्ञान लिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। वाहनों को रोके जाने से राज्य में आलू की आपूर्ति प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को तत्काल प्रभाव से मामले से निपटने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल के आलू व्यापारियों के एक संगठन के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू का भंडार बनाए रखने और राज्य में आलू की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए बृहस्पतिवार से आलू की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर कथित रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर तिवारी ने मामले के निपटारे के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से फोन पर बात की। बयान में कहा गया, 'पंत ने आश्वासन दिया है कि आलू आपूर्ति के मुद्दे को सुलझाने के लिए जल्द ही एक समिति गठित की जाएगी।' एक अधिकारी के अनुसार, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल द्वारा आलू की आपूर्ति सीमित कर दिए जाने के कारण झारखंड के खुदरा बाजार में पिछले दो दिनों में आलू की कीमत में पांच रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है।

ऑफ बीट

आंखों में संक्रमण हो जाए तो क्या करें

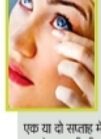

सबसे आम नेत्र संक्रमण, जैसे कि 'कंजंक्टिवाइटिस' आमतौर पर दृष्टि को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बिना उपचार के ठीक हो जाते हैं।

'कंजंक्टिवाइटिस' एक सामान्य स्थिति है जिसमें आपकी आंख का सफेद भाग गुलाबी या लाल हो जाता है। कंजंक्टिवाइटिस पीड़ित लोगों की आंखों में जलन होती है और पानी निकलता है। ठंडी, साफ पट्टी का इस्तेमाल करने और पलकों पर जमी पपड़ी को धीरे से पोंछने से आपकी आंखों को ठीक होने में मदद मिलती है। 'बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस' दूसरा सबसे आम रोग है। इसमें गाढ़ा पीला या हरा स्राव होने की आशंका अधिक होती है जो पलकों पर जम सकता है। यह आमतौर पर बिना इलाज के एक या दो सप्ताह में ठीक हो जाता है, लेकिन 'एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स' से इससे जल्द ही ठीक होने में मदद मिलती है। यदि आपकी आंखें वर्ष के कुछ समय में गुलाबी और खुजली वाली रहती हैं, तो संभवतः यह 'एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस' है। लगभग 40 प्रतिशत लोग किसी न किसी समय 'एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस' से पीड़ित होते हैं। 'कंजंक्टिवाइटिस' के इन सभी रूपों के लिए धूप का चश्मा और कृत्रिम आंसू मददगार साबित हो सकते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

5,800 करोड़ रुपये पीएलआइ स्कीम के तहत आवंटित किए गए केंद्र सरकार द्वारा बीत वर्ष 2023 और 2024 के बीच। इसी स्कीम के कारण में सरकार को केवल स्मार्टफोन निर्माण से एक लाख चार हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

शिवेश प्रताप
तकनीकी प्रकाशन सलाहकार

पीएलआइ स्कीम

प्रगति पथ पर अग्रसर स्मार्टफोन विनिर्माण

केंद्र सरकार ने हाल ही में देश की पीएलआइ योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाया है। इस योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इससे पीएलआइ से जुड़ी कंपनियों द्वारा 12.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ है। वहीं, इस पहल ने विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10 लाख नौकरियां सृजित की हैं। इसमें एक बात प्रमुखता से सामने आई है कि स्मार्टफोन निर्माण की दिशा में देश पिछले कुछ ही वर्षों में बहुत आगे निकल चुका है। इस स्कीम से देश की विनिर्माण एवं औद्योगिक क्षमताएं और अधिक मजबूत हो रही हैं, जिसे अनेक तथ्यों से समझा जा सकता है

केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से देश में स्मार्टफोन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बाद अब इनका निर्यात भी किया जा रहा है। फाइल

मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण क्रांति के रूप उभरता दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से स्मार्टफोन विनिर्माण के क्षेत्र में। यह योजना 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत आत्मनिर्भरता और भारतीय उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक निर्णायक कदम है। मोदी सरकार ने न केवल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सक्षम नीतियां बनाई, बल्कि इससे कंपनियों के लिए कार्यकुशलता, नवाचार और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही, सरकार की जिम्मेदार शासन प्रणाली और पारदर्शी नीतियों ने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया और सकारात्मक परिणाम प्रदान किए। सरकार का उद्देश्य था कि देश में अधिक से अधिक उत्पादों का निर्माण हो, जिससे न केवल आत्मनिर्भरता को बल मिले, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिले। यह योजना भारत की आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख कारक है, जो वैश्विक निवेश को आकर्षित कर रही है।

आइए पीएलआइ स्कीम के उद्देश्य और परिणामों का विश्लेषण करते हैं, ताकि यह समझा जा सके कि क्या वाकई में इस स्कीम के लक्ष्य पूरे हुए हैं और कितना फायदा हुआ है। पीएलआइ स्कीम के तहत, स्मार्टफोन निर्माण क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखा गया है, जिसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ निर्यात और रोजगार के अवसरों में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इस स्कीम ने भारत को एक वैश्विक उत्पादन हब के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस स्कीम के तहत निर्माताओं को जो प्रोत्साहन मिला, उससे भारतीय स्मार्टफोन उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिली।

प्रोत्साहन राशि से लाभ : पीएलआइ स्कीम में सरकार द्वारा उत्पादकों को इंसेंटिव दिया जाता है, जैसे कोई कंपनी मोबाइल फोन का बना रही है तो पीएलआइ स्कीम में उनको इंसेंटिव मिलता है। मान लीजिए अगर 25 हजार रुपये का मोबाइल फोन है और सरकार आपको 10 प्रतिशत पर इंसेंटिव यानें ढाई हजार रुपये सब्सिडी दे तो उस मोबाइल की लागत कम हो जाती है और कंपनियों के लिए यही प्रोत्साहन संजीवनी का कार्य करता है। साथ ही, यह स्कीम सरकार के लिए एक राजस्व का खजाना साबित हुई है। वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रालय (एमईआइटीवाई) की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन (आइसीईए) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 और वर्ष 2024 के बीच 12.55 लाख करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं का उत्पादन किया गया है। इस दौरान सरकार की ओर से 5,800 करोड़ रुपये पीएलआइ स्कीम के तहत आवंटित किए गए, जबकि स्मार्टफोन स्कीम के बदले में सरकार को 1,04,200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि प्रोत्साहन राशि का लगभग 19 गुना है। यह आंकड़ा इस योजना की सफलता को रेखांकित करता है, क्योंकि सरकार ने जो निवेश किया था, वह केवल उत्पादन में वृद्धि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप भारी राजस्व भी उत्पन्न हुआ।

चयनित कंपनियां और स्कीम का प्रदर्शन : पीएलआइ स्कीम के तहत कुल 10 कंपनियों का चयन किया गया, जिनमें से पांच वैश्विक और पांच भारतीय कंपनियां शामिल थीं। इस योजना के लिए कुल 38,601 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया। स्कीम के तहत कंपनियों को उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य होता है, और केवल उन्हें कंपनियों को इंसेंटिव प्रदान किया गया, जिन्होंने अपने निर्धारित उत्पादन लक्ष्य समय पर पूरे किए और हर वर्ष उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित की। यह योजना पांच साल के लिए लाई गई थी जिसे 2020 से 2025 तक चलना था, लेकिन कोविड के कारण इसमें देरी हुई।

इस योजना का प्रभाव केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजगार सृजन, राजस्व में वृद्धि, निर्यात में उछाल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) आकर्षित करने और मूल्यवर्धन (वैल्यू एडिशन) जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि सरकार अपने आगामी बजट में इस स्कीम के तहत और भी अधिक प्रोत्साहन देगी। इससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। इसके अलावा, वर्ष 2030 तक 500 अरब डालर के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस स्कीम के तहत स्मार्टफोन निर्माताओं को स्पष्ट और समयबद्ध उत्पादन लक्ष्य दिए गए, जिन्हें पूरा करने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस रणनीति के सहयोग से न केवल उत्पादन में तेजी आई, बल्कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। इस स्कीम के माध्यम से अब तक तीन लाख प्रत्यक्ष और छह लाख परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। इसके अतिरिक्त, यह योजना महिलाओं और मिड-स्किल वर्कर्स के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे उनके लिए नए आर्थिक अवसर खुले हैं। ब्लू-कालर वर्कर्स के लिए भी यह स्कीम बड़ी राहत साबित हुई, क्योंकि इससे उत्पादन से जुड़ी सहायक उद्योगों में भी रोजगार के अवसरों का विस्तार किया। इसके परिणामस्वरूप भारत न केवल स्मार्टफोन निर्माण में आत्मनिर्भर बना है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है, जिससे देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

निर्यात में ऐतिहासिक उछाल और मूल्यवर्धन

पीएलआइ स्कीम का एक और प्रभावशाली परिणाम भारत के स्मार्टफोन निर्यात पर देखने को मिला है। पहले, जहां भारत स्मार्टफोन निर्यात में 23वें स्थान पर था, अब यह तेजी से प्रगति करते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। इस स्कीम के तहत भारत ने अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपये के स्मार्टफोन निर्यात किए हैं। अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में स्मार्टफोन भारत के शीर्ष निर्यातित उत्पादों में शामिल हो गया है, जो भारत के बढ़ते तकनीकी कौशल और प्रतिस्पर्धा की दर्शाता है। इस स्कीम के प्रभाव से भारत ने निर्यात के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद अब स्मार्टफोन बन चुका है, जो वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

इस दिशा में एक जो बड़ा काम हुआ है वह है वैल्यू एडिशन का, क्योंकि जो स्मार्टफोन बनता है, ऐसा नहीं है कि वह एक इकलौता ही सबकुछ बना देता है। वस्तुतः स्मार्टफोन में आपको स्क्रीन भी चाहिए, बैटरी, उसमें नट बोल्ट वगैरह भी चाहिए। यानी उसमें जो भी केयरेनेट लगते हैं, उनमें से अधिकांश अलग-अलग देशों में बनते हैं। पिछले पांच वर्षों में भारत ने स्मार्टफोन निर्माण में वैल्यू एडिशन को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर लिया है, जिसका अर्थ है कि अब स्मार्टफोन के कुल घटकों का पांचवां हिस्सा भारत में ही निर्मित हो रहा है। यह उपलब्धि वैश्विक मानकों पर भी उल्लेखनीय है, क्योंकि इसे चरण में चीन और वियतनाम की तुलना में भारत ने तेज गति से वैल्यू एडिशन में वृद्धि की है। इस सफलता की सबसे बड़ी कहानी एप्पल की है। आइफोन निर्माण और निर्यात ने भारत के स्मार्टफोन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। एप्पल ने भारत से छह अरब डालर मूल्य के आइफोन का निर्यात किया है, जिससे देश की निर्यात क्षमता को नया आयाम मिला है। पिछले एक साल में आइफोन के निर्यात में मूल्य के आधार पर 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके चलते इस वित्तीय वर्ष में आइफोन का 10 अरब डालर का निर्यात लक्ष्य भी प्राप्त करने की संभावना जताई जा रही है। यह भारत के वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ते कदम और 'मेक इन इंडिया' विजन की सफलता को भी दर्शाती है।

इस स्कीम के माध्यम से केंद्र सरकार ने भारतीय स्मार्टफोन उद्योग के उत्पादन को बढ़ाया, रोजगार सृजन किया, निर्यात बढ़ाया और भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 अरब डालर के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह योजना निश्चित रूप से इसके करीब पहुंचने में मदद करेगी। अब जब भारत एक वैश्विक स्मार्टफोन निर्माता बन चुका है, तो आने वाले वर्षों में इस उद्योग के और अधिक प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

स्मार्टफोन निर्माण में भारत की सफलता के पीछे मोदी सरकार की नीतिगत स्पष्टता और प्रोत्साहनकारी दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस स्कीम के माध्यम से सरकार ने उत्पादन को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया। यह स्कीम न केवल वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है, बल्कि निर्माताओं को स्पष्ट लक्ष्य और प्रदर्शन आधारित लाभ सुनिश्चित करती है। "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसे अभियानों के तहत सरकार ने निवेश-अनुकूल माहौल बनाने के लिए लाजिस्टिक्स, टैक्स छूट और प्रक्रियागत सुधार जैसे कई उपाय किए। सरकार की इस सक्रिय भूमिका ने भारत को स्मार्टफोन निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में मदद की। विशेष रूप से एप्पल जैसे कंपनियों को आकर्षित करना और उत्पादन आधार को भारत में स्थानांतरित करने में सफलता हासिल करना, इस नीति समर्थन का प्रत्यक्ष परिणाम है। मोदी सरकार का यह दृष्टिकोण न केवल देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा है, बल्कि इसे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत स्थान दिला रहा है।

(शिवेश प्रताप)

खरी-खरी

प्रताड़ित बहू ईवीएम

रेखा शाह आरबी

अपने देश के नेता धन्य भाग हैं। उनके मन की हो तो सब जय जय और उनके मन की न हो तो हाय-हाय करने में देर नहीं लगाते हैं। मन की न होने पर ऐसा रुदाली रुदन प्रारंभ करते हैं कि जनता भी कंपकुंप हो जाती है कि माननीय अपना दुखड़ा से रहे हैं या जनता के दुख से दुखी हैं। वह सच बोल रहा या झूठ बोल रहा। आप हजार जन्म लेकर भी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हर नेता एक अच्छा अभिनेता होता है।

जबकि उससे पहले हजारों झूठ बोल चुका होता है और उसके झूठ बोलने पर जनता को विश्वास भी होता है। यदि वह कोई चुनाव जीतते हैं तो छाती 56 इंच की करके घूमते हैं। हर मंच पर यह कहते हुए स्वयं को शाबाशी देते हैं कि उनके कार्य और उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर जनता ने उनको पद रूपी आशिर्वाद दिया है, बेचारे कभी यह नहीं बताते हैं कि इसके लिए कितना स्वयं से मेहनत और वाद-विवाद किया है। लेकिन यदि वह चुनाव हार जाते हैं तो जिस दरिया-दिली से हर तरफ अपनी ईमानदारी और कर्मठता का बाजा बजाते हुए घूमते हैं। उसे दरियादिली से यह स्वीकार नहीं करते हैं कि उनके भ्रष्टाचार और करप्ट नियत के कारण जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। उस समय वह ईवीएम के माथे अपनी नाकामी और नकारापन का छठा फोड़ते हैं।

और ईवीएम तो है ही सबके पाप अपने सिर ढोने के लिए। ईवीएम का दिल तो यही कहता है कि कहां जाए... साहब अपने पाप कभी अपने आप भी ढो लीजिए। भार उठाते उठाते थक चुकी हूं, लेकिन माननीय को तो आहत पड़ चुकी है। अपना हर काम दूसरों से करवाने की तो यह काम भला स्वयं से कैसे कर सकते हैं।

अपने देश में ईवीएम से मतदान होते अब बहुत साल बीत गए। लेकिन बेचारे का हाल आज भी एकदम प्रताड़ित बहू की तरह है। कोई कौआकंनी कह देता है, कोई कनडेबर कहता है। एक ही व्यक्ति को कभी अच्छी लगती है और कभी बहुत बुरी लगती है। जिसके मन में जो आता है, वही उसे सुना देता है चाहे भले ही उसकी सुनने की आकात न हो। और वह बेचारी के जैसे अपना माथा पीट के रह जाती है।

X पोस्ट

पाकिस्तान के 'हाइब्रिड शासन तंत्र' ने आखिरकार आइसीसी पैरिंग्रेस ट्राफी के आयोजन को लेकर भी हाइब्रिड माडल स्वीकार कर लिया है।

सुशांत सरीन@sushantsareen

प्रतीत होता है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखेगा तब तक वहां आइसीसी के आयोजन हाइब्रिड माडल में ही होते रहेंगे। फिलहाल तो यही समाधान दिख रहा है।

मकरंद केणकर@wmakarand

इस देश में किसी की भी जमीन और किसी भी धर्मस्थल पर दावा करने का अधिकार सिर्फ वक्फ बोर्ड को है। अगर आप अपने धर्म स्थल पर अपना दावा करते हैं तो आप साप्रदायिक है।

विष्णु शंकर जैन@Vishnu_Jain1

संयोग जांच ब्यूरो यानी एफबीआइ के अगले निदेशक के रूप में काश पटेल की नियुक्ति के साथ ही ट्रंप ने इस अमेरिकी एजेंसी में व्यापक स्वच्छता अभियान का आगाज कर दिया है। मौजूदा निदेशक के दौर में तो यह एजेंसी उन खालिस्तानी आतंकियों की ढाल बनी हुई है, जो भारत को तरह-तरह की आतंकी धमकियां देते रहते हैं।

ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चयन में देरी महायुति में खटपट का संकेत करती है?

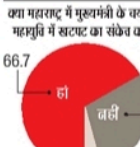

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आपको संसद के शीतकालीन सत्र में इस सप्ताह सामान्य कामकाज होने के आसार नजर आ रहे हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बच्चे हों दो से अधिक हों यह नेक सलाह,
मालिक ईश्वर है मगर जैसी उसकी चाह।
जैसी उसकी चाह किसी को दे दो दर्जन,
कोई दे औलाद तड़पता सारा जीवन।
पढ़े-लिखे-गुणवान रहे तो दो ही अच्छे,
वरना तो बेकार यहां हो दर्जन बच्चे!

– ओमप्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

सुलगे संभल में संभावनाएं तलाशती राजनीति

हरिशंकर मिश्र
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

संभल में राजनीति के लिए सब कुछ है। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जामा मस्जिद है, इसको लेकर अदालत में वाद भी है और अब हिंसा में चार लोगों की मौत भी। सुनियोजित ढंगे की परतें धीरे-धीरे खुलती हैं और बहुत कुछ बेनकाब होता है और ऐसा ही वहां हो भी रहा है। एक शहर जिसे बड़ा तो कतई नहीं कहा जा सकता, वहां स्थिति आसानी से संभाली जा सकती थी, लेकिन संभाली नहीं जा सकी और अब कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि बिवादों में घिरी एक मस्जिद के निकटवर्ती मोहल्लों में तनाव बढ़ता रहा, विरोध की तैयारियां होती रहीं, लेकिन पुलिस-प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? लगी तो इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। अब संभल को लेकर राजनीति गरमाई है तो प्रशासनिक विफलता इसकी आड़ में छिप गई है, लेकिन इस बात पर भी सोचना होगा कि कहीं रख के नीचे अभी भी कुछ दबा तो नहीं है। न भी दबा हो तो राजनीति के लिए तो बहुत कुछ है ही और इसलिए विपक्षी इसको लेकर मुखर हैं और अगले चुनाव तक रहेंगे।

संभल के इतिहास में जाएं तो यहां 48 साल पहले 1976 में भी दंगा भड़क चुका है और केंद्र में यही जामा मस्जिद थी। तब कुछ शहराती तत्वों ने जामा मस्जिद में घुसकर माहौल खराब किया था और हिंदू-मुस्लिमों में लंबे समय तक तनाव का माहौल रहा। अब जबकि अतीत की बातें भूलकर दोनों ही वर्ग भाईचारा बनाकर चल रहे थे तो फिर अब जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़क गई। इसके मूल में एक दावा है जो कि कहता है कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। यह दावा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 19 नवंबर को किया और अदालत ने आदेश दिया कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुना जाना जरूरी है। इसलिए भारत सरकार व अन्य दूसरे पक्षों को सुने जाने के लिए नोटिस भेजा जाए ताकि दोनों पक्षों को सुनकर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। एडवोकेट कमिश्नर अपनी मौके की रिपोर्ट अदालत में नियत तिथि को प्रस्तुत करें। मामला संवेदनशील होने से उसकी वीडियोग्राफी की जाए। उसी दिन प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ वीडियोग्राफी कराई।

संभल में 24 नवंबर को पुलिस बल पर पत्थर फेंकते शहराती तत्व। फाइल

अब बात 24 नवंबर की। यानी रविवार... हिंसा का दिन। दूसरे चरण का सर्वे करने के लिए रविवार सुबह सात बजे एडवोकेट कमिश्नर समेश राघव एवं वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन व श्री गोपाल शर्मा, केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विष्णु शर्मा एवं जामा मस्जिद कमेटी के सदर के साथ टीम मस्जिद में पहुंची और वीडियोग्राफी चल ही रही थी कि तीन तरफ से अचानक ही भीड़ उमड़ी और पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव और आगजनी शुरू हो गई। पुलिस और उपद्रवियों के आमने-सामने फायरिंग शुरू हो गई। इसमें पांच लोगों की मौत हो गई, हालांकि पुलिस ने इसे चार ही माना। एक युवक को उसके परिजनों ने बगैर पोस्टमाटम कराए ही दफना दिया और कोई शिकायत भी नहीं की। इसके बाद की कार्रवाई पुलिस की है और लगभग ढाई सौ लोग हिरासत में लिए गए। इंटरनेट बंद कर दिया गया और दो दिन के बाद स्थिति पर प्रशासन की पूरी पकड़ थी। आरोपित चिह्नित कर लिए गए थे जिसमें सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। 3,750 से अधिक लोगों के खिलाफ सात अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं।

प्रशासन की शुरुआती पड़ताल में ही यह साफ हो गया कि पूरी हिंसा सुनियोजित थी। घटना से पहले हुई जुमे की नमाज में ही लोगों को उकसाने वाली बातें कही गई थीं। पत्थरबाजी की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। अब पुलिस ने ऐसे युवकों की फोटो भी सार्वजनिक की है जिसमें हाथ में पत्थर लिए युवकों का समूह नजर आ रहा है। नुकसान की पड़ताल भी की जा रही है और जैसा कि योगी सरकार में अब तक होता आया है प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा ही, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक बयानबाजी के दौर जारी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटनाक्रम के दिन ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का गठन कर संभल जाने का आदेश दिया, लेकिन किसी भी नेता को घर से निकलने ही नहीं दिया गया। इसके बाद से शहर में बाहर से प्रवेश करने वालों पर 10 दिसंबर तक के लिए पाबंदी है। फिर भी राजनीति तो होगी ही, अखिलेश यादव ने अब खुद संभल जाने का निर्णय लिया है तो राजनीति का गरमाना तय है।

छत्तीसगढ़ डायरी

नियुक्ति में भ्रष्टाचार से मुक्ति

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार का एक वर्ष पूरा होने को है। चिंतन-मंथन का दौर चल रहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष में क्या किया। इस बीच 28 नवंबर को वर्ष 2023 की छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। प्राथमिक तौर पर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्ति के दावे को दम मिला है। सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी भी वर्ष 2021 की परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

सरकार की उपलब्धियों और विफलताओं पर जारी चर्चा के साथ कांग्रेसियों के बीच हार के कारणों का भी विश्लेषण चल रहा है। कांग्रेसी अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि अगर किसी एक मुद्दे ने सरकार के विरुद्ध पूरे प्रदेश में माहौल खड़ा किया तो वह रहा सीजीपीएससी 2021 में भ्रष्टाचार। नौकरशाहों से लेकर उद्योगपतियों-पूंजीपतियों तक ने अपने खिलेदरों की डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार आदि बनाने के लिए लाखों-करोड़ों खर्च किए। सीजीपीएससी के अधिकारियों ने अपने परिवार के दो-दो, तीन-तीन लोगों को चयनित करा लिया। इधर कांग्रेस नेतृत्व के पक्ष में केवल बदनामी ही आई। प्रदेश के किसी प्रमुख नेता के खिलेदर का नाम इस घोटाले में नहीं आया, परंतु कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में बदनाम हो गई। युवाओं के बीच बघेल सरकार के विरोध में माहौल खड़ा हो गया। तब सरकार ने अगर आरोप सामने आते ही टामन सिंह सोनवानी को अध्यक्ष पद से हटाते हुए जांच की घोषणा कर दी गई होती तो शायद परिणाम कुछ और होता।

विधानसभा का चुनाव परिणाम तीन दिसंबर 2023 को आने के बाद 13 दिसंबर को विष्णु सरकार के पदभार ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के संकल्पों में सीजीपीएससी की भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा का मुद्दा शीर्ष पर था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी चुनावी सभाओं में भष्ट्राचार मुक्त और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया का वादा किया। यह संयोग है कि 28 नवंबर को घोषित परिणाम में सभी शीर्ष अभ्यर्थी ऐसे हैं जो संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त कर सके हैं।

इधर विष्णु देव सरकार 3100 रुपये क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये की दर से महतारी वंदन योजना का लाभ देने के वादों को निभाने में भी सफल रही है। इस तरह किसानों और महिलाओं को साधने में सरकार की सफलता पर कोई प्रश्न नहीं है। इन सबके बीच विपक्ष की तरफ से सरकार पर अभिश्चय और अनिर्णय के भी आरोप लग रहे हैं। राजधानी रायपुर में ही अपराध की घटनाओं में वृद्धि का उदाहरण देकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार हमलावर हैं। विपक्ष का आरोप यह भी है कि सत्ता के चार केंद्र हो गए हैं और उनके उपकेंद्र अलग-अलग जगहों से संचालित हो रहे हैं। कुछ दिल्ली से, कुछ नागपुर से और कुछ तो झारखंड-बिहार से भी। सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार की दरों के नए कीर्तिमानों की भी बात हो रही है जिसके संबंध में विपक्ष की तरफ से 50 से 52 प्रतिशत तक पहुंच जाने के दावे हैं। मंत्रियों के विभागों के संचालन केंद्र स्थापित हो गए हैं। इसमें सत्य तो पड़ताल का विषय है, परंतु किसी को संदेह नहीं कि विष्णु देव साय अपने लक्ष्यों को साधने के प्रति पूर्ण सचेत हैं। उनके स्तर से किसी तरह की गड़बड़ी को संरक्षण भी नहीं मिल रहा।

यद्यपि जनता ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जिस तेजी से कार्रवाई की उम्मीद लगा ली गई थी वह ध्वस्त होती नजर आ रही है। कोयला, आबकारी, महादेव सट्टा एप, डीएमएफ जैसे घोटाले में परिणाम बिस्वल की खिचड़ी की तरह हांडी पर चढ़े हैं। भाजपा ने सत्ता में वापसी के बाद भ्रष्टाचार के एक दर्जन से अधिक मामलों में जांच और कार्रवाई की घोषणा कर रखे है। इनमें से कई की जांच रिपोर्ट सरकार तक पहुंच भी चुकी है परंतु उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। कार्रवाई की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही। इनमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में 800 करोड़ का भ्रष्टाचार भी शामिल है। शराब बन गमन पथ योजना का ठेकेदार जांच की घोषणा के बाद काम छोड़कर भाग चुका है। गौठानें बंद हैं और भ्रष्टाचार की फाइल भी। राजीव मितान क्लब से लेकर आदिवासी बहुल गांवों में खेलर पैनल खरीदी तक में घोटाले की जांच की घोषणाएं कार्रवाई के इंतजार में हैं। विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर विपक्ष प्रश्न कर रहा है और सरकार को स्वयं उत्तर देना होगा।

सीजीपीएससी घोटाले में कार्रवाई के लिए सीएम विष्णु देव साय का बनवाया करते पुतला। डीपीआर

इन सबके बीच नक्सलमुक्ति की दिशा में प्रदेश मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। पिछले एक वर्ष में 260 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर प्रदेश शांति स्थापना के साथ ही तेजी से प्रगति पथ पर बढ़ेगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री की भूमिका में बस्तर में नगरनार इस्पात संयंत्र की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले विष्णु के कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने पर इन ठोस उपलब्धियों की चर्चा तो अवश्य ही की जाएगी। साथ ही जनता की आकांक्षा घोषणा पत्र से जागृत उम्मीदों को सरकार होते देखने की भी है।

****

अनमोल वचन

कठोर संयम और अनुशासन के बिना मनुष्य किसी भी गुण को नहीं अपना सकता।
-हजारी प्रसाद द्विवेदी

'महायुति' में जोरआजमाइश

महाराष्ट्र की 'महायुति' सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसम्बर को होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। 23 नवम्बर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के इतने दिनों बाद अभी तक नये मुख्यमंत्री के शपथ न ले सकने पर अटकलबाजियों का बाजार भी गरम है। हालांकि इतना तय है कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और देवेंद्र फड़णवीस मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे चल रहे हैं। इस बीच, कार्यकारी मुख्यमंत्री और शिवसेना (शिंदे) के नेता एकनाथ शिंदे के अचानक स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपने पैतृक गांव चले जाने से यह भी लगता है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महायुति के घटक दल भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) के बीच

बताया जाता है कि भाजपा को मुख्यमंत्री पद और उपमुख्यमंत्री के दो पद, जिनमें से एक-एक पद शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) को दिए जाने पर मुहर लग चुकी है। तो शिंदे का एकाएक अपने गांव चले जाने को क्या समझा जाए? दरअसल, संख्या बल के मद्देनजर मुख्यमंत्री पद पर शिंदे दावा करने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि उनके पक्ष के कुछ विधायकों ने यह कहकर मामले को गरमाने की कोशिश जरूर की कि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया था और उनकी कुछ योजनाओं ने मतदाताओं को खासा प्रभावित किया जिससे महायुति के पक्ष में जनादेश आया। यह भी कहलवाया गया कि मुख्यमंत्री पद पर ओबीसी को लाया जाए। ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री पद पर रहने का प्रस्ताव भी शिंदे के एक विधायक ने रखा था। लेकिन शिंदे को इतना साफ हो गया है कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद से नहीं नवाजने वाली। उस सूरत में तो कतई नहीं जब अजित पवार के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा जुटाने की स्थिति में है। दरअसल, शिंदे की कोशिश है कि मुख्यमंत्री पद नहीं तो कुछ महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों पर काबिज हुआ जाए। इससे एक तो उन्हें अपने दल को एकजुट बनाए रखने में मदद मिलेगी और दूसरे, अपने मतदाता वर्ग को भी अपने साथ जोड़े रखने में मदद मिलेगी। शिवसेना (उद्धव) से भविष्य में मिल सकने वाली चुनौती से निश्चिंत होने के लिए शिंदे के लिए जरूरी है कि अपने मतदाता वर्ग और विधायकों को एकजुट रखते हुए अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखें। बहरहाल, शिंदे के सामने ज्यादा विकल्प नहीं हैं। भाजपा के पास सीएम पद रहना तय है। शिवसेना और एनसीपी (अजित) से 1-1 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इस बीच, घटक दलों में जोरआजमाइश जारी रहेगी।

कर्मचारियों का हित जरूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का खाताधारक बनने के लिए पंद्रह हजार रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में श्रम मंत्री ने इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया जो इसका अध्यक्ष भी होता है। ईपीएफओ के सारे फैसले यही बोर्ड लेता है। बैठक में तीस हजार तक वेतन पाने वाले कर्मियों और श्रमिकों को ईपीएफओ का सदस्य बनाने के मामले में चर्चा होने के बावजूद मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। न ही मंहगाई भत्ते देने या मुफ्त इलाज की

सुविधाओं पर कोई जवाब मिला। बीते दस सालों में ईपीएफओ के खाताधारक/पेंशनर दोगुने हो चुके हैं। जमाराशि और सेटेलमेंट भी दोगुने हो चुके हैं मगर इसकी तुलना में कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी। निचले वर्ग को पीएफ का लाभ देने से ना-नुकर करने वाली सरकार कारोबारियों के हितों को लेकर अभी भी पक्षपाती नजर आती है। जैसा कि बैठक में सरकार इंडस्ट्री फ्रेंडली नीति के तहत माफी योजना लाई। जो कर्मचारियों का पीएफ नहीं जमा कर रहे हैं, या जिन्होंने अपने कर्मियों को सदस्य बनाने में हिलाई की, उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जैसा कि नियमों के अनुसार किसी भी कंपनी या फर्म में यदि कर्मचारियों की संख्या बीस से ज्यादा है तो ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। परंतु बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जो उनका पंजीकरण कराने या समय पर अंशदान करने में कोताही करती हैं जिससे खाता निष्क्रिय हो जाता है। लोक सभा में दी गई जानकारी के अनुसार संगठन में साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि निष्क्रिय खातों में जमा है। सरकार को इसका निपटान जल्द करना चाहिए। यह जरूरतमंदों की मेहनत की कमाई है। कारोबारियों की गलती का खामियाजा हमेशा नीचे का कर्मचारी और श्रमिक ही भुगतता है। खासकर इस वक्त, जब सरकार पेंशन को लेकर नये नियम बनाने को उतावली है, उसे संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के प्रति अपना रवैया मुलायमियत भरा रखना चाहिए। पहले ही उनके श्रम का उचित आकलन करने से कारोबारी कतराते हैं, उस पर नियमानुसार उन्हें मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा में सेंध लगाने का मौका किसी पक्ष को दिया जाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। श्रम मंत्रालय को संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने निर्णय पर पुनर्निरीक्षण करना चाहिए।

सामयिक/नीरज शर्मा 'भरथल'

हिन्दू-सिख भाईचारे पर खतरा

देश को तोड़ने में लगी ताकतें हर बात को लोगों के पास ऐसे पहुंचाती हैं कि वो विवादित बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही बाबा वागेश्वर की एक पुरानी वीडियो में दिए गए बयान के साथ किया जा रहा है। वीडियो में बाबा ने जिक्र किया है कि हरिहर मंदिर में पूजा नहीं हो रही परंतु अब जल्द ही उसमें रुद्र अभिषेक किया जाएगा और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब देश विरोधी ताकतों ने हिन्दू-सिख भाईचारे में तनाव फैलाने के लिए इस बयान को हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर के साथ जोड़ दिया है। जब कि जो बात की गई है, वो संभल में स्थित जामा मस्जिद के संदर्भ में कही जा रही है।

मुगलकाल के आरंभिक दौर में बाबर ने मीर बाकि को अवध का गवर्नर बनाया था। माना जाता है कि इसी दौरान 1528 में उसने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था और 1529 में इसी मीर बाकि, जिसे मीर बेग नाम से भी जाना जाता है, ने संभल की जामा मस्जिद का निर्माण श्रीहरिहर मंदिर को तोड़ कर करवाया था। संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण करीब 5 बीघा जमीन पर किया गया है। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दायर की याचिका में दावा किया है कि जामा मस्जिद की इमारत ही सदियों पुराना श्री हरिहर मंदिर है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर मंदिर होने की कई निशानियां मौजूद हैं, जिनमें कुछ खंभों का भी जिक्र है। हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान हरिहर भगवान विष्णु और भगवान शिव के मिश्रित रूप हैं। इन्हें हरिहर के अलावा शंकरनारायण और शिवकेशव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके शरीर का एक हिस्सा भाग्यान विष्णु यानी हरि और दूसरा भगवान शिव यानी हर का है। संभल में शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट 29 नवम्बर को चंदौसी कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। कोर्ट कमिश्नर के अनुसार सर्वे की रिपोर्ट पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। इस बीच सूत्रों की मानें तो सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं, जो हिन्दू पक्ष के पक्ष को मजबूत करते हैं। जानकारी के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्जिद में कई हिन्दू प्रतीक चिह्न मिले हैं। पश्चिमी गेट के पास द्वारपाल शैली के खंबे हैं, जिन पर कलाकृतियां बनी हुई हैं। मस्जिद के मुख्य गुंबद पर कलशों की आकृति मिली है।

नासूर बनता बढ़ता स्तर

प्रदूषण

योगेश कु. गोयल

प्रदूषण को लेकर उद्योगों को जागरूक करने तथा लोगों में प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 2 दिसम्बर को 'राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मूल उद्देश्य देश में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों को आवश्यकता की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। वास्तव में यह दिन 1984 की उस भयानक गैस त्रासदी की घटना के कारण पीड़ित हुए लोगों के निर्दोष जीवन को याद करने के लिए चिह्नित किया गया है, जिसमें हजारों लोग भोपाल की यूसीआईएल फैक्टरी से मिथाइल गैस के रिसाव के कारण मौत की नींद सो गए थे।

इस दिन विशेष रूप से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है तथा देश में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में लोगों को बताया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को प्रदूषण रोकने में मददगार बनने और विभिन्न कानूनों के बारे में उन्हें अधिकाधिक जागरूक करना है। हालांकि औद्योगिक प्रदूषण की जांच के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एनपीसीबी) बनाया हुआ है, जो जांच करता है कि उद्योगों ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन किया है या नहीं लेकिन इसके बावजूद औद्योगिक प्रदूषण को लेकर आज भी स्थिति कितनी विकराल है, किसी से छिपा नहीं है।

कल-कारखानों एवं फैक्टरियों से निर्बाध रूप से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन वायु प्रदूषण के स्तर को दिनों-दिन बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन की विभिन्न चुनौतियां दुनिया के सामने खड़ी हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए दुनिया भर के देश वैश्विक उपाय कर तो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नाकाफी ही साबित हुए हैं। घातक विकिरण से धरती की सुरक्षा करती ओजोन परत में छेद के लिए वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार माना जाता है

> कारखानों एवं फैक्टरियों से निर्बाध निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन वायु प्रदूषण के स्तर को दिनों-दिन बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन की विभिन्न चुनौतियां दुनिया के सामने खड़ी हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए दुनिया भर के देश वैश्विक उपाय कर तो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नाकाफी ही साबित हुए हैं। घातक विकिरण से धरती की सुरक्षा करती ओजोन परत में छेद के लिए वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार माना जाता है

की जा रही जहरीली गैसों के कारण ही ओजोन परत में छिद्र हुआ है, जिसे भरने के लिए दशकों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है।

भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार वायु प्रदूषण विश्व भर में प्रति वर्ष करीब सत्तर लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है। आंकड़ों के अनुसार स्थिति इतनी खराब है कि वायु में मौजूद प्रदूषक हवा के जरिए सीधे शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों, मस्तिष्क तथा हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं, और दस में से नौ लोगों

को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नहीं मिलती। प्रदूषण इस कदर नासूर बनता जा रहा है कि पिछले कुछ समय से इस मामले में बार-बार सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है। खासकर दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण स्तर पर तो सुप्रीम कोर्ट कई बार कड़ी नाराजगी जताते हुए कड़े निर्देश दे चुका है लेकिन हालात जस के तस हैं। हालांकि वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा करीब डेढ़ महीने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप के तहत कार्रवाई की जा रही है और अभी भी ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू हैं किंतु वायु प्रदूषण पर लगाम कसने में सफलता नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की राजधानी में नवम्बर का महीना अत्यधिक प्रदूषित रहा और अभी भी हालात में सुधार की संभावना नजर नहीं आ रही।

वायु प्रदूषण को लेकर देश के कई अन्य इलाकों के हालात भी अच्छे नहीं हैं। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि यह न केवल तरह-तरह की गंभीर बीमारियों का जनक बन रहा है, बल्कि प्रति वर्ष लाखों लोग वायु प्रदूषण के ही कारण काल के ग्रास बन रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि दुनिया भर में करीब चार अरब लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, केरोसिन ऑयल, गोबर इत्यादि ईंधन पर निर्भर हैं, जो बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, और इनका गंभीर असर पर्यावरण के साथ-साथ खाना पकाने वालों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।

हेल्थ इफैक्ट इंस्टीच्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक बाहर तथा घर के अंदर लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण स्ट्रोक, दिल का दौरा, डायबिटीज, फेफड़ों का कैंसर तथा जन्म के समय होने वाली बीमारियों इत्यादि की चपेट में आकर अब हर साल भारत में कई लाख लोगों की मौत हो रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण और हृदय एवं फेफड़े रोगों के बीच संबंध होने के स्पष्ट साक्ष्य हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 के बाद से पांच करोड़ से अधिक लोग घर के अंदर वायु प्रदूषण से पीड़ित हुए हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की बैक्रानिक बेट रिट्ज का कहना है कि घरों के अंदर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक समस्या भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में है। वायु प्रदूषण दुनिया में मौत के बड़े कारणों में चौथे स्थान पर है। 'स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर' रिपोर्ट के अनुसार उच्च रक्तचाप, तंबाकू सेवन तथा खराब आहार के बाद समय से पहले मौत का चौथा प्रमुख कारण वायु प्रदूषण ही है।

बच्चों पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को लेकर तो दुनिया भर में अनेक शोध किए जा चुके हैं, और इन सभी का निष्कर्ष है कि प्रदूषण बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जिसके चलते प्रति वर्ष लाखों बच्चे असमय काल का ग्रास बन जाते हैं, और करोड़ों बच्चे मासूम उम्र में ही तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। 'प्रदूषण मुक्त सांसें' पुस्तक के अनुसार, बयस्कों की तुलना में बच्चे वायु प्रदूषण के सबसे आसान शिकार बन रहे हैं, जो अपने कोमल फेफड़ों और इम्यून सिस्टम के चलते हवा में मौजूद विषैले तत्वों को सांस के जरिए अपने अंदर ले रहे हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि वायु प्रदूषण बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण बच्चे के फेफड़े और मस्तिष्क के विकास तथा संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित कर सकता है, और अगर समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं तो पूरी जिंदगी बनी रह सकती हैं।

(लेख में विचार निजी हैं)

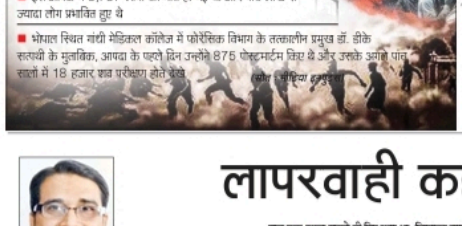

ट्रंप ने काश पटेल को एफबीआई के डायरेक्टर पद के लिए नामांकित करके इस एजेंसी के कार्यकलाप दुरुस्त करने का प्रयास किया है, जो अमेरिकी 'डीप स्टेट' की अंग है। मौजूदा डायरेक्टर के तहत एफबीआई ने भारत के लिए खतरा बनने वाले खालिस्तानी उग्रवादियों को शह दी थी।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

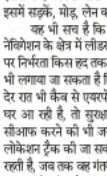

बरेली पुल हादसा | **कुमार समीर**

लापरवाही कहें या हत्या

गूगल मैप्स हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। एक स्थान से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसका जम कर इसका इस्तेमाल हो रहा है। करोड़ों भारतीय रोजाना सफर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें अपनी यात्रा प्लान करने में मदद मिलती है। इसमें सड़कें, मोड़, लेन की जानकारी शामिल होती हैं।

यह भी सच है कि आज की तारीख में गूगल मैप्स नेविगेशन के क्षेत्र में लीडर की भूमिका में है। लोगों की इस पर निर्भरता किस हद तक बढ़ गई है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अगर आपकी, हमारी बिटिया देर रात भी कैब से एयरपोर्ट, स्टेशन जा रही है, या वहां से घर आ रही है, तो सुरक्षा के ख्याल से रिसीव करने या सीआफ करने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे ही उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, और यह सुविधा तब तक रहती है, जब तक वह गंतव्य तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाती। सुरक्षा की दृष्टि से यह बड़ी बात है, और जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वे सफर आसान हो जाने के लिए गूगल को धन्यवाद देते भी नहीं थकते।

लेकिन पिछले दिनों बरेली में एक हादसे से सब कुछ उल्टा हो गया है। सुरक्षा को लेकर ही गूगल मैप्स ऐप पर सवाल खड़ा किया जाने लगा है। पूछा जा रहा है कि गूगल मैप्स ने टूटे पुल वाला रास्ता क्यों दिखाया? हालांकि इसमें भी दो राय नहीं कि हादसे के बाद प्रथम दृष्टया कोई भी यही सवाल करेगा। कई लोग तो तर्क देते हैं कि गूगल मैप्स बरेली में त्रासदी को टाल सकता था। यह गूगल मैप्स की लापरवाही है, जो यूजर्स डेटा की बड़ी मात्रा एकत्र करता है। पुल एक साल पहले ही गिर गया था, जिसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान किसी भी यूजर ने उस सड़क का उपयोग नहीं किया। अगर यह मामला है तो सबसे बड़ा सवाल है कि गूगल मैप्स एक सड़क की सिफारिश कैसे कर सकता है, जिसका इस्तेमाल एक साल से ज्यादा समय से नहीं हुआ है?

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन के प्रमुख अमित यादव का कहना है कि इस विसंगति को गूगल मैप्स के एल्गोरिदम द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए था, जिससे संभावित रूप

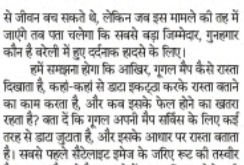

से जीवन बच सकते थे, लेकिन जब इस मामले की तह में जाएंगे तब पता चलेगा कि सबसे बड़ा जिम्मेदार, गुनहगार कौन है बरेली में हुए दर्दनाक हादसे के लिए।

हमें समझना होगा कि आखिर, गूगल मैप कैसे रास्ता दिखाता है, कहां-कहां से डाटा इकट्ठा करके रास्ता बताने का काम करता है, और कब इसके फेल होने का खतरा रहता है? बता दें कि गूगल अपनी मैप सर्विस के लिए कई तरह से डाटा जुटाता है, और इसके आधार पर रास्ता बताता है। सबसे पहले सैटेलाइट इमेज के जरिए रूट की तस्वीर तैयार करता है। इसे तैयार करने में गूगल एरियल फोटोग्राफी का भी इस्तेमाल करता है। ट्रैफिक सिग्नल कैमरा, जीपीएस, यूजर इनपुट और स्ट्रीट मैप के जरिए गूगल डाटा तैयार करता है। इसके बाद गूगल की मैप सर्विस सारे इनपुट के साथ रियल टाइम डाटा की एनालिसिस करती है, और इसके आधार पर गूगल रास्ता दिखाता है। गूगल मैप जीपीएस सिस्टम के जरिए यूजर की लोकेशन और मंजिल के बीच का रास्ता बताता है। मोड़ से पहले बॉयस के जरिए यूजर्स को अलर्ट भी भेजता है। यह सब कुछ इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि गूगल कई तरह के डाटा इकट्ठा करता है। सड़क की क्या स्थिति है, यह स्ट्रीट व्यू के जरिए पता चलती है। स्ट्रीट व्यू के लिए वो कैमरे जिम्मेदार होते हैं, जो गूगल को मौजूदा हालात की जानकारी देते हैं। इनके जरिए ही गूगल तक सड़कों की 360 डिग्री तस्वीरें पहुंचती हैं। इन सबकी प्रॉसेसिंग के बाद ही गूगल मैप के जरिए आप तक जानकारी पहुंचाता है।

अब घटना स्थल की बात करें तो जिस पुल पर यह हादसा हुआ उसकी अप्रोच रोड करीब साल भर पहले ही बाढ़ में बह गई थी। दरअसल, बदायूं जिला दातागंज से बरेली जनपद के फरीदपुर को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण कराया गया था। पुल 2021-22 में बन कर तैयार हुआ था और 2022 में पुल पर वाहन दौड़ने लगे थे। कुछ महीने बाद ही बाढ़ आई और 2023 जुलाई में पुल की अप्रोच रोड पूरी तरह से बह गई। अधूरे पुल पर जाने से ही गत रविवार सुबह कार पुल से नीचे नदी में गिर गई और 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की बड़ी लापरवाही झलकती है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने पुल की अप्रोच रोड बहने के बावजूद पुल के दोनों ओर कोई भी अवरोध, बैरिकेड नहीं किया। इस वजह से दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। दोनों ओर बैरिकेड होता तो हादसा नहीं होता। कैमरे से गूगल को टूटे हुए पुल की जानकारी मिल जाती। पीडब्ल्यूडी द्वारा जान बूझकर पुल के दोनों किनारों पर मजबूत बैरिकेडिंग, अवरोध, रिफ्लेक्टर बोर्ड नहीं लगाया गया था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सहानुभूति | **श्रीराम शर्मा आचार्य**

सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सहानुभूति एक शक्ति है, संबल है, जिससे

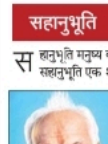

मानवता के हितों की रक्षा होती है। सहानुभूति इतनी विशाल आत्मिक भाषा है कि इसे पशु-पक्षी तक प्यार करते हैं। किसी चरवाहे पर सिंह हमला कर दे तो समूह के सारे जानवर उस पर टूट पड़ते हैं, और सींगों से मार-मारकर बलशाली शेर को भगा देते हैं। एक बंदर की आर्त पुकार पर सारे बंदर इकट्ठा हो जाते हैं। बाज के आक्रमण से सावधान रहने के लिए चिड़ियां विचित्र प्रकार का शोर मचाती हैं। यह बिगुल सुनते ही सारे पक्षी अपना-अपना मोर्चा मजबूत बना कर छूप जाते हैं। सहानुभूति की भावना से जब पशुओं तक में इतनी उदारता हो सकती है, तो मनुष्य इससे कितना लाभान्वित हो सकता है, इसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। सहानुभूति के विकास के साथ चार और सुगों का विकास होता है-1) दयाभाव, 2) उदारता, 3) भद्रता; और 4) अंतःदृष्टि। सहानुभूति की भावनाएं जितना अधिक प्रौढ़ होती हैं, दया भावना उसी के अनुरूप एक आवेश-मात्र न रह कर स्वभाव का एक अंग बन जाती है। जीव-जंतुओं के प्रति भी दया आने लगती है। स्वेच्छापूर्वक किसी का उपकार करना ही उदारता है, यह सहानुभूति का दूसरा चरण है। इस कोटि के सभी व्यक्ति भद्र माने जाते हैं। इन सज्जनोचित भावनाओं से अंतःदृष्टि जागृत होती है। जो सबको परमात्मा का ही अंश मानते हैं, वही आत्मज्ञान के सच्चे अधिकारी होते हैं। निर्दयतापूर्वक किए गए कार्य, नीचता, ईर्ष्या, विद्वेष और संदेह के दुर्गुणों के कारण लोगों को बाद में बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। जब चारों तरफ से असहयोग, अविश्वास और असम्मान लोग व्यक्त करने लगते हैं, तो अपने कुकृत्यों पर आत्मग्लानि होती है। सोचते हैं, हमने भी परोपकार किया होता, दूसरे के दुःखों को अपना दुःख समझ कर मेल-व्यवहार पैदा किया होता तो आज जो अकेलेपन का दुःख भोग रहे हैं, उससे तो बच गए होते। इस पश्चाताप की अग्नि में जल-जल कर लोग अपनी शेष शक्तियों का भी नाश कर लेते हैं किंतु जो दूसरों के हृदय के साथ अपना हृदय मिला देते हैं, उन्हें सभी से निश्छल प्रेम मिलता है, और गर्म-ज्ञान प्राप्त होता है।

रीडर्स मेल

एड्स के प्रति जागरूकता जरूरी

एक दिसम्बर को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना है। एड्स खतरनाक रोग है, मूलतः असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दरअसल, विश्व एड्स दिवस आपको याद करता है कि यह बीमारी अभी भी हमारे-आपके बीच है, और इसे खत्म करने की कोशिशों में आपको भी आगे आना होगा। निम्न वर्ग के लोगों में अभी भी जानकारी का अभाव है। इसलिए भी इस वर्ग में एचआईवी पॉजीटिव लोगों की संख्या अधिक है जबकि बहुत सी संस्थाएं निम्न आय वर्ग के लोगों में इस बात के प्रति जागरूकता अभियान चला रही हैं। लोग कारण को जाने के बाद भी सावधानियां नहीं बरतते। जिन कारणों से एड्स होता है, उनसे बचने की बजाय उन्हें अनदेखा कर जाते हैं। इनमें से अधिकांश लोग असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित रक्त के कारण एड्स की चपेट में आते हैं। एचआईवी को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। प्रसिद्ध उद्धरण है 'रोकथाम इलाज से बेहतर है'। सुरक्षित संभोग, एसटीडी के लिए परीक्षण, एकल यौन साथी, सुई साझा करने जैसे अस्वास्थ्यकर चलन से परहेज किया जाना चाहिए।

देवानंद राय, ई मेल से

उकसाने वालों पर भी कसें नकेल

न्यायालय में विचाराधीन मामलों को प्रभावित करने के लिए धरने, प्रदर्शन, हड़ताल, अराजकता, पत्थरबाजी जैसे कृत्यों को अंजाम देना फैशन बन गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने में अराजक तत्व पीछे नहीं रहते। सिर्फ आरोप लगा कर कठोर कार्रवाई के लिए प्रदर्शन करना भी इसी श्रेणी में आता है। संभल में कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालते हुए भीड़ द्वारा की गई पथरबाजी भी इसी श्रेणी में आती है। कौन नहीं जानता कि देश में कुछ राजनीतिक दल तुष्टिकरण की राजनीति के भरोसे पर ही अपने परिवार कल्याण का भरण-पोषण कर रहे हैं। उन राजनीतिक दलों का कार्य ही अराजक तत्वों की पीठ थपथपाना है। ड्रोन कैमरे एवं घटना स्थल पर लगे कैमरों में संभल के अपराधियों के चेहरे स्पष्ट नजर आ रहे हैं। उन अराजक तत्वों की पहचान उजागर करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से परहेज क्यों किया जाए? मेरा मानना है कि अराजक तत्वों पर ही कठोर कार्रवाई न हो, अराजक तत्वों को उकसाने वालों पर भी की जाए।

डॉ. सुधाकर आशावादी, मेरठ

स्वागतयोग्य पहलकदमी

दिल्ली से कश्मीर का सफर अब दिल की धड़कन सा आसान होगा। कश्मीर, जो इतिहास और प्रकृति की गोद में बसा है, जल्द ही जन्नत बन जाएगा। 26 जनवरी, 2025 से ट्रेन सेवा शुरू होगी। सोचिए, कितना कम होगा यात्रा का समय! सुरंगों की चिंता भी दूर होगी। खासकर सर्दियों में, जब बर्फ सड़कें ढक लेती हैं। ट्रेन सेवा एक नया भरोसा लेकर आएगी। यह न सिर्फ स्थानीय लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगी, बल्कि पर्यटकों को भी आमंत्रित करेगी। कश्मीर एक ग्लोबल पर्यटन स्थल बनेगा। स्थानीय निवासियों के लिए आय के नये रास्ते खुलेंगे। संस्कृतियों का अद्भुत मेल होगा, और एकता की भावना और मजबूत होगी। सरकार का यह कदम सच में काबिल-ए-तारीफ है!

अनामिका पांडेय, आईएमसी, जम्मू
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिन्या काजी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, रोकड़-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सहयोग बल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश सिंह*।
मुद्रण - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, मुद्रण - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 107 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संकलन तथा कानूनी बातों के लिए उत्तरदायी

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 246

जीडीपी में तीव्र गिरावट के मायने

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा गत सप्ताह जारी किए गए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों ने विश्लेषकों को चौंका दिया। अधिकांश लोगों को यह अंदेशा तो था कि मांग में कमी जीडीपी में भी नजर आएगी लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर केवल 5.4 फीसदी रह जाएगी जो सात तिमाहियों में सबसे कम दर है। रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्री खासतौर पर निराश होंगे क्योंकि उन्होंने अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में सात फीसदी की वृद्धि दर का अनुमान पेश किया था। वित्त वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था केवल छह फीसदी की दर से बढ़ी थी और अब रिजर्व बैंक को पूरे वर्ष के लिए 7.2 फीसदी के वृद्धि अनुमान पर पुनः विचार करना होगा। दूसरी तिमाही के दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने वृद्धि पर असर डाला था। उस अवधि में उसमें साल-दर-साल आधार पर केवल केवल 2.2 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली थी जबकि पहली तिमाही में 7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। निर्माण क्षेत्र में भी धीमापन आया और खनन क्षेत्र में भी। हालांकि कृषि क्षेत्र पिछले साल की समान अवधि के 1.7 फीसदी की तुलना में 3.5 फीसदी की दर से बढ़ा।

अनुमान से कम वृद्धि दर ने नीति प्रबंधकों के लिए जटिलता बढ़ा दी है और कई सवाल पैदा किए हैं। यह बात ध्यान देने लायक है कि अगले आम बजट की प्रस्तुति के पहले ये जीडीपी के आखिरी आंकड़े हैं। यह सही है कि एनएसओ चालू वित्त वर्ष के पहले अग्रिम अनुमान जनवरी 2025 में जारी करेगा। इन अनुमानों में अतिरिक्त सूचना को शामिल किए जाने की संभावना सीमित होगी। चालू वर्ष की पहली छमाही का आर्थिक प्रदर्शन कम से कम दो अहम नीतिगत चुनौतियां पेश करता है। पहली चुनौती है राजकोषीय प्रबंधन। ध्यान देने वाली बात है कि पहली छमाही में नॉमिनल वृद्धि दर 8.9 फीसदी रही। वर्ष के लिए बजट अनुमान 10 फीसदी के नॉमिनल वृद्धि अनुमानों पर आधारित हैं। अगर यही रुझान दूसरी छमाही में भी जारी रहता है तो विशुद्ध संदर्भों में राजकोषीय घाटे को निचले स्तर पर बनाए रखना होगा ताकि जीडीपी के 4.9 फीसदी तक के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। अगर मान लिया जाए कि राजस्व लक्ष्य हासिल होंगे तो इसका अर्थ होगा कम सरकारी व्यय। ताजा आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर तक केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियां बजट अनुमान के 53.7 फीसदी थीं। गत वित्त वर्ष के दौरान तुलनात्मक स्तर 58.6 फीसदी था। व्यय पक्ष की बात करें तो समायोजन की गुंजाइश मौजूद है लेकिन पूंजीगत व्यय की धीमी गति से नीति नियामकों को चिंतित होना चाहिए। वित्त वर्ष के आरंभिक सात महीनों में सरकार ने अपने आवंटन की सिर्फ 42 फीसदी राशि व्यय की जो धीमी वृद्धि को एक हद तक स्पष्ट करता है।

दूसरी नीतिगत चुनौती है आर्थिक गतिविधियों को टिकाऊ बनाना। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार के पूंजीगत व्यय में इजाफा वृद्धि को गति प्रदान करेगा। यह धारणा कुछ हद तक दूसरी छमाही में फलीभूत हो सकती है। बहरहाल, सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए कब तक उच्च सरकारी व्यय पर निर्भर रहेगी। राजकोषीय बाधाओं को देखते हुए पूंजीगत व्यय में निरंतर इजाफा करना मुश्किल होगा। चालू वर्ष में आवंटन जीडीपी के 3.4 फीसदी के बराबर है। उच्च वृद्धि के लिए अन्य कारकों खासतौर पर निजी निवेश को बढ़ाना होगा। मध्यम अवधि के नजरिये से देखें तो बाहरी अनिश्चितता हालात को केवल कठिन बनाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप की जीत ने जटिलताएं बढ़ा दी हैं। मौद्रिक नीति के मोर्चे पर मौद्रिक नीति समिति पर नीतिगत ब्याज दरें कम करने का दबाव बढ़ेगा। एमपीसी को इस सप्ताह के आखिर में होने वाली बैठक में अपने रुख पर टिके रहना चाहिए। मुद्रास्फीति के 6.2 फीसदी के स्तर को देखते हुए बिना सोचे-समझे की गई कोई भी प्रतिक्रिया हालात को जटिल बना सकती है। चाहे जो भी हो, सुस्ती से निपटने के लिए नीतिगत दर में कमी से परे उपाय सोचने होंगे।

भारत का पाकिस्तान में खेलना उचित नहीं

भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के बीच क्रिकेट से जुड़े रिश्तों के टूटने में खेल से जुड़ा कोई विवाद शामिल नहीं है। इसे दो देशों और वहां घट रही घटनाओं से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

इस सप्ताह का विषय क्रिकेट नहीं बल्कि भारत के पड़ोस की भू-राजनीति है। यही वजह है कि इसकी शुरुआत क्रिकेट से हुई। भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की कोई वजह नहीं है। इस मामले में सभी दबावों को नकारा जाना चाहिए। इसका इकलौता समझदारी भरा हल होगा जगह में बदलाव। यह उग्रवाद, उग्रवाद, राष्ट्रवाद, मित्रता या शत्रुता अथवा सार्क (अब कोई पूछ सकता है कि यह क्या था) को पुनर्जीवित करने का मुद्दा नहीं है। यह एक कट्टर क्रिकेट प्रशंसक की क्रूर लेकिन व्यावहारिक बात है। इस समय पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलना भारत, पाकिस्तान या क्रिकेट के खेल, किसी के लिए अच्छा नहीं है। यकीनन कुछ किंतु-परंतु होंगे लेकिन इनका कोई महत्त्व नहीं।

पाकिस्तान का कहना है कि वे आईसीसी विश्व कप खेलने भारत आए थे और भारत भी अन्य देशों में उसके साथ खेलता है तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल सकता? इसका सीधा जवाब है कि उनका देश ऐसी बड़ी प्रतियोगिता की मेजबानी करने की स्थिति में ही नहीं है। यह दो देशों की बात नहीं है। खासकर तब जबकि वहां व्यापक लोकप्रियता और सड़कों पर ताकत रखने वाले एकमात्र राजनीतिक दल के अनुयायियों के बीच भारत-विरोधी भावना इतनी प्रबल हो गई है।

सन 1989 में कराची में एक दर्शक ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत की कमीज फाड़ दी थी। अब अगर वैसी घटना का एक छोटा हिस्सा भी हुआ तो यह बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। इससे दोनों के रिश्ते और खराब हो सकते हैं, चल रही प्रतियोगिता बाधित हो सकती है, और पाकिस्तान के साथ दुनिया में कहीं भी खेलने को लेकर भारत का रवैया और कड़ा हो सकता है। अगर पाकिस्तानी सरकार अपनी 'सड़कों' तक पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है तो भारत में लोगों की राय नाजुक होनी ही है। पाकिस्तान और उसकी क्रिकेट को लेकर पुराना लगाव कमजोर पड़ चुका है। दोनों देशों और क्रिकेट के लिए यह अहम है कि हम जोखिम को कम करें।

भारतीय उपमहाद्वीप विश्व क्रिकेट का नया घर है जहां क्रिकेट देखने वाले कुल लोगों में से 95 फीसदी लोग रहते हैं लेकिन इसकी भूराजनीतिक स्थिति इस खेल की त्रासदी है। पाकिस्तान की राजधानी में हाल ही में एक शक्तिशाली प्रदर्शन हुआ है जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण हाल ही में बांग्लादेश से आईसीसी विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली गई और उसे संयुक्त अरब अमीरात को दे दिया गया। अफगानिस्तान के क्रिकेटर, जिनकी क्रिकेट भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे तेजी से सुधर रही है, पाकिस्तान में एक मैच नहीं खेल सकते। बल्कि उन्होंने खेला ही नहीं है।

पाकिस्तान इकलौता देश है जहां खेलने गए दूसरे मुल्क के क्रिकेटरों पर हमले किए गए। ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार हुआ। 1989 में श्रीकांत से जुड़ी घटना के बाद 2009 में लाहौर में टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंकाई क्रिकेटरों पर आतंकी हमला हुआ था। बहरहाल तब से अब तक काफी सुधार हुआ है। टेस्ट खेलने वाले सभी प्रमुख देश पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं और कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं। लेकिन मौजूदा अनिश्चित समय में भारतीय टीम के लिए वहां जाना काफी जोखिम भरा हो सकता है।

हम जानते हैं कि हम बिना बदले में क्या सुनने को मिल सकता है। दर्शकों और पत्रकारों के बीजा का मुद्दा, अहमदाबाद में भीड़ का पक्षपाती रवैया और बाबर आजम तथा मोहम्मद रिजवान का विरोध। बदकिस्मती यह बताता है कि भारत और पाकिस्तान के साथ किस तरह की समस्याएं हैं। कई बार जब कोई रिश्ता बहुत कमजोर होता है तो समझदारी इसी बात में होती है कि उन तत्वों को सामने नहीं आने दिया जाए जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान कम से कम ऐसी जगहों पर आईसीसी की प्रतियोगिताओं में एक-दूसरे के साथ खेलते रहें जो दोनों पक्षों के लिए सुरक्षित हों। दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के साथ भी हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां हमारे पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने हाल ही में अच्छे माहौल में क्रिकेट खेली है। यह सब बताता है कि हमारे पड़ोस में भूराजनीतिक हालात कितनी तेजी से कमजोर पड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह आईपीएल की नीलामी में 12 बांग्लादेशी खिलाड़ी सूचीबद्ध थे लेकिन एक भी खिलाड़ी को नहीं चुना गया। आईपीएल की शुरुआत के बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी प्रतिभाशाली नहीं हैं, बात बस यह है कि अब हर कोई राजनीतिक जोखिम का आकलन करके चल रहा है। इसमें प्रशंसकों की भावनाओं को भी शामिल कर लीजिए।

इस क्षेत्र के बदलते भूराजनीतिक हालात को आईपीएल के जरिये भी महसूस किया जा सकता है। 26/11 के आतंकी हमले के पहले तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खूब पसंद किया जाता था और उनकी खूब मांग थी। उसके बाद जिस तरह पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से पश्चाताप देखने को नहीं मिला, उस बात ने टीम के घनघोर प्रशंसकों का भी दिल तोड़ दिया। अब बांग्लादेश भी उसी श्रेणी में आ गया है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि यह अस्थायी होगा।

भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट के टूटे रिश्ते केवल क्रिकेट के बारे में नहीं बल्कि देशों की स्थिति के बारे में हैं। ये रिश्ते बहुत नाजुक हैं। पाकिस्तान 26/11 के हमले के बाद कभी गलती सुधारता नहीं दिखा। उस हमले के जिम्मेदार खुले घूम रहे हैं और 2019 के बाद से वे अगर कोई बड़ा हमला नहीं कर पाए हैं तो उसकी वजह है भारत द्वारा पुलवामा हमले का कड़ा प्रतिकार। उन्हें पता है कि भारत उनके देश में घुसकर बदला लेगा और भले ही जंग ही क्यों न करनी पड़ जाए।

भारत सरकार में या आम जनता में कोई इस बात पर यकीन नहीं करता है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। उसने अपने यहां मौजूद आतंकी ढांचे तक को नष्ट नहीं किया है। भारतीय जनता की इस धारणा के साथ पाकिस्तान के आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी की बात तक खरी नहीं उतरती। वहां टीम भेजना साहस नहीं होगा बल्कि वह बेवकूफाना हरकत होगी। भारतीय टीम के सुबह पहुंचने और मैच खेलकर शाम को वापस लौटने जैसे विचार पूरे हालात को और खराब करने वाले होंगे।

गत 18 नवंबर को अमेरिकी रणनीतिक विद्वान और क्षेत्र विशेषज्ञ क्रिस्टोफर क्लैरी ने एक्स पर लिखा: 'पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों खुद को ऐसे हालात में पाते हैं जहां मौजूदा सत्ता टिकाऊ नहीं नजर आती है और टिकाऊ सरकार बनाने की कोई मार्ग नजर नहीं आता।'

यह एक बात भारत की कठिनाई को रेखांकित करती है। हमारे पूर्व और पश्चिम में बड़े पड़ोसी देशों में अनिश्चितता बनी हुई है। वहां की सड़कों पर भारत-विरोध का माहौल है। पाकिस्तान में यह बात स्पष्ट है कि परदे के पीछे से कौन चीजों को चला रहा है। बांग्लादेश के बारे में तो हम पूरे भरोसे से यह भी नहीं कह सकते कि जनरल वकार उज-जमां बॉस हैं।

बांग्लादेश में जो शासन है वह अपने आप में विशिष्ट है। यह पहला मौका है जब स्वयंसेवी/एनजीओ क्षेत्र ने किसी देश का शासन संभाला है। वह 17.6 करोड़ की आबादी वाला देश है जिसमें 16 करोड़ मुस्लिम हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुहम्मद यूनुस अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे। यह जरूर सोचा जा रहा है कि वह किस दिशा में जा रहे हैं और उनके बाद कौन। हिंदुस्तान का विरोध उन्हें वहीं तक ले जाएगा। इतिहास बताता है कि इन चीजों का अंत अच्छा नहीं होता।

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले ही आगे बढ़ रही है, सामाजिक संकेतक बेहतर स्थिति में हैं और उसकी प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान की आय के दोगुनी है। अंततः वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा।

तब भारत इस रिश्ते को सुधारने के लिए और कड़ी मशक्कत करेगा। फिलहाल पाकिस्तान मुशर्रफ को हटाने के लिए हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। यही वजह है कि भारतीय टीम के दौरे को लेकर बचीखुची सद्भावना को जोखिम में डालना या राजनीतिक मुद्दा बनाना अभी भी शायद उसके हित में नहीं हो। चूंकि पाकिस्तान उर्दू को अपनी राष्ट्रीय भाषा कहता है इसलिए उचित होगा कि गुलजार की कुछ पंक्तियां उसके लिए पढ़ दी जाएं: सिर्फ एहसास है ये दूर से महसूस करो / प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो।

अर्थव्यवस्था: सामान्यीकरण की ओर कदम

राधिका राव

भारत ने पिछले तीन वर्षों में तेजी से वृद्धि की है जिसमें औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि लगभग 8 प्रतिशत रही है। वित्तीय बाजारों ने वैश्विक स्तर की तुलना में इस शानदार प्रदर्शन पर बेहद उत्साह के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल में, वृद्धि की रफ्तार में कमी आई है जिसे हम सामान्यीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और यह वास्तव में विस्तार के स्थिर दर पर वापसी की तरह है। मजबूत वृद्धि के इस चरण के साथ कुछ क्षेत्रों में चिंताजनक अप्रत्यक्ष प्रभाव थे जिन्हें अब सावधानी पूर्वक व्यापक कदमों से नियंत्रित करने का लक्ष्य है।

हम यहां पर तीन पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, वृद्धि में चक्रीय मंदी लाने वाले कारक। दूसरा, उपभोक्ता के ऋण चक्र में 'तेज बनाम स्थिरता का तर्क। तीसरा, सख्त मौद्रिक नीति की लंबी अवधि के चलते वृद्धि दर पर व्यापक प्रभाव।

पहला, कठिन वित्तीय स्थिति और कुछ अप्रत्याशित और असामान्य कारक (जैसे चुनाव, निर्माण कार्यों में मंदी, परियोजनाओं में देरी, और मौसम की विपरीत परिस्थितियों जैसे भीषण गर्मी और असमय बारिश) के देरी से पड़ने वाले प्रभाव, आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी करने वाले बाधक के रूप में उभरे हैं। हमारे विशेष जीडीपी नाउकास्ट मॉडल के साथ-साथ मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के प्रमुख वृद्धि कारकों के उप-सूचकांकों ने अर्थव्यवस्था की दिशा के बारे में जानकारी दी है।

औद्योगिक गतिविधि और शुद्ध निर्यात (वस्तु एवं सेवाएं) होता रहा है लेकिन निवेश (मशीनरी और उपकरण) और खपत वित्त वर्ष के मध्य में पिछड़ गए। नियामकीय सख्ती वाले कदमों की वजह से असुरक्षित ऋण कम हो गए हैं। इसके साथ ही, महंगाई को कम करने के लिए सरकार की कोशिशों के कारण उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच तनाव बढ़ा है और इसकी कुछ कीमत अर्थव्यवस्था चुका रही है।

आखिर में, निजी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में वृद्धि के स्पष्ट संकेत अभी नहीं दिख रहे हैं। हमारे पिछले शोध में यह बात साबित हुई थी कि भविष्य में वृद्धि की उम्मीदें और कंपनियों का मुनाफा ही आमतौर पर कंपनियों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। निर्यात में विविधता लाने यानी अधिक मात्रा में विनिर्माण उत्पादों और बेहतर सेवा व्यापार (विशेषकर पेशेवर सेवाएं) की तरफ बढ़ने से निर्यात के योगदान की अस्थिरता कम हो गई है।

सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी हो रही है और राज्यों को केंद्र सरकार से रियायती कर्ज मिलने की उम्मीद है जिससे राज्य सरकारों के पास भी ज्यादा खर्च की गुंजाइश बनेगी। हाल में हुए राज्य चुनावों के नतीजे दर्शाते हैं कि राजनीतिक स्थिरता भी बुनियादी ढांचे पर खर्च जारी रखने के लिए जरूरी है।

केंद्र सरकार को अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच अपने पूंजीगत खर्च को पिछले साल की तुलना में 52 प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि पिछले समय की कमी पूरी की जा सके जो बजटीय लक्ष्य को हासिल करने में एक बड़ी चुनौती है। उपभोग की रफ्तार धीमी रहने की संभावना है। दूसरी छमाही में महंगाई कम होने, नीतियों में सख्ती कम होने और सरकारी खर्च बढ़ने से मामूली तेजी आने की उम्मीद है जिसके कारण हमारी वृद्धि दर का अनुमान 6.7 प्रतिशत है।

हम उम्मीद करते हैं कि मध्यम अवधि में वृद्धि दर 6.5-6.6 प्रतिशत पर स्थिर होगी, जो वित्त वर्ष 2019-20 की रफ्तार से अधिक मजबूत है लेकिन महामारी के बाद के वर्षों की तुलना में कम है। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 9-9.5 प्रतिशत और विदेशी मुद्रा भंडार की धारणाओं के साथ जोड़कर हम यह देखते हैं कि भारत की नॉमिनल जीडीपी (अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) इस दशक के भीतर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बन सकती है।

दूसरा, ग्राहकों के कर्ज लेने की रफ्तार में भी तेजी बनाए रखने या सावधानी बरतने की बहस चल रही है। बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा ऋण में दोहरे अंकों की उच्च वृद्धि दर्ज की जिससे अधिकारियों ने बिना कुछ गिरवी रखे दिए गए असुरक्षित कर्जों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई चिंताजनक क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में कर्ज न चुकाने की दर शामिल है, जो मार्च 2024 तक अन्य सभी उपभोक्ता ऋण उप-श्रेणियों की तुलना में अधिक थी। आरबीआई ने इस खंड में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) ऋणदाताओं और लघु वित्त बैंकों के जोखिम स्तर को भी जाहिर किया। उपभोक्ताओं को कर्ज मिलने में आसानी होने के साथ ही समान वक्त पर खर्च कम हो रहा है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि असली चिंता कर्ज के स्तर को लेकर है।

पिछली आठ तिमाहियों में, कुल मिलाकर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू कर्ज बढ़ रहा है। संपत्ति के मूल्य बढ़ने से घरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन उच्च आय वाले वर्ग ज्यादा मजबूत हैं। जीवनयापन की लागत में लगातार वृद्धि से खरीदने की क्षमता पर दबाव बढ़ रहा है। महामारी के बाद से, जीडीपी डिफ्लेटर 25 प्रतिशत बढ़ गया है (2019 सूचकांक)। कर्ज कम करने की इच्छा से निकट भविष्य में ऋण खपत में कमी आ सकती है। जीवनयापन की लागत को स्थिर रखना और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार के लिए निकट और मध्यम अवधि में जरूरी काम होंगे।

तीसरा, मौद्रिक नीति समिति ने सतर्कता का रुख बनाए रखा है क्योंकि महंगाई अभी ज्यादा है और ब्याज दर कम करने की गुंजाइश बहुत कम है। हाल के महीनों में खाद्य कीमतों, खासकर सब्जियों की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। अब सवाल है कि क्या सरकार को सिर्फ खाने-पीने की चीजों की कीमतों को छोड़कर बाकी चीजों की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कुछ तर्क हैं। खरीफ फसलों के आने से कीमतों में कमी आने की उम्मीद है साथ ही इस समय केवल एक-तिहाई चीजें ही 4 प्रतिशत से अधिक महंगी हुई हैं। हमारे हिसाब से भी औसतन महंगाई भी बहुत ज्यादा नहीं है।

दूसरी बार महंगाई बढ़ने की चिंता अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है क्योंकि भविष्य में महंगाई, ग्रामीण/शहरी मजदूरी वृद्धि और कारोबारी लागत से जुड़ी उम्मीदें नियंत्रण में हैं। लंबी अवधि तक सख्त मौद्रिक नीति अपनाने से वृद्धि के मोर्चे पर अधिक नुकसान हो सकता है। इस तर्क में एकमात्र जोखिम, मुद्रा से जुड़ी हुई है जो डॉलर की बोली और पोर्टफोलियो बिक्री के दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड स्तर की साप्ताहिक गिरावट से अंदाजा मिलता है कि मुद्रा को नए क्रमिक निचले स्तर पर जाने से रोकने के लिए बड़े हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। फिर भी, यह तर्क दिया जा सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूत वृद्धि ऐसे ही 'मुश्किल दिनों' के लिए थी। प्रगतिशील नीतिगत पूर्वाग्रह 2025 की शुरुआत में दरों को कम करने की गुंजाइश पैदा कर सकता है।

(लेखिका डीबीएस बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक हैं)

आपका पक्ष

डिजिटल भुगतान: सुविधा के साथ बढ़ता खतरा

डिजिटल भुगतान ने हमारे जीवन को निश्चित रूप से आसान बना दिया है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ गया है और वह है साइबर ठगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। नकली यूपीआई ऐप, फर्जी क्यूआर कोड और डिजिटल अरेस्ट का इस्तेमाल करके वे लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं। इन अपराधियों का कोई देश नहीं होता, वे दुनिया के किसी भी कोने से हमला कर सकते हैं। इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार और बैंक लगातार नए उपाय कर रहे हैं। लेकिन इन उपायों के बावजूद भी साइबर अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लगाना मुश्किल है। इसलिए हमें खुद को सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपने बैंक खातों की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए और हमेशा विश्वसनीय ऐप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। डिजिटल भुगतान के फायदों का लाभ उठाते हुए हमें सावधान भी रहना होगा। हमें साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। साथ ही, सरकार को भी इस मुद्दे पर और अधिक सख्त कदम उठाने चाहिए।

राजूराम प्रजापत, नागौर

यूपीआई जैसी सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं

सड़क हादसे रोकने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी

देश में नाबालिगों की, वाहन चलाते समय तेज रफ्तार के कारण हुई दुर्घटनाओं बढ़ती संख्या चिंताजनक है। प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में बड़ी संख्या में नाबालिगों की जान चली जाती है। वजह तो इसके पीछे बहुत-सी हैं। स्पीड ब्रेकर, खराब सड़क, वाहनों की फिटनेस पर ध्यान न देना आदि। लेकिन सबसे ज्यादा जो वजह सामने आती है वह है, इनकी अनियंत्रित गति। हाईवे पर वाहन तीव्र गति से चलते हैं, जिससे बड़े हादसे हो जाते हैं। युवा तेज गति से बाइक दौड़ाते हुए नजर आ जाते हैं। इन वाहनों की गति इतनी अधिक होती है कि जरा-सी भी चूक हुई, तो उनकी और सामने वाले कि जिंदगी पर संकट आ सकता है। बहुत-से नाबालिग बाइक से स्टंट करते हुए दिख जाते हैं। इस तरह वाहन चलाने पर अंकुश लगाने के लिए अभिभावकों के साथ पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। सड़क हादसे रोकने के लिए जन-जागरूकता बेहद जरूरी है। स्कूल के पाठ्यक्रम में इस विषय को जोड़ना चाहिए। सड़क सुरक्षा का दायित्व हर नागरिक पर है। परिवार में सभी को समय-समय पर यातायात नियमों से जुड़ी जानकारी दी जानी चाहिए। युवाओं को समझना चाहिए कि सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाएं। दरअसल, सड़क हादसे रोकने हेतु इसके लिए जिम्मेदार कारणों पर गंभीरता से विचार करना होगा। नशा भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुल मिलाकर, सड़क हादसे रोकने के लिए हमें सर्वप्रथम यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और भारी वाहनों का शहर के अंदर प्रवेश रोकना चाहिए। सड़कों पर गतिरोधकों का निर्माण करना चाहिए। साथ ही सड़कों का रखरखाव भी होना चाहिए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

तिरुवनंतपुरम के विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर रविवार को कंटेनर जहाज एमएससी जुआनित पहुंचा।

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 2 दिसंबर 2024

अच्छी नहीं अनिश्चितता

यह भी महाराष्ट्र की समकालीन राजनीति की एक दिलचस्प विशेषता ही कही जाएगी कि प्रचंड जनादेश के बावजूद सरकार गठन की प्रक्रिया मुश्किलों से घिरी दिख रही है। अपनी तरफ से शपथ ग्रहण की तारीख घोषित करके BJP ने यह कोशिश जरूर की है कि सभी मतभेद तब तक सुलझा लिए जाएं, लेकिन इस कदम का भी कितना और कैसा असर होगा, इसे लेकर तत्काल कोई नतीजा निकालना मुश्किल है।

महाराष्ट्र में सरकार बनने में देरी

असमंजस से असहजता | राजनीति में हालांकि इस तरह के असमंजस की स्थिति बनती रही है, लेकिन जिस तरह की अप्रत्याशित जीत महायुति के हिस्से में आई है, उसके बाद इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। इस देरी से जहां महायुति के घटक दलों में आपसी विश्वास और सामंजस्य की कमी का संदेश जा रहा है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर BJP की स्थिति असहज हो रही है, वहीं विपक्षी खेमे को भी टीका-टिप्पणी का मौका मिल रहा है।

बीमारी की आड़ | फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे एकनाथ शिंदे के अचानक सातारा जाकर बैठ जाने के पीछे भले ही औपचारिक तौर पर उनकी सेहत खराब होने का हवाला दिया जा रहा हो, उनकी पार्टी के ही कई नेता इसे परोक्ष धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि शिंदे इस तरह से अपने गांव तभी जाते हैं जब कोई 'बड़ा फैसला' करना होता है। इसलिए शिंदे क्या करेंगे, इस बात को लेकर भी अटकलें लग रही हैं।

वैकल्पिक समीकरण नहीं | सवाल अगर ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा तो उसके पीछे चुनाव नतीजों से निकले ठोस राजनीतिक समीकरण ही हैं, जिनमें किसी वैकल्पिक व्यवस्था की गुंजाइश नहीं दिख रही। BJP और अजित पवार की अगुआई वाली NCP के विधायकों का जोड़ ही सुविधानाबक बहुमत जुटा देता है। अजित पवार जिस मजबूती से BJP के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसमें एकनाथ शिंदे कोई भी फैसला करें, BJP नेतृत्व का सिरदर्द नहीं बन सकते।

सबका साथ, सबका विश्वास | फिर भी BJP के लिए सबको साथ लेना और सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। आगामी मुंबई महानगरपालिका के चुनाव तय करेंगे कि मुंबई में किसका दबदबा रहेगा। मुंबई और ठाणे में शिंदे के प्रभाव को देखते हुए BJP उन्हें खुद से दूर करके उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कोई मौका नहीं देना चाहेगी। लिहाजा, उन्हें मनाना BJP नेतृत्व के लिए जरूरी है।

दूर हो अनिश्चितता | कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र जैसा अहम मोर्चा फतह करने के बाद भी इस तरह का अनिश्चय NDA और महायुति की तरफ से कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहा। यह जितनी जल्दी दूर हो, उतना ही अच्छा है।

चक्र-व्यू

भाषा ने खोले राज़

राहुल पाण्डेय

दुनिया की अब तक की सबसे ज्ञात वर्णमाला मिली है, लगभग 4400 साल पुरानी। तकरीबन 20 साल की रिसर्च के बाद इतिहासकारों ने पाया है कि सीरिया में मिली यह वर्णमाला 2400 ईसा पूर्व की है। वैज्ञानिकों को कब्र से उंगली जितनी बड़ी मिट्टी की चार नलियां मिली हैं, जिनमें आठ अलग-अलग प्रतीक उकेरे गए थे। अभी तक सबसे पुरानी वर्णमाला प्रोटो-साइनेटिक स्क्रिप्ट है। लगभग 1900 ईसा पूर्व की यह स्क्रिप्ट इजिप्ट की है और माना जाता है कि यह कनानी भाषा में है। भाषा विज्ञानियों में इसे वर्णमाला मानने या न मानने को लेकर बहस है। एक तर्क यह है कि साइनेटिक स्क्रिप्ट चित्रलिपि वाली है, जिसे वर्णमाला इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि ये शब्दों को दर्शाने के लिए चित्र का उपयोग करते हैं। उनमें ध्वनि के हिसाब से भी चित्र नहीं होते। लेकिन सीरिया से जो वर्णमाला मिली है, वह चित्रलिपि नहीं है। उसमें शब्द हैं। वैज्ञानिकों ने उन्हें पढ़ने की कोशिश भी की है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक मिट्टी की नलियों में बने प्रतीकों को जोर से बोला जाए तो उनकी ध्वनियां तकरीबन वैसी निकलती हैं, जैसी कि a, i, k, l, n, s और y बोलने पर निकलती हैं। फिर भी ये अक्षर किसी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाते। हालांकि यूनिवर्सिटी के भाषा विशेषज्ञ थियोडोर लुईस का सुझाव है कि इस हिसाब से जोड़कर पढ़ें तो इसमें सिल्लुनु नाम का एक शब्द मिलता है। सिल्लुनु शब्द सीरिया के एक प्राचीन शहर उगारिट के ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि उगारिट में कभी कनानी भाषा बोली जाती थी, जो मजदूरों और गुलामों की भाषा थी, न कि राजपरिवारों की शाही भाषा।

इस खोज से यह कह सकते हैं कि 2400 ईसा पूर्व इस भाषा में कोई सिल्लुनु रहा होगा। कौन रहा होगा यह सिल्लुनु? इतिहास का अब तक का सबसे पुराना ज्ञात शब्द कुशीम है, और यह भी सीरिया से ही मिला है। माना जाता है कि सीरिया के उरुक (वर्का) से मिला यह शब्द लगभग 3400 ईसा पूर्व पुराना है। इस शब्द के बारे में इतिहासकार युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि कुशीम किसी पदाधिकारी के पद का भी नाम हो सकता है, या किसी खास व्यक्ति का नाम भी। यह नाम हिसाब-किताब की तख्ती के साथ मिला है, जिसमें लिखा है- '29,086 माप्रा जौ 35 महीने कुशीम।' इसलिए यह भी कह सकते हैं कि कुशीम कोई मुनीम रहा होगा। अगर कुशीम सचमुच कोई नाम ही है तो यह इतिहास का पहला व्यक्ति हो सकता है, जिसका नाम हमें ज्ञात है और वह कोई राजा नहीं, बल्कि मुंशी है। कुशीम के आने के बहुत दिनों बाद इतिहास से छनकर एक और नाम आया है- सिल्लुनु। इस बार यह नाम किसी मुंशी नहीं बल्कि किसी सेठ के परिवार का लग रहा है। इतिहासकारों को कब्र से सोने-चांदी के जेवर भी खूब मिले हैं।

एकदा

महानता के गुण

बचपन में नरेंद्र बेहद चंचल स्वभाव के थे। स्कूल में जाकर भी उनकी चंचलता में कोई कमी नहीं आई। एक दिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे और नरेंद्र अपने मित्रों के साथ बातचीत में मशगूल थे। अध्यापक की नजर जब नरेंद्र की टोली पर पड़ी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नरेंद्र की टोली में से हर एक छात्र को खड़ा करके उससे वही प्रश्न पूछा जिसका जवाब वह कुछ देर पहले बता चुके थे। कोई भी छात्र जवाब नहीं दे पाया। आखिर में अध्यापक ने नरेंद्र को खड़ा करके अपना प्रश्न

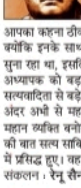
Subrata Dhar

दोहराया। नरेंद्र ने उस सवाल का सटीक उत्तर दे दिया। सही जवाब सुनकर अध्यापक ने नरेंद्र को बैठने का इशारा करते हुए अन्य छात्रों को खड़ा रहने कोकहा। कहने पर भी जब नरेंद्र नहीं बैठे तो अध्यापक बोले, 'बेटा, तुम्हारा जवाब सही है, इसलिए तुम बैठ सकते हो। ये सभी पढ़ाते समय आपस में बात कर रहे थे, इसलिए इन्हें सजा मिली है।' इस पर नरेंद्र ने कहा, 'सर, आपका कहना ठीक है, लेकिन इनके साथ सजा मुझे भी मिलनी चाहिए क्योंकि इनके साथ मैं भी बातों में लगा हुआ था। मैं ही इन्हें ये बातें सुना रहा था, इसलिए मैं भी बराबर का दोषी हूं।' नरेंद्र की बात सुनकर अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उस बच्चे की निर्भीकता और सत्यवादिता से बड़े खुश हुए और पीठ थपथपाते हुए बोले, 'बेटा, तुम्हारे अंदर अभी से महानता के गुण झलक रहे हैं। तुम एक दिन देश के महान व्यक्ति बनोगे और इस देश का नाम रोशन करोगे।' अध्यापक की बात सत्य साबित हुई। नरेंद्र पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। वह आज सभी के प्रेरणास्रोत हैं।

संकलन : रेनू सैनी

सुप्रीम कोर्ट ने अंतहीन-सी लग रही धर्मनिरपेक्षता की बहस को आख़िरकार विराम दे दिया

संविधान से क्यों नहीं हटेगा सेकुलर शब्द

राजेश चौधरी

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े जाने को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। इससे जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दी। 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन के जरिये प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए थे। इसे लेकर शीर्ष अदालत के सामने सवाल उठाए गए थे। इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट कई बार पहले भी व्यवस्था देते हुए कह चुका है कि सेकुलरिज्म संविधान का मूलभूत अंग है।

विवाद का जड़ | संविधान की मूल प्रस्तावना में सेकुलर शब्द नहीं था। संविधान सभा में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तब संविधान की प्रस्तावना में 'संप्रभुतासंपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य' ही लिखा गया। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1976 में संशोधन के जरिये संविधान की प्रस्तावना में 'संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' लिखा गया। इसी संशोधन को अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते खारिज कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने मामले को लार्जर बेंच के पास भेजने से भी इनकार कर दिया।

संसद को है अधिकार | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है। उसे यह अधिकार अनुच्छेद-368 के तहत हासिल है। अदालत ने कहा कि 44 साल बाद संशोधन प्रक्रिया को अमान्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सेकुलरिज्म संविधान की मूलभूत विशेषता है। मूल रूप से, धर्मनिरपेक्षता का विचार समानता के अधिकार के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो संवैधानिक ढांचे के पैटर्न को दर्शाने वाले बुनियादी ताने-बाने में गहराई से बुना हुआ है।

धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या | भारत ने समय के साथ धर्मनिरपेक्षता की अपनी व्याख्या विकसित की है, जिसमें राज्य न तो किसी धर्म का समर्थन करता है और न ही किसी धर्म का पालन और अभ्यास करने से मना करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय संदर्भ में समाजवाद का मतलब भी खास आर्थिक नीतियां अपनाने के लिए बाध्य करना नहीं है। समाजवाद का अर्थ सिर्फ इतना है राज्य की प्रतिबद्धता एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सभी नागरिकों को समान अवसर सुनिश्चित करने की है।

क्यों अहम थी बहस
- पिछली करीब आधी सदी से जारी थी
- सोशलिस्ट और सेकुलर पर थी आपत्ति
- कोर्ट ने लार्जर बेंच को भी नहीं भेजा केस

अहम फैसले | केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में 1973 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की संविधानपीठ ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया था। कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ऐसे ही एस.आर. बोम्मई बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की आधारशिला है। आर.सी. पौड्याल बनाम केंद्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि शुरू से ही संविधान का अभिप्राय सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देने और उनके साथ बिना भेदभाव के व्यवहार करने का था। एम. इस्माइल फारूकी बनाम केंद्र सरकार मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता और सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हासिल है।

समानता के अधिकार का पहलू | धर्मनिरपेक्षता भारत की संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व है। इसे समानता के अधिकार का एक पहलू माना जाता है, जो संविधान की मूल संरचना के ताने-बाने में समाहित है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता रहा है कि प्रस्तावना में जिस तरह से सेकुलर व सोशलिस्ट शब्द संविधान संशोधन के जरिये डाले गए क्या उसी तरह से संविधान संशोधन के जरिये इन्हें हटाया भी जा सकता है?

छेड़छाड़ नहीं हो सकती | कानून के जानकार व सीनियर एडवोकेट एमएल लाहोटी बताते हैं कि अब संविधान संशोधन के जरिये सेकुलर शब्द प्रस्तावना से हटाया नहीं जा सकता। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा था कि संविधान संशोधन का संसद को अधिकार है, लेकिन वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में यह बात कह चुका है कि प्रस्तावना भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसे में अब उसे नहीं छेड़ा जा सकता।

संविधान की भावना और प्रारूप | सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों और संविधान को देखें तो संविधान की भावना और प्रारूप ही सेकुलर है। अनुच्छेद-15, 16, 25, 26, 27, 28 व 29 ये तमाम मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं और ये सेकुलर नेचर के हैं। इनमें समानता से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता तक के अधिकार शामिल हैं। ऐसे में सेकुलर शब्द को संविधान संशोधन के जरिये भी नहीं हटाया जा सकता।

मूलभूत फीचर | सेकुलरिज्म हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हमेशा हिस्सा रहा है। शीर्ष अदालत ने कई बार अपने जजमेंट में कहा है कि सेकुलरिज्म भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हमेशा से पार्ट था और उसका पार्ट है। अगर आप समानता के अधिकार को देखते हैं तो वहां भी भाईचारे और बंधुत्व का इस्तेमाल किया गया है। यह साफ तौर पर संदेश देता है कि सेकुलरिज्म भारतीय संविधान का मूलभूत फीचर है।

ठंडे पानी से नहाकर देखिए, बदल जाएगी धारणा

बड़े फैसले करना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन कुछ छोटे फैसले भी कम परेशान नहीं करते। क्या पहनूं, क्या खाऊं, कहां जाऊं, और अब चूंकि सर्दियों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, तो इसी में जोड़ लीजिए, कैसे नहाऊं। पानी की पहली धार का सामना कैसे करना है, इस मौसम की सुबह का सबसे मुश्किल सवाल यही है। मन बार-बार तैयार होता है और बार-बार बदलता है। हाथ आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। इस मुद्दी समझ आता है कि क्यों चंचल कहा गया है मन को। वह टिक ही नहीं पाता अपने फैसले पर। उसके लिए अपनी बात पर कायम रहना और मुश्किल हो जाता है जब पानी ठंडा हो। गजब कशमकश चलती है तब दिल-दिमाग के बीच। इसी मुश्किल से बचने के लिए ठंड आते ही पानी गर्म करना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन, पानी गर्म करने से वह आनंद भी क्या भाप में नहीं उड़ जाता, जो ठंडे पानी से नहाने पर आता है?

हमें हर जगह रोमांच चाहिए। इसी की तलाश में हम पहाड़ चढ़ते हैं और घाटी भी उतरते हैं। यही तलाश हमें उकसाती है एक बाल्टी बर्फ के पानी से नहाने या जमी झील में छलांग मारने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए। ठंडे पानी से नहाना रोमांच के उसी अनुभव से बार-बार गुजरना है। और ऐसा हर अनुभव जीत का एक अहसास लेकर आता है। दिन की शुरुआत इस विजयी अहसास से करने से अच्छा क्या होगा? रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि, 'आप केवल खड़े होकर और पानी को घूरकर समुद्र पार नहीं कर सकते।' यानी सफलता के लिए कोशिश तो करनी ही होगी।

पहला कदम कभी आसान नहीं होता, ठंडे पानी के पहले

AI Image

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

मग की तरह। आगे बढ़ने के बजाय हम धारणा बनाने लगते हैं और यही जीवन की अन्य चीजों के साथ भी है। लोग, जगह, काम - कुछ ऐसा नहीं बचता, जिसके बारे में हम पहले से सोचना न शुरू कर दें। लेकिन, धारणाएं हमेशा सही नहीं होतीं। ये टूटती हैं, बशर्ते सच जानने की कोशिश की जाए। इसके लिए उठाना पड़ता है पहला कदम। हॉलिवुड एक्टर विल स्मिथ के अनुसार, 'पहला कदम यह है कि आपको खुद से कहना है कि आप कर सकते हैं।' जब आप ऐसा कह देंगे और फिर कर लेंगे, तो पता चलेगा कि सोचा हुआ कितना गलत था।

ठंडे पानी से नहाने पर रिलीज होता है डोपामाइन हार्मोन। इसे फीलगुड वाला हार्मोन भी कहते हैं। मूड अच्छा हो जाता है इससे। वैसे, बढ़ने के लिए तो शरीर में इसका स्तर मोबाइल फोन पर रील्स देखकर भी बढ़ जाता है, लेकिन वह होती है लत। रील्स और शॉर्ट विडियो लती बना सकते हैं, ठंडा पानी नहीं। स्क्रीन से हटते ही मूड दोबारा बिगड़ सकता है, जबकि कुछ रिसर्च के मुताबिक कोल्ड वॉटर शॉवर से रिलीज हुए डोपामाइन का असर तीन घंटे तक रह सकता है। ठंडा पानी ज्यादा सचेत बनाता है और स्फूर्ति से भरता है। इसकी वजह से Noradrenaline नाम के केमिकल का स्तर बढ़ जाता है वॉडी में। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी वजह से ठंडे पानी से नहाने के बाद लगता है कि दिमाग एकदम से खुल गया।

ठंडा पानी हिचक तोड़ता है और हिम्मत भरता है। बच्चों को नहलाते समय जब कहा जाता है कि ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो यह बात बस हौसला देने के लिए नहीं होती। इसके पीछे की वजह है ठंडे पानी की खासियत। तभी तो संजीव कुमार भी इतने मजे से यह गाना गुनगुनाते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं।

शेयर करें अपने अनुभव
जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद मालूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें-'जीवन आनंद'

जान दांव पर क्यों लगाते हैं ये दीवाने

मृत्युंजय राय

भूटान में पहाड़ों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। 6,000 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को लेकर ऐसी बंदिश है क्योंकि वहां के लोग पहाड़ों को पवित्र मानते हैं। कैलाश पर्वत पर भी धार्मिक मान्यताओं की वजह से पर्वतारोहण की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसे गिने-चुने मामलों को छोड़ दें तो पर्वतारोहण का आकर्षण न सिर्फ समय के साथ इंसानों में बढ़ा है बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से यह पहले की तुलना में कम जोखिम वाला और आसान भी हो गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए बढ़ती भीड़ भी इसकी गवाही देती है, जिसे दुर्गम माना जाता है और उस पर विजय की कोशिशों में अच्छी-खासी तादाद में लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि इंसानों को पहाड़ क्यों सदियों से आकर्षित करते रहे हैं? क्यों इंसान उन पर विजय पाना चाहता है और इसके लिए जान की बाजी लगाने तक को तैयार है?

AI Image
विचार विंडो

इसी सवाल का जवाब **THE WHITE LADDER: Triumph and Tragedy at the Dawn of Mountaineering** नाम की किताब में दिया गया है, जिसे लिखा है डेनियल लाइट (Daniel Light) ने। किताब में मशहूर पर्वतारोही जॉर्ज मेलरी का एक किस्सा भी दिया गया है। जब एक रिपोर्टर ने जॉर्ज से पूछा कि वह माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था, '...क्योंकि माउंट एवरेस्ट धरती पर है।'

खैर, हिमालय को लेकर एक और किस्सा जर्मन पर्वतारोही और साइंटिस्ट Adolph Schlagintweit से जुड़ता है। 1854 में वह अपने भाइयों के साथ हिमालय की जियोग्राफी और कल्चर की स्टडी करने निकले। वह चाहते थे कि इस अभियान में जो भी चीजें दिखें, उन्हें दर्ज किया जाए। एडॉल्फ अपने भाइयों के साथ Ibi Gamin पर 22,259 फुट की ऊंचाई तक पहुंच पाए, लेकिन शिखर तक नहीं। उनकी यह कामयाबी तब के यूरोपीय पर्वतारोहियों के लिए प्रेरणा बनी, लेकिन एडॉल्फ के जीवन का अंत काफी दुखद ढंग से हुआ। शिनच्यांग (पहले काशगर) में उन्हें एक वॉरलॉर्ड ने बंदी बना लिया और जासूसी के आरोप में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। हिमालय में ही कराकोरम का एक किस्सा यहूदी मूल के ब्रिटिश पर्वतारोही ऑस्कर एकेनस्टीन से जुड़ता है। ऑस्कर को पर्वतारोहण की तकनीक डिवेलप करने की खातिर भी जाना जाता है। वह कराकोरम पर विजय पाना चाहते थे। उन्हें भी इस अभियान के दौरान खतरनाक लोग मिले। 1902 में उनके अभियान में एलिएस्टर क्राउली नाम के एक सज्जन भी शामिल थे। लेकिन इस दौरान मौसम ने उन लोगों का साथ नहीं दिया और वे अपने टेंट में ही महदूद होकर रह गए। इसलिए उनका यह मिशन पूरा नहीं हो पाया।

एकेनस्टीन के ही समकक्ष अलबर्ट ममरी (Albert Mummery) नाम के ब्रिटिश पर्वतारोही भी थे। वह यूरोप में आल्पस पर्वत की चढ़ाई कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने हिमालय पर विजय पाने की सोची, लेकिन उस वक्त हिमालय पर पर्वतारोहण का तजुर्बा कम ही लोगों को था। 1895 में उन्होंने दुनिया के 9वें सबसे ऊंचे पर्वत पर फतह पाने का प्रयास किया, लेकिन 20,000 फुट की ऊंचाई को पार करने के बाद वह लापता हो गए और उनका शव तक नहीं मिला।

ऐसे किरदारों के जरिये डेनियल लाइट की यह किताब रीडर्स को ऐसी दुनिया में ले जाती है, जिसकी आज शायद ही कल्पना की जा सके। इनमें से कई किरदार असंभव को संभव करने की इच्छा की खातिर साहसिक अभियानों पर जान की बाजी लगाकर निकले। यह चाहते थे कि इस अभियान में जो भी चीजें दिखें, उन्हें दर्ज किया जाए। एडॉल्फ अपने भाइयों के साथ Ibi Gamin पर 22,259 फुट की ऊंचाई

जी का जंजाल कैमरे

प्रणव प्रियदर्शी

नवीनतम तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल भले ही नेक उद्देश्यों से शुरू किया जाए, भारत जैसे देश में यह कैसे महिलाओं के उत्पीड़न का जरिया बन जाता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (CTR) में कैमरों का जाल बिछाए जाने के बाद का अनुभव। इनका खुलासा हुआ है कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों की एक रिपोर्ट से। हालांकि, जैसा कि हर प्रयोग के साथ होता है, इसके फायदे भी देखने में आए हैं। वन्य जीवों और जंगल की संपत्ति की सुरक्षा जैसे मुख्य मकसद से अलग, महिलाओं के जीवन को भी केंद्र में रखें तो इन कैमरों से उन्हें घरेलू हिंसा का प्रतिकार करने में मदद मिली है। मिसाल के तौर पर, तृषांत सिमलाई और क्रिस सेडब्रुक की इस रिपोर्ट में एक ऐसी महिला का जिक्र है, जो पति की गाली-गलौज और मारपीट से बचने के लिए घर के पास लगे कैमरे की जद में चली जाती थी। लेकिन इस सीमित प्रभाव को छोड़ दें तो कैमरों के इस्तेमाल ने उस पूरे इलाके में महिलाओं के पर्सनल स्पेस का बुरी तरह उल्लंघन किया है। एक महिला अनजाने ही सेमी न्यूड अवस्था में कैमरे की जद में आ गई और कुछ नवनियुक्त वनकर्मी न केवल उसकी तस्वीरों तक पहुंच गए बल्कि उसे लोकल और सोशल मीडिया में सार्वजनिक भी कर दिया। इससे नाराज स्थानीय निवासियों ने वनकर्मियों के दफ्तर को जलाने की धमकी दे दी। CTR इस मामले की जांच भी करवा रहा है। पर यह प्रकरण एकाध मामलों तक सीमित नहीं। यहां महिलाओं के मन में यह बात घर कर गई है कि उन पर कैमरों से नजर रखी जा रही। इस वजह से यहां जंगल में जोर से बात करते या गाते हुए चलने का चलन कम हो गया है। यह आदत उन्हें जंगली जानवरों से सुरक्षा देती है। अगर गाते हुए या जोर से बात करते हुए न चला जाए तो अचानक इंसानों की उपस्थिति से चौंककर वन्य पशुओं के हमला करने की आशंका बढ़ जाती है। यह बात सही भी साबित हुई। रिसर्च के दौरान इंटरव्यू देने वाली एक महिला इस बीच बाघ के हमले में मारी जा चुकी है।

AI Image
आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

सर्दी में संतुलन

25 नवंबर के 'जीवन आनंद' कॉलम में प्रकाशित लेख 'अलाव की आग बिना अधूरी हैं सर्दियां' पढ़ा। यह लेख सर्दी के मौसम के साथ जुड़ी एक सुंदर कल्पना को दर्शाता है। सर्दियां अपनी पूरी ठंडक और शीतलता के साथ आती हैं, लेकिन उनका असली आनंद तब तक नहीं मिलता, जब तक अलाव की गर्मी न हो। अलाव न केवल शारीरिक गर्मी प्रदान करता है, बल्कि यह मन को भी गर्माहट और सुखद अनुभव से भर देता है। अलाव के पास बैठना, उसके ताप से शरीर को आराम मिलना बहुत आनंददायक है। यह ठंडक और गर्मी के बीच का संतुलन है।

अनिका गुप्ता, ईमेल से

जीवन की कला

यह पत्र 18 नवंबर के लेख 'जीवन के कैनवास को रंगीन करतीं सब्जियां' से संबंधित है। इस लेख में जीवन को एक कला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे किसी चित्रकार का कैनवास रंगों से भरता है, वैसे ही जीवन को संपूर्ण और स्वस्थ बनाने में सब्जियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सब्जियों के प्राकृतिक रंग, जैसे हरा, लाल, पीला और नारंगी हमारे भोजन को भी रोचक बनाते हैं। साथ में, शरीर के लिए आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर को ऊर्जा और ताजगी देती हैं, जबकि लाल रंग की सब्जियां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं।

कपिल गोयल, पीतमपुरा

दिनचर्या का आनंद

प्रतिदिन सुबह जल्दी जागना आध्यात्मिक और शारीरिक दृष्टि से लाभकारी है। इससे शरीर और मस्तिष्क, दोनों को ऊर्जा मिलती है। मॉर्निंग वॉक, योग और व्यायाम से शरीर स्वस्थ व स्फूर्ति रहता है। मानसिक शांति और एकाग्रता भी बढ़ती है। संध्या समय में टहलना, प्रकृति का आनंद लेना दिनभर की थकान को दूर करता है। जीवन जब व्यस्त होता जा रहा है, तब हमें अपने लिए सुबह-शाम थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए।

जय गोविंद मिश्रा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

महाराष्ट्र : शपथ की तारीख और जगह तय, चेहरा नहीं - एक खबर - थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, चेहरा भी नजर आ जाएगा।

श्वेता श्रीवास्तव

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

मेहनत से मिली चीज़ ही देगी असली ख़ुशी
हरीश बड़थ्वाल

जब हम किसी चीज को मेहनत से प्राप्त करते हैं, तो जो खुशी और संतुष्टि मिलती है, वह सहजता से प्राप्त चीजों से कहीं अधिक होती है। यही कारण है कि जीवन के हर क्षेत्र में मेहनत, साधना और ध्यान का महत्व है। बिना परिश्रम किए भोजन भी ठीक से नहीं पचता। वह बेहतर तरीके से अवशोषित नहीं होता और उससे हमें ज्यादा ऊर्जा भी नहीं मिल पाती। इसी तरह मन, आत्मा और जीवन की संतुष्टि के लिए प्रार्थना, साधना और योग की आवश्यकता होती है। इसलिए कह सकते हैं कि मेहनत करने वाले ही उत्सवी फिजाओं का लुत्फ उठा सकते हैं और वही इसके हकदार भी होते हैं।

जो चीज बिना मेहनत के मिल जाती है, वह टिकाऊ नहीं होती। जैसे लॉटरी, जुआ या सट्टे से मिली रकम। देखा जाता है कि लोग उसे जल्दी से खर्च कर फिर पहले वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया कि विरासत से मिली धनराशि को एक तिहाई लोग दो साल के अंदर ही खर्च कर देते हैं। यही हाल उन लोगों का भी होता है जिन्हें जुगाड़ से नौकरी मिल जाती है या अचानक से बड़ी आमदनी हो जाती है। उन्हें लगता है कि धन-दौलत तो चमत्कार की तरह मिल जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग गरीब लोगों को हीन भावना से देखते हैं।

हम जब किसी चीज को बिना मेहनत के पाते हैं, तो उसका मूल्य नहीं समझ पाते। कोई चीज जब लगातार बिना किसी संघर्ष के मिलती रहे, तो हम आलसी स्वभाव के हो जाते हैं। यही कारण है कि संपन्नता और खुशहाली तब तक स्थायी नहीं रहती, जब तक उसमें अपने श्रम और मेहनत का योगदान नहीं डालते। जब हमें किसी चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो उसका मूल्य समझ में आता है और हम उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं।

सही मायने में देखा जाए तो समृद्धि, शांति, खुशी और संतुष्टि ये चीजें हैं जो हमें केवल तब मिल सकती हैं, जब हम अपनी मेहनत से उन्हें अर्जित करें। यह सोच भी हमारे जीवन के साथ प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई है। अगर हम यह मानते हैं कि हमारी विशेषता केवल हमारे जन्म, परिवार या स्थिति के कारण है, तो हम विकास के रास्ते से हट जाते हैं। यह सोच न सिर्फ हमारी प्रगति को रुकवा देती है, बल्कि हमें उस सच्ची खुशी से भी दूर कर देती है, जो केवल कर्मठता से आती है।

हमें यह समझने की जरूरत है कि जो भी हम चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। अगर हम खुद से कुछ अर्जित करते हैं, तो उसका मोल अधिक होता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी का असली स्वाद तब मिलता है जब हम गर्मी में श्रम करके पसीना बहाते हैं। सेलिब्रेशन का असली आनंद तब आता है, जब हम दिनभर की मेहनत के बाद आराम करते हैं।

जब हम किसी अंतरिक उद्देश्य या उच्च लक्ष्य को और ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। यह आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि जब तक हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को सही दिशा में नहीं लगाते, तब तक जीवन के उद्देश्य को सही से नहीं समझ सकते।

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 2 दिसंबर 2024 प्रकाशक, मुद्रक, प्रिंटर, पब्लिशर और मालिक बेनेट, कोलमैन एंड कं

दैनिक जागरण

घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता

सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा

भुवनेश्वर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के तीन दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री का शामिल होना इस सम्मेलन की महत्ता को रेखांकित करता है। इसकी पुष्टि इस सम्मेलन में आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और खालिस्तान समर्थक समूहों की गतिविधियों के अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अन्य विषयों पर गहन चर्चा से भी होती है। इस सम्मेलन में तीन दिनों तक विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा के निष्कर्षों के अमल में लाने के ठोस उपाय करने से ही आंतरिक सुरक्षा को बल मिलेगा। वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई मोर्चों पर गंभीर चुनौतियां खड़ी होती हुई दिख रही हैं। एक ऐसे समय जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर है तब हर स्तर पर कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर न केवल जोर दिया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे आम लोगों का सुरक्षा परिदृश्य के प्रति भरोसा और अधिक बढ़े। यह अच्छा है कि इस सम्मेलन में साइबर अपराधों पर भी गंभीर चर्चा की गई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि साइबर अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साइबर अपराधी जिस तरह संगठित होकर काम करने लगे हैं, वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि फिलहाल हमारी सुरक्षा एजेंसियां साइबर अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही हैं।

यह ठीक है कि साइबर अपराधों के प्रति लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को साइबर अपराधियों के दुस्साहस का दमन भी करना होगा। अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को एक ओर साइबर अपराधियों पर लगाम लगानी होगी और दूसरी ओर साइबर सुरक्षा के तंत्र को और अधिक मजबूत भी बनाना होगा, क्योंकि साइबर सुरक्षा में सेंधमारी भी एक बड़ी समस्या बन रही है। इस समस्या से निपटना इसलिए कठिन है, क्योंकि अक्सर यह सेंधमारी विदेश में बैठे साइबर अपराधियों की ओर से की जाती है। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में पाकिस्तान प्रेरित और प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के जिन उपायों पर चर्चा हुई होगी, उनका असर जम्मू-कश्मीर में देखने को अवश्य मिलेगा। वर्तमान में पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां की स्थितियां आतंकी और जिहादी तत्वों को बल प्रदान करने वाली हैं। निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन उसे पूरे तौर पर पस्त करने की आवश्यकता है ताकि नक्सली संगठन स्वयं को फिर से संगठित कर सिर न उठा सकें। यह संतोषजनक है कि नए आपराधिक कानूनों पर अमल शुरू हो गया है और इस पर सम्मेलन में चर्चा भी हुई, लेकिन बात तब बनेगी जब आम आदमी को इन कानूनों का सकारात्मक प्रभाव नजर आएगा।

आय संसाधनों में वृद्धि

सशक्त उत्तराखंड तब ही बन सकता है, जब प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसके लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। राज्य के पास अपनी आय के स्रोत सीमित हैं। इन स्रोतों से होने वाली राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था को व्यापक और पारदर्शी बनाकर और कर चोरी पर अंकुश लगाकर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। स्वयं के कर राजस्व से संबंधित जिन क्षेत्रों में इस दिशा में प्रयास हुए हैं, उनके सार्थक परिणाम प्राप्त हुए। जीएसटी में केंद्र से होने वाली प्रतिपूर्ति 30 जून, 2022 को बंद होने के बाद राज्य के सामने आमदनी घटने का संकट खड़ा हो गया था। निरंतर प्रयास से एसजीएसटी में लगातार दो वर्षों में वृद्धि देखी गई। इस क्षेत्र से आय बढ़ाने की संभावनाएं अधिक हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में आमदनी में अधिक वृद्धि हो सकेगी। अभी चालू वित्तीय वर्ष के आठ महीनों में 61 प्रतिशत से अधिक कर राजस्व अर्जित किया जा चुका है। शेष चार महीनों में 40 प्रतिशत से कुछ कम रह गए लक्ष्य को पाने की उम्मीद है। कर और करेतर राजस्व जुटाने में कुछ विभागों के स्तर पर लगातार ढिलाई देखी जा रही है। इनमें वन विभाग और ऊर्जा जैसे विभाग हैं। राज्य का वन क्षेत्रफल 71 प्रतिशत तक पहुंच गया है, लेकिन इससे राजस्व अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल रहा है। विभाग के पास बड़ी मात्रा में चीड़ के पेड़ से निकलने वाला लीसा (रेजिन) है, लेकिन इसके उपयोग और निस्तारण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। इसी प्रकार ईको टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं हैं। विभाग को आय बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती 100 प्रतिशत बिलिंग क्षमता पाने की है। साथ में लाइन लास रोकने की गंभीरता से काम होना चाहिए।

मतांतरण पर सही संदेश

हृदयनारायण दीक्षित

दलितों ने तमाम कष्ट सहे हैं। उनके हिस्से के अवसर मतांतरित ईसाइयों एवं मुस्लिमों को नहीं दिए जा सकते

अवधेश राजपूत

मतांतरण वस्तुतः राष्ट्रांतरण होता है। मतांतरित व्यक्ति अपनी जन्मभूमि, इतिहास और संस्कृति से टूट जाता है। भारत ईसाई, इस्लामी जोर जबरदस्ती, लोभ, भय आधारित मतांतरण का भुक्तभोगी है। मद्रास हाई कोर्ट में एक महिला ने ईसाई होने के बावजूद हिंदू दलित होने का प्रमाण पत्र मांगा था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि केवल नौकरी के लिए मतांतरण संविधान विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए मतांतरण संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय से राष्ट्र प्रसन्न है। राष्ट्रपति के 1950 के आदेश में कहा गया है कि सिर्फ हिंदुओं, बौद्ध, जैन सहित सिक्खों के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सकता है। संविधान में धर्म प्रचार (अनु. 25) की स्वतंत्रता है और किसी भी पंथ या विश्वास को स्वीकार करने की भी। कोर्ट ने बल देते हुए कहा कि मतांतरण सच्चे विश्वास से प्रेरित होते हैं न कि गुप्त उद्देश्यों से। मतांतरित दलित ईसाई-मुस्लिम की आरक्षण से जुड़ी मांग पुरानी है। मतांतरित अनुसूचित जाति को सरकारी प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति का नहीं माना जा सकता। उन्हें ईसाई या मुस्लिम बन जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के व्यापक प्रभाव होंगे।

मतांतरण अंग्रेजी राज के पहले से ही राष्ट्रीय बेचैनी का विषय रहा है। मिशनरी अस्पताल, स्कूल और तमाम सुविधाएं सेवाएं देकर गरीबों का मतांतरण कराते हैं। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और झारखंड आदि कई राज्यों में मतांतरण जारी है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1936 में हरिजन में लिखा था, 'आप पुरस्कार के रूप में चाहते हैं कि आपके मरीज ईसाई बन जाएं।' डा. आंबेडकर ने भी कहा था, 'गांधी जी के तर्क से वह सहमत हैं, लेकिन उन्हें ईसाई पंथ प्रचारकों से दो टूक शब्दों में कह देना चाहिए कि अपना काम रोक दो।' उन्होंने ब्लादिमीर के ईसाई होने और एक साथ भारी भीड़ के मतांतरण का उदाहरण देते हुए कहा, 'इतिहास गवाह है कि धोखाधड़ी के कारण धर्म परिवर्तन हुए हैं।' अफ्रीकी आर्कबिशप डेसमंड टूटू ने कहा था, 'जब मिशनरी अफ्रीका आए तब उनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की। आंखें खोलीं तो पाया कि हमारे पास बाइबल थी और भूमि उनके कब्जे में।' मतांतरित व्यक्ति की देश के प्रति कोई आस्था नहीं होती। उसके आराध्य भी बदल जाते हैं। विश्वविख्यात लेखक वीएस नायपाल ने लिखा है, 'जिसका धर्म परिवर्तन होता है, उसका अपना अतीत नष्ट हो जाता है। नए विश्वास के कारण उसके पूर्वज बदल जाते हैं। उसे कहना पड़ता है कि हमारे पूर्वजों की संस्कृति अस्तित्व में नहीं है और न ही कोई मायने रखती है।'

आजादी के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेसी सरकार भी मतांतरण से परेशान रही। उस दौर में मुख्यमंत्री रहे रविशंकर शुक्ल ने न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। समिति ने 14 जिलों के लगभग 12,000 लोगों के बयान लिए। ईसाई संस्थाओं की भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। नियोगी समिति ने मतांतरण के लक्ष्य को लेकर भारत आए विदेशी तत्वों को देश से बाहर करने की सिफारिश की। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एमएल रेगे के नेतृत्व वाली जांच समिति ने ईसाई मतांतरण को ही दंगों का कारण बताया। वेणुगोपाल आयोग ने यह कृत्य रोकने के लिए नए कानून की सिफारिश की। ओडिशा में सक्रिय ईसाई पंथ प्रचारक ग्राहम स्टैंस और उनके दो बच्चों को जलाकर मारने की जांच करने वाले वाधवा आयोग ने भी ईसाई मतांतरण को चिह्नित किया।

वर्ष 2020 में मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई और चार बड़े ईसाई संगठनों के अनुमति पत्र एवं विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम संबंधी प्रविधान निरस्त कर दिए। अधिनियम के संशोधन में सभी एनजीओ को 20 प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक व्यय न करने के निर्देश हैं। इससे पूर्व एनजीओ विदेशी सहायता का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक खाते में दिखाते थे, मगर इस राशि का उपयोग मतांतरण के लिए होता रहा। विदेशी अनुदान को किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित पर भी रोक लगाई थी। प्रत्येक दृष्टि से प्रशंसनीय इस कानूनी संशोधन का भी विरोध हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने अधिनियम का विरोध किया था। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कहा था।

धर्म प्रचार का अधिकार खतरनाक है। इसका सदुपयोग विरल है और फायदे के लिए दुरुपयोग आसन्न। धर्म उपभोक्ता वस्तु नहीं है। उपभोक्ता वस्तुओं का प्रचार होता है। धर्म साधक के तल पर व्यक्तिगत है और सामूहिक स्तर पर राष्ट्रजीवन की आचार संहिता। ईसाई और इस्लाम सहित सभी पंथ, मत और मजहब धर्म नहीं हैं। वे पंथ/रिलीजन हैं। प्रत्येक पंथ और रिलीजन का कोई न कोई पैगंबर या देवदूत होता है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य धर्म प्रचार के अधिकार के विरुद्ध थे। सभा में तजम्मुल हुसैन ने कहा था, 'मैं आपसे अपने तरीके से मुक्ति के लिए क्यों कहूं? आप भी मुझे ऐसा क्यों कहें? आखिरकार धर्म प्रचार की आवश्यकता क्या है?' लोकनाथ मिश्र ने धर्म प्रचार को गुलामी का दस्तावेज बताया था। केएम मुंशी ने कहा, 'भारतीय ईसाई समुदाय ने इस शब्द के रखने पर जोर दिया। परिणाम कुछ भी हो। हमने जो समझौते किए हैं। हमें उन्हें मानना चाहिए।' भारतीय नेतृत्व ने अंग्रेजों से धर्म प्रचार के अधिकार को संविधान में जोड़ने का समझौता किया था?

मतांतरित अनुसूचित जातियों, दलितों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मतांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का होने के आधार पर आरक्षण देना भारतीय समाज के साथ कदम मिलाकर चलने वाले मूल दलितों की क्षति पहुंचाना है। दलितों ने तमाम कष्ट सहे हैं। वे राष्ट्रजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनके हिस्से के अवसर मतांतरित ईसाइयों एवं मुस्लिमों को नहीं दिए जा सकते। शीर्ष अदालत ने इस विचार को खारिज कर दिया है। मतांतरण के कृत्य में जुटी मिशनरियों को गोवंश, अनुसूचित जातियों को मतांतरण का चारा फेंकने की प्रकृति रोकनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला स्वागतयोग्य है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

संकट में भारतीय ज्ञान परंपरा

एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे भारत के लिए औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति आवश्यक हो गई है

आचार्य रामदेव पी. तिवारी

अपनी जड़ों की ओर लौटने का समय। प्रतीकात्मक

यद्यपि हमने 15 अगस्त, 1947 को तत्कालीन औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, किंतु अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की दासता का दुष्प्रभाव हमारी संस्थाओं, व्यवस्थाओं, राजनीतिक-सामाजिक प्रतीकों एवं जीवनशैली में विद्यमान है। औपनिवेशिक प्रवृत्ति एवं परंपराओं, हमारी शासन व्यवस्था, भाषा, वास्तुकला एवं जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में अब भी मौजूद हैं। तत्कालीन भौगोलिक परतंत्रता अब मानसिक और सांस्कृतिक गुलामी में परिवर्तित हो रही है। वर्तमान परिदृश्य में जब भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, यह आवश्यक हो जाता है कि हम औपनिवेशिक मानसिकता एवं उसके प्रतीकों से मुक्त हों। आज विश्वभर के चिंतक इस बात से सहमत हैं कि गुलामी केवल शारीरिक रूप से किसी देश पर अधिकार जमाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह उस राष्ट्र के जीवन दर्शन एवं मूल्यों को भी प्रभावित करती है। अंग्रेजों ने भारत पर शासन करते हुए सिर्फ भौगोलिक एवं आर्थिक शोषण ही नहीं किया, वरन सामाजिकता, परंपरा, इतिहास और सांस्कृतिक अस्मिता को भी विकृत करने का दुष्प्रयास किया। परिणामस्वरूप ऐसी मानसिकता का विकास हुआ जिसमें भारतीय नागरिक 'स्व' के अस्तित्व को भुलकर पश्चिमी सभ्यतागत विमर्श के अनुगामी बन बैठे।

जैसे कि भारत में आज भी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है। अंग्रेजी के मुकाबले अन्य भारतीय भाषाओं को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। उच्च शिक्षा, न्याय प्रणाली एवं प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। भारतीय भाषाओं का व्यवहार करने वालों को कमतर आंका जाता है एवं अंग्रेजी बोलने वालों को अधिक योग्य माना जाता है। कई माता-पिता इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां एक भी शब्द हिंदी का बोलने नहीं दिया जाता। युवा पीढ़ी न तो अपनी मातृभाषा में लिखने-पढ़ने में सक्षम है और न ही भारतीय साहित्य और ग्रंथों को समझने में। ऐसी स्थिति ने भारतीय ज्ञान परंपरा को संकट में डाल दिया है। अंग्रेजी से हमें परहेज नहीं होना चाहिए, परंतु उसे अपनी मातृभाषा से ज्यादा महत्व देना ठीक वैसे है जैसे अपनी मां के स्थान पर दूसरे की मां को अधिक श्रेष्ठ मानना। आज संपूर्ण जीवनशैली में पश्चिमी बातों का अंधानुकरण करना एक 'स्टेटस सिंबल' स बन गया है। परंपरागत व्यंजनों के प्रति हमारी रुचि कम हो रही है एवं पाश्चात्य व्यंजन हमारी थाली की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज हम जो फादर्स-मदर्स-ब्रदर्स-सिस्टर्स-वैलेंटाइन डे आदि मनाते हैं, यह तो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं, अपितु पाश्चात्य संस्कृति की भौंडी नकल हैं। हमारे लिए तो जीवन का प्रत्येक क्षण इन रिश्तों में आत्मीयता हेतु समर्पित था। हम अपनी प्रकृति-प्रेमी जीवनशैली से विरक्त होकर प्रकृति विरोधी पथ पर अग्रसर हो गए हैं। परिणामतः जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम झेलने को विवश हैं।

संपूर्ण व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित करने वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बजाय भारतीय शिक्षा प्रणाली आज भी मैकाले द्वारा स्थापित ढांचे पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी शासन के लिए 'क्लर्क' तैयार करना था। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज पश्चिमी ज्ञान को श्रेय देती है एवं भारतीय ग्रंथों, विज्ञान और परंपराओं को हाशिये पर धकेल रही है। इस हेतु हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली का नए सिरे से अध्ययन एवं वर्तमान में उनकी उपादेयता पर सघनता से कार्य करना होगा। आज भी भारतीय न्याय प्रणाली एवं प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश माडल पर आधारित है। न्यायिक प्रक्रिया अंग्रेजी में होती है, जो आम जनमानस की समझ से परे है। इस दिशा में तेजी से परिवर्तन की आवश्यकता है। भला हो मोदी सरकार का जिसने पहली बार भारतीय न्याय संहिता लागू की।

अंग्रेजों ने भारतीयों में यह भावना विकसित की कि हम सभ्यता, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में पश्चिम से कमतर हैं। यहां तक कहा गया कि भारतीयों को सच्चे बनाना अंग्रेजों का अतिरिक्त कर्तव्य है। यह मानसिक गुलामी हमारे विकास में बाधा बन रही है। भारतीय परंपराओं, संस्कारों, रीति रिवाजों, कौशल-विकास परंपरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदि को आधुनिकता के नाम पर त्यागा जा रहा है। युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और संस्कृति से अनभिज्ञ होती जा रही है। हम अपने संसाधनों और प्रतिभा का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी वस्तुओं, तकनीक और सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता आत्मनिर्भर भारत के मार्ग में अवरोध है। ऐसे में प्रश्न है कि मानसिक गुलामी से मुक्ति कैसे पाएं जाए? औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने के लिए देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। यह केवल सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं हो सकता, समाज के प्रत्येक वर्ग को मनसा, वाचा, कर्मणा इस महायज्ञ में आहुति डालनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके ही शिक्षा में भारतीय संस्कृति, परंपराओं, ज्ञान भंडार एवं गौरवशाली इतिहास को प्राथमिकता दी जा सकती है। आवश्यकता है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें एवं उन्हें सींचें। अपनी संस्कृति एवं जीवंत परंपरा पर गर्व करें और औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागकर आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, विकसित एवं 'स्व' के तंत्र वाले भारत का निर्माण करें। मानसिक गुलामी से मुक्त होकर ही हम वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जब तक भारतीय समाज इस बीमारी से मुक्त नहीं होगा, हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। और इस लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर 2047 तक प्राप्त कर लेना होगा।

(लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मनसा-वाचा-कर्मणा

दैनिक जीवन में मन, वाणी और कर्म में समरूपता का भाव ही मनसा-वाचा-कर्मणा का स्वरूप है। जो मन में, वही मुख में और वही आचरण में परिलक्षित होने की अनिवार्यता ही इस सूत्र वाक्य का सारांश है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी समय किसी भी विषय पर इन तीनों की तादात्म्यता समबेत बनी रहे। वास्तव में ये तीनों घटक ही मनुष्य की सकारात्मकता और नकारात्मकता से संबंध जोड़ते हैं।

विचार, शब्द और कर्म में एकरूपता से मनुष्य के जीवन में नैतिकता का समावेश होता है। इससे उसकी आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होती है। संसार में जितने भी महामानव हुए, उनमें यही गुण विद्यमान रहा है कि वे अपने शब्दों, विचारों और कार्यों में स्थिर रहे। अपने मन, वाणी और कर्म से हम जिस वस्तु के बारे में सतत सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए सदैव शुभ चिंतन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हम जो भी हैं, जिस कालखंड में हैं, वह हमारे सोच का परिणाम है। ऋषि-मुनियों का तो यहां तक अभिमत रहा है कि केवल हमारा सोच ही ऐसा न हो, वरन हमारे स्वप्न भी सुंदर बनें।

महापुरुष अपने प्रवचनों में मनसा-वाचा-कर्मणा का निरूपण करते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आगे शब्द बन जाते हैं। फिर शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो कर्म बन जाते हैं। आगे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, जो आदत बन जाते हैं। तदुपरांत अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, जो चरित्र बन जाती हैं। अंत में अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, जो अंततः भाग्य बन जाता है। अतः विचार से भाग्य बनने तक की यात्रा के इन सभी पड़ावों को अपने मन-वाणी-कर्म से सुखद और सार्थक बनाए रखना चाहिए। यदि लगन एवं इच्छाशक्ति से लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें तो वह असंभव नहीं रह जाता है।

एसएन दुबे 'स्नेही'

संकट में हैं दुनिया के ग्लेशियर

मुकुल व्यास

एक ताजा अध्ययन से पता चलता है कि इस सदी के अंत तक दुनिया के आधे से ज्यादा ग्लेशियर पिघल सकते हैं

दुनिया के कई ग्लेशियर पिछले हिमयुग के दौरान बने थे। ये ग्लेशियर हजारों सालों से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों में विद्यमान हैं, लेकिन आने वाले समय में इस स्थिति में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक ताजा अध्ययन से पता चलता है कि इस सदी के अंत तक दुनिया के आधे से ज्यादा ग्लेशियर पिघल सकते हैं। स्विट्जरलैंड और ब्रेजिलयन के वैज्ञानिकों ने कार्बन उत्सर्जन के विभिन्न परिदृश्यों के तहत ग्लेशियरों की संभावित क्षति का अनुमान लगाया है। पृथ्वी के सभी ग्लेशियरों की संख्या दो लाख है। अध्ययन से मिले आंकड़े डराने वाले हैं। यदि कार्बन का उत्सर्जन उच्च स्तर पर हुआ तो सभी ग्लेशियरों में से 54 प्रतिशत तक ग्लेशियर पिघल सकते हैं। आल्प्स में यह संख्या 75 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

ग्लेशियर दुनिया के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लेशियरों में होने वाले परिवर्तन सीधे हमारे समाज और प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इससे स्लीबल बार्मिंग का खतरा बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन और भी गंभीर हो जाता है।

भविष्य में ग्लेशियर क्षति का अनुमान लगाने के लिए शोधार्थियों ने ऐतिहासिक ग्लेशियर द्रव्यमान, कार्बन उत्सर्जन और तापमान डाटा का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कम कार्बन उत्सर्जन के तहत 2100 तक ग्लेशियर अपने द्रव्यमान का 25 से 29 प्रतिशत खो सकते हैं। उच्च-उत्सर्जन परिदृश्य के तहत यह आंकड़ा 46 से 54 प्रतिशत के बीच बढ़ सकता है। इस तरह के चिंताजनक राजपाश के बावजूद शोधकर्ताओं ने अनुमानित ग्लेशियर विकास में अनिश्चितताओं को स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि शेष में विशेष रूप से ग्लेशियरों की जांच की गई है, न कि बर्फ की चादरों की। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर पाई जाने वाली बर्फ की चादरों में भूमि की बर्फ का 99 प्रतिशत और पृथ्वी के ताजा पानी का 68 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मौजूद है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

मेलबाक्स

उद्योग जगत को इनसे जोड़ा जा सकता है।

पीयूष शंकर गर्ग, गाजियाबाद

उद्देश्यों में विफल स्थानीय निकाय

'अकर्मण्यता से घिरे स्थानीय निकाय' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. एके वर्मा ने उल्लेख किया है कि स्थानीय स्वशासन इकाइयों को संवैधानिक मान्यता और अधिकार मिले हुए 32 वर्ष बीत गए। मगर ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में विफल रहे हैं। कारण बताया कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सामंती प्रवृत्ति एवं जात-पात की राजनीति के कारण नवाचार के माध्यम से समस्याओं के निराकरण की प्रवृत्ति विकसित नहीं हो सकी है। प्रमंचद के पंच-परमेश्वर वाली पंचायत में पराली जलाने की समस्या नहीं थी। जनसंख्या कम थी तो कचरा भी कम होते थे। अब जनसंख्या बढ़ने का प्रतिफल ही है न कि डिवाइडर पर लोग सो रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ गया। शाहियां सड़कों पर हो रही हैं। आखिर इन्हीं सब समस्याओं के लिए न पंचायत एवं नगरपालिका को संवैधानिक मान्यता मिली थी। स्थानीय समस्याओं को प्रकृति बिल्कुल स्थानीय होती है। जिसका समाधान वही कर सकते हैं जो उस आर्थिक-सामाजिक परिवेश से भली-भांति परिचित होंगे। मगर उसी बुराई से छोटी पंचायतें भी ग्रस्त हैं, जो ठेश की बड़ी पंचायत में मौजूद है, विधायिका में व्याप्त है। लिहाजा इस ढांचे के पुनरीक्षण कराए जाने की जरूरत है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

बढ़ रही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

'ज्ञान के दरवाजे खोलने की पहल' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में डा. ब्रजेश कुमार तिवारी ने 'वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन' योजना के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी है। यह योजना वैश्विक स्तर पर प्रकाशित हो रहे 13 हजार से अधिक जर्नल तक देश भर के छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों तक पहुंच आसान बनाएगी। इसमें दर्ज ज्ञान को प्राप्त कर हमारे युवा देश की वैज्ञानिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित करेंगे। विगत कुछ वर्षों से सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सबको इसे उपलब्ध कराने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का 'स्वयं' पोर्टल इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां आइआइटी जैसे उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रतिष्ठित शिक्षकों के लेक्चर्स और उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रम आनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसने लंबे समय से महसूस की जा रही योग्य शिक्षकों की कमी को दूर करने का काम किया है। इसी तरह देश में डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू की गई है। इसकी मदद से देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे छात्र और शिक्षक अब आसानी से अपनी जरूरत की पुस्तकें पढ़ पा रहे हैं। इन सर्वोपलब्ध संसाधनों के बारे में छात्रों और अध्यापकों को बताने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है। इसके आलावा छात्रों को नई-नई तकनीकों को सिखाने के लिए भी इन बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि छात्र पढ़े हुए विषयों का प्रायोगिक तौर पर अभ्यास कर सकें। जैसे कि

संसद में हंगामा

वर्तमान शीतकालीन सत्र का प्रथम सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में हंगामा पिछले कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन अब तक संसद के सुचारु संचालन के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई। जिसका परिणाम है कि देश के अरबों रुपये हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। देश की भावी पीढ़ी को हंगामा करने का संदेश जा रहा है। देश में सड़क से संसद तक अनुशासन कायम करना सबसे बड़ा मुद्दा है। संसद और विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को मर्यादित आचरण और संसदीय भाषा के प्रयोग करने का कानून बनना चाहिए। जो भी सदस्य अमर्यादित आचरण करे उसको सदन से निकाल देने चाहिए। चेतावनी के बाद भी यदि न माने तो उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। चुनाव आयोग को ऐसे निष्कासित सदस्यों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देश की आम जनता संसद में मर्यादित आचरण चाहती है। हमारे देश के सभी राजनेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए।

कुलदीप मोहन त्रिवेदी, उन्नाव, उप्र

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

आपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****